



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 129]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 17, 2010/वैशाख 27, 1932

No. 129]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 17, 2010/VAISAKHA 27, 1932

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अंतिम जांच परिणाम

नई दिल्ली, 17 मई, 2010

विषय : चीन जन.गण. और इंडोनेशिया के मूल के या वहां से निर्यातित “बांस के फाइबर को छोड़कर विस्कोस स्टेपल फाइबर” के आयातों के बारे में पाटनरोधी जांच—अंतिम जांच परिणाम ।

सं. 14/6/2009-डीजीएडी.—समय-समय पर यथासंशोधित सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमा-शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं का अभिज्ञान, पाटनरोधी शुल्क का निर्धारण एवं वसूली तथा क्षति निर्धारण) नियम (जिसे आगे पाटनरोधी नियम कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए; चीन जन.गण. तथा इंडोनेशिया (जिन्हें आगे संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के या वहां से निर्यातित “बांस के फाइबर को छोड़कर विस्कोस स्टेपल फाइबर” (जिसे आगे संबद्ध वस्तु भी कहा गया है) के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की थी ।

क. मामले की पृष्ठभूमि

2. निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे प्राधिकारी कहा गया है) को उपर्युक्त अधिनियम तथा पाटनरोधी नियमावली नियमों के अंतर्गत घरेलू उद्योग की ओर से एसोसिएशन ऑफ मेन मेड फाइबर इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एएमएफआईआई) से एक लिखित आवेदन प्राप्त हुआ जिसमें चीन जन.गण. तथा इंडोनेशिया के मूल के या वहां से निर्यातित “बांस के फाइबर को छोड़कर विस्कोस स्टेपल फाइबर” के पाटन का आरोप लगाया गया था ।

3. आवेदन की प्रारंभिक जांच से कुछेक कमियों का पता चला जिन्हें आवेदक ने बाद में सुधार दिया था । अतः आवेदन को समुचित ढंग से प्रलेखित माना गया था । जांच की शुरुआत को न्यायोचित ठहराने के लिए आवेदक द्वारा प्रस्तुत पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों के बारे में जांच शुरू करने का निर्णय लिया । प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के उप-नियम 5(5) के अनुसार जांच शुरुआत की कार्यवाही से पूर्व एक आवेदन की प्राप्ति के बारे में भारत स्थित संबद्ध देशों के दूतावासों को सूचित किया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ पाटन तथा इसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को हुई क्षति का दावा किया गया था । प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(1) के अनुसरण में कथित पाटन के अस्तित्व, सीमा तथा प्रभाव का निर्धारण करने एवं पाटनरोधी शुल्क की वह राशि संस्तुत करने, जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगी, संबद्ध वस्तु के आयातों के बारे में पाटनरोधी जांच शुरू करते हुए 19 मार्च, 2009 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की जिसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था ।

संबद्ध वस्तु के आयातों के बारे में पाटनरोधी जांच शुरू करते हुए 19 मार्च, 2009 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की जिसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था।

4. प्राधिकारी ने चीन जन.गण. एवं इंडोनेशिया के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "बांस के फाइबर को छोड़कर विस्कोस स्टेपल फाइबर" जो उपशीर्ष 5504.10.00 के अंतर्गत आता है, के आयातों पर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाने की संस्तुति की थी। प्रारंभिक जांच परिणाम दिनांक 5 अगस्त, 2009 की अधिसूचना सं. 14/6/2009-डी जी ए डी द्वारा अधिसूचित किए गए थे।

ख. प्रक्रिया

5. इस कार्यवाही में निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुपालन किया गया है :-

- i. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(2) के अनुसार संबद्ध देशों के भारत स्थित दूतावासों को जांच की शुरुआत के बारे में सूचित किया गया था।
- ii. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने दिनांक 19 मार्च, 2009 की जांच शुरुआत अधिसूचना की प्रतियां अपने पास उपलब्ध सूचना के अनुसार संबद्ध देशों के भारत स्थित दूतावासों, संबद्ध देशों के ज्ञात निर्यातकों, ज्ञात आयातकों एवं अन्य हितबद्ध पक्षकारों तथा घरेलू उद्योग को प्रेषित की थीं। इस जांच से संबंधित पक्षकारों से निर्धारित समयावधि के भीतर प्रश्नावलियों के उत्तर प्रस्तुत करने तथा अपने विचारों को लिखित रूप से अवगत कराने का अनुरोध किया गया था। निर्यातकों को भेजे गए पत्र एवं प्रश्नावलियों की प्रतियां ज्ञात निर्यातकों/उत्पादकों की सूची के साथ संबद्ध देशों के दूतावासों को भी भिजवाई गई थी और उन्हें संबद्ध देशों के निर्यातकों/उत्पादकों को प्रश्नावलियों के उत्तर निर्धारित अवधि के भीतर प्रस्तुत करने की सलाह देने का अनुरोध किया गया था।
- iii. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार ज्ञात निर्यातकों तथा भारत स्थित संबद्ध देशों के दूतावासों को आवेदन के अगोपनीय रूपांतरण की प्रति उपलब्ध कराई।
- iv. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार संबद्ध देशों के निम्नलिखित ज्ञात निर्यातकों को संगत सूचना मांगने के लिए प्रश्नावलियां भेजी:

क्र.सं.	कंपनी का नाम
	इंडोनेशिया
1.	पी.टी. साउथ पेसिफिक विस्कोस
2.	पी. टी. इंडो भारत रेयॉन चीन जन.गण.
	चीन जन.गण.
3.	हेबाई जिगाओ केमिकल फाइबर कं. लि.
4.	कुन्शान हेंगशेंग केमिकल फाइबर कं.
5.	जिबो हुआलॉग केमिकल फाइबर कं. लि.

6.	हुबाई केमिकल फाइबर ग्रुप लि.,
7.	गाओमी सिल्वर हॉक केमिकल फाइबर कं. लि.
8.	सतेरी (जियांगसी) केमिकल फाइबर कं. लि.
9.	फुलीदा ग्रुप होल्डिंग कं. लि.
10.	मनासी आओयांग टेक्नीकल कं. लि.
11.	यीबिन ग्रेस ग्रुप कंपनी लि.

v. जांच शुरुआत की अधिसूचना के उत्तर में इंडोनेशिया के निम्नलिखित निर्यातकों/उत्पादकों ने उत्तर दिया है:

- मै. पी.टी. इंडो भारत रेयान
- मै. पी.टी. साउथ पेसिफिक विस्कोस

चीन जन.गण. के किसी उत्पादक/ निर्यातक ने इस मामले में कोई उत्तर नहीं दिया है ।

vi. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना मांगते हुए भारत में संबद्ध वस्तु के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को प्रश्नावलियां भेजी गई थीं:

<ul style="list-style-type: none"> • पल्लव टेक्सटाइल्स • चेरन स्पिन टेक्स (आई) लि., • पल्लीपलायम स्पिनर्स, • श्री चेरन सिन.इंडिया लि. • केसर मल्टीयार्न मिल लि. • सुन्दरराजा मिल्स लि., • गिन्नी फिलामेंट्स लि., • पीकेपीएन स्पिनिंग मिल्स (प्रा.) लि., • अडानी एन्टरप्राइजेज लि. • राजापलायम मिल्स लि. • सतलेट इंडस. लि. • पल्लव टेक्सटाइल्स • जेनिथ स्पिनर्स • चेरन स्पिनटेक्स (आई) लि., • पी वी टेक्सटाइल्स, • बिरला टेक्सटाइल्स मिल्स, • एजीटी मिल्स. प्रा.लि. 	<ul style="list-style-type: none"> • आरएसडब्ल्यूएम लि. • रिलायंस कैमोटैक्स इंड लि., • श्री राजस्थान सिन्टैक्स • पल्लीपलायम स्पिनर्स, • राजगुरु स्पिनिंग मिल्स, • दीपक स्पिनर्स लि., • अंकुर उद्योग, चोला स्पि. मिल्स, • पीकेपीएन स्पि. मिल्स (प्रा.) लि. • जीमाटैक्स इंड प्रा. लि. • श्री भगीरथ टेक्सटाइल्स लि., • सुन्दरराजा मिल्स लि., • सूर्यलता स्पि.मिल्स • जिलेन्डर्स अरबुतनाट एंड कं. • विक्टरी स्पि. मिल्स • अरुण कुमार स्पि. मिल्स प्रा., • आरएसडब्ल्यूएम लि. • चेरन स्पि. लि.
---	--

<ul style="list-style-type: none"> ● मोथी स्पिनर्स लि., ● ओरिएन्ट सिन्टैक्स, ● एसएमपी टैक्सटाइल मिल्स (प्रा.) लि. ● केशर मल्टीयार्न मिल लि. ● केशर मल्टीयार्न मिल लि. ● सरमंगल सिंथेटिक्स, ● श्री राजस्थान सिन्टैक्स लि., ● महाराजा सतायम इंड लि. ● एसएमपी टैक्सटाइल मिल्स (प्रा.) लि. ● नाहर स्पिनिंग ● चोला स्पिनिंग मिल्स प्रा.लि., ● पीकेपीएन स्पिनिंग मिल्स (प्रा.) लि. ● श्री कार्तिकेय स्पि. एंड वीव. मिल्स, ● केआरवी स्पि. मिल्स प्रा.लि. ● वेलाताल स्पिनिंग मिल्स प्रा.लि., ● श्री दीनाकर फैब्रिक्स ● आरकाट टैक्सटाइल मिल लि. ● वल्ली स्पिनिंग मिल्स ● बांसवाड़ा सिनटैक्स लि. 	<ul style="list-style-type: none"> ● श्री भरनी स्पि. ● सुतलेट इंडस. लि. ● राजगुरु स्पि. मिल्स ● पल्लव टैक्सटाइल्स ● सिद्धार्थ एक्सपोर्ट प्रा. लि. ● चालीस्वरर स्पि. मिल्स, ● सुन्दरराजा मिल्स लि., \ ● श्री करपागम्बल मिल्स ● श्री हरी प्रसास टैक्सटाइल्स ● वर्धमान टैक्सटाइल्स लि. ● श्री नल्लाथल स्पि. मिल्स ● मोथी स्पि. लि., ● सुपर टैक्स मिल्स इंडिया प्रा.लि., ● जीवीएस स्पि., ● रू स्पि. मिल्स ● सराफ यार्न प्रा.लि. ● संगम स्पि. लि. ● चेनाब टैक्सटाइल्स मिल्स , ● स्पेनटैक्स इंड लि.
---	--

उपर्युक्त अधिसूचना के उत्तर में एवं तत्पश्चात निम्नलिखित आयातकों एवं प्रयोक्ताओं और उनके एसोसिएशनों ने उत्तर दिया है :-

क्र.सं.	कंपनी का नाम
1	इंडियन स्पिनर्स एसो.-मुंबई
2	श्री राजस्थान सिनटैक्स लि.
3	सूर्यलता स्पिनिंग मिल्स लि.
4	स्पेनटैक्स इंड लि., नई दिल्ली
5	पी.वी. टैक्सटाइल्स लि.
6	श्री चेरन सिंथेटिक इंडिया लि.
7	पल्लव टैक्सटाइल लि., तमिलनाडु
8	आरएसडब्ल्यूएम लि.
9	पल्लीपलायम स्पिनर्स प्रा. लि.
10	नार्दन इंडिया टैक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन
11	दि सिंथेटिक एवं रेयॉन वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद

12.	राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स एसो.
13.	गिन्नी फिलामेंट्स लि.
14.	केशर मल्टियार्न मिल्स, कोलकाता
15.	जिमटेक्स इंडस्ट्रीज प्रा.लि., मुंबई

- vii. पिछले तीन वर्षों और जांच अवधि के दौरान किए गए आयातों के आंकड़े उपलब्ध कराने के लिए वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) से अनुरोध किया गया था ।
- viii. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण सार्वजनिक फाइल के रूप में उपलब्ध कराया और उसे हितबद्ध पार्टियों के निरीक्षणार्थ खुला रखा;
- ix. आवेदक द्वारा सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जीएएपी) के आधार पर प्रस्तुत सूचना के अनुसार भारत में संबद्ध वस्तु के उत्पादन की इष्टतम लागत और उसे बनाने तथा बेचने की लागत निकाली गई थी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कमतर पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।
- x. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार प्राधिकारी ने दिनांक 22 दिसंबर, 2009 को आयोजित एक सार्वजनिक सुनवाई में सभी हितबद्ध पक्षकारों को अपने विचार मौखिक रूप से व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया था । जिन पक्षकारों ने सार्वजनिक सुनवाई में अपने विचार व्यक्त किए थे, उनसे मौखिक रूप से व्यक्त विचारों को लिखित निवेदन के रूप में प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया । लिखित निवेदनों/उत्तरों में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर वर्तमान जांच परिणाम में, जहां प्रासंगिक पाया गया, विचार किया गया है ।
- xi. निर्दिष्ट प्राधिकारी के बदल जाने के कारण कुछेक हितबद्ध पक्षकारों ने दूसरी सार्वजनिक सुनवाई के आयोजन का अनुरोध किया था । तथापि, पाटनरोधी नियमावली के सावधानीपूर्वक किए गए अध्ययन के उपरांत प्राधिकारी का विचार था कि इस एकमात्र आधार पर दूसरी सुनवाई का आयोजन किया जाना आवश्यक नहीं है । जिस पक्षकार ने सुनवाई का अनुरोध किया था उसने ऐसा कोई मुद्दा नहीं उठाया है, जिसे प्राधिकारी के समक्ष मौखिक रूप से प्रस्तुत करना आवश्यक हो । इसके अलावा प्राधिकारी ने वर्तमान जांच परिणाम तैयार करते समय हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदनों पर विधिवत विचार किया है ।
- xii. घरेलू उद्योग द्वारा तथा सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत सूचना एवं आंकड़ों का सत्यापन जिस सीमा तक आवश्यक समझा गया, किया गया है ।
- xiii. यह जांच 1 जुलाई, 2008 से 31 दिसंबर, 2008 तक की अवधि (जांच अवधि) के लिए की गई थी । क्षति विश्लेषण के संदर्भ में रुझानों की जांच में वर्ष 2005-06, 2006-07, 2007-08, अप्रैल, 08-जून 08 की अवधि और जांच अवधि शामिल थी ।
- xiv. पाटनरोधी नियमावली के नियम 16 के अनुसार इस मामले में प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन अनिवार्य तथ्यों को ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों के समक्ष प्रकट किया गया था । प्रकटीकरण विवरण के संबंध में प्राप्त टिप्पणियों पर अंतिम जांच परिणाम में विधिवत विचार किया गया है ।

- xv. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की जांच पर्याप्तता एवं गोपनीयता के दावे के संदर्भ में की गई थी । संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने, जहां आवश्यक था, गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया और ऐसी सूचना को गोपनीय मानते हुए उसे अन्य हितबद्ध पक्षकारों के समक्ष प्रकट नहीं किया है । जहां कहीं संभव था, गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों के गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना का पर्याप्त अगोपनीय पाठ प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था ।
- xvi. जहां कहीं किसी हितबद्ध पक्षकार ने सूचना उपलब्ध कराने से मना किया है अथवा वर्तमान जांच की कार्यवाही के दौरान अन्यथा आवश्यक सूचना उपलब्ध नहीं कराई है अथवा जांच में अत्यधिक बाधा डाली है, प्राधिकारी ने अपने जांच परिणाम "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर दर्ज किए हैं ।
- xvii. *** यह चिन्ह इस अधिसूचना में हितबद्ध पार्टियों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना का द्योतक है और प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमानुसार उसे गोपनीय ही माना है ।

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान घरेलू वस्तु

ग.1 आयातकों एवं निर्यातकों द्वारा किए गए निवेदन

6. मै. गिन्नी फिलामेंट ने निम्नानुसार निवेदन किया है :-

- मूल मुद्दा यह है कि वह एक नॉन-वूवन विनिर्माता हैं, जिन्हें विशेष किस्म के विस्कोस स्टेपल फाइबरों की जरूरत होती है और यह कि घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन में उचित तथ्यों को शामिल नहीं किया गया है । यह हाइड्रो एंटेगलमेंट प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए नॉन वूवन किस्म का विनिर्माण करता है । घरेलू उद्योग द्वारा उल्लिखित क्रेता उनकी किस्म की प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल नहीं करते अतः यह कहना गलत है कि समान वस्तु के लिए अनेक कंपनियां घरेलू फाइबर का प्रयोग कर रही हैं । घरेलू उद्योग द्वारा उल्लिखित ग्राहकों में से कोई भी गिन्नी फिलामेंट्स लि. का ग्राहक नहीं है, जैसा कि घरेलू उद्योग ने कहा है । तदनुसार इस मामले में पाटनरोधी शुल्क लगाने से अपने उद्योग को छूट प्रदान करने का अनुरोध करते हैं ।
- घरेलू फाइबर उनके अंतिम उत्पाद हेतु किसी भी प्रकार से उपयुक्त नहीं है । जिस नमूना खेप का परीक्षण किया गया था वह दर्शाती है कि घरेलू उत्पाद अपेक्षानुरूप नहीं है ।
- घरेलू फाइबर के इस्तेमाल से जेट स्ट्रिप्स, काट्रिजें, फिल्टर आदि अवरुद्ध हो जाते हैं, जिससे उत्पादन प्रक्रिया में रुकावटें आती हैं । ग्रेसिम द्वारा विरंजन प्रक्रिया में हाइड्रोजन परॉक्साइड का इस्तेमाल नहीं किया जाता, जिसके कारण विनिर्मित कपड़े में दुर्गन्ध आती है ।
- ग्रेसिम द्वारा डलिंग एजेंट का प्रयोग नहीं किया जाता, अतः राख की मात्रा कम होती है । उनके लिए फाइबर में कमतर ऑयल पिक अप आवश्यक है, जो घरेलू फाइबर में नहीं होता ।

ग.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन

7. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं :-

- यह कहना गलत है कि घरेलू उत्पाद उनके उत्पाद हेतु उपयुक्त नहीं हैं । उनके उत्पाद का इस्तेमाल अनेक कंपनियां कर रही हैं और समान वस्तुओं का उत्पादन कर रही हैं । ऐसे ग्राहकों को की गई बिक्री का ब्यौरा निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है :-

(बक्री मी.ट. में)			
क्र.सं.	कंपनी का नाम	2008-09	2009-10 9 माह
1	गिन्नी फिलमेंट्स लिमिटेड	***	***
2	यू एन आई प्रॉडक्ट्स लिमिटेड	***	***
3	सुप्रीम नॉन वूवन प्रा.लि.	***	***
4	पैसिफिक हरीश इंडस्ट्रीज	***	***
5	यूनिक नॉन वूवन कंपनी	***	***
6	टाटा मिल्स	***	***
7	कॉसमॉस नॉन वूवन मिल्स प्रा.लि.	***	***
8	ठाकर फेल्ड्स प्रा.लि.	***	***
9	जीवन प्रॉडक्ट्स	***	***
10	अल्फा फोम लिमिटेड	***	***
11	रूबी सर्जिकल एंड एलाइड प्रॉडक्ट्स	***	***
12	कुल	***	***

- घरेलू उद्योग ने तर्क दिया है कि वह नियमित आधार पर इन ग्राहकों को बिक्री करता रहा है । गिन्नी फिलमेंट भी उनसे नियमित आधार पर खरीद कर रहा है, अतः कोई कारण नहीं कि गिन्नी फिलमेंट्स आगे खरीद नहीं कर सकता ।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

8 विचाराधीन उत्पाद "बांस के फाइबर को छोड़कर विस्कोस स्टेपल फाइबर (वीएसएफ)" है । सीमाशुल्क टैरिफ के अंतर्गत विस्कोस स्टेपल फाइबर को "पिनाई/धुनाई न किये गए विस्कोस रेयन स्टेपल फाइबर" के रूप में वर्णित है और इसे समान बाजारों में "रेयन फाइबर" के नाम से भी जाना जाता है । विचाराधीन उत्पाद सीमाशुल्क शीर्ष 5504.10.00 के अंतर्गत वर्गीकृत है । सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे पर किसी भी रूप में बाध्यकारी नहीं है ।

9. विस्कोस स्टेपल फाइबर सर्वप्रथम मानव निर्मित फाइबर था और अन्य मानव निर्मित फाइबरों के विपरीत यह सिंथेटिक फाइबर नहीं है । इसका निर्माण वेट स्पिनिंग प्रौद्योगिकी के जरिए किया जाता है और काष्ठ की लुगदी, जो काष्ठ को विभिन्न रासायनिक एवं यांत्रिक प्रक्रियाओं से गुजार कर सतत धारणीय प्राकृतिक संसाधन अर्थात् काष्ठ से निष्कर्षित अनिवार्य सेल्युलोज है, से निर्मित एक री-जेनेरेटेड सेल्युलोज फाइबर है । सेल्युलोसिक आधार के कारण विस्कोस स्टेपल फाइबर के गुणधर्म थर्मोप्लास्टिक, पेट्रोलियम आधारित सिंथेटिक फाइबर जैसे नाइलोन या पालिएस्टर के गुणधर्मों से भिन्न प्राकृतिक सेल्युलोसिक फाइबर के गुणधर्मों से मिलते-जुलते होते हैं । इसके अलावा, इसमें इंजीनियर्ड विनिर्देशन तथा समानता का अंतर्निहित लाभ होता है ।

10. विस्कोस स्टेपल फाइबर ने उत्कृष्ट ड्रैप, सुखद एहसास के साथ रेशम जैसा सौन्दर्यबोध होता है और उसमें बेहतरीन रंग होते हैं । इससे निर्मित फैब्रिक्स आद्रता अवशोषी (सूत से भी अधिक), हवादार, पहनने में आरामदायक होते हैं और इन्हें आसानी से विभिन्न रंगों में रंगा जा सकता है । इनमें सीधे खिंचाव नहीं आता है और ये पिलरोधी होते हैं ।

11. वीएसएफ की मुख्य क्षमता उसकी लोचशीलता और समस्त अन्य वस्त्र फाइबरों के साथ आसानी से मिश्रण क्षमता है जिससे सौन्दर्य, कोमलता, अवशोषकता आती है जिससे इस प्रकार के मिश्रणों के कारण निर्मित फैब्रिक आरामदायक हो जाते हैं । बांस के फाइबर, जो एक प्रकार का विस्कोस स्टेपल फाइबर है, को इस जांच के दायरे से बाहर रखा गया है । जांच शुरुआत की अधिसूचना में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने हितबद्ध पार्टियों से विशिष्ट तौर पर यह अनुरोध किया था कि वे बांस के फाइबर को छोड़ने के बारे में अपने अनुरोध करें । किसी भी हितबद्ध पार्टी ने इस संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया था ।

12. समान वस्तु के संबंध में पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(घ) में निम्नानुसार उपबंध है :

"समान वस्तु" का अर्थ एक ऐसी वस्तु से है जो भारत में पाटन के लिए जांच के अधीन वस्तु के समान हो या प्रत्येक दृष्टि से उसके जैसी हो अथवा ऐसी वस्तु के अभाव में कोई अन्य ऐसी वस्तु जो यद्यपि प्रत्येक दृष्टि से समान न हो तब भी उसमें जांचाधीन वस्तु से अत्यधिक मिलती-जुलती विशेषताएं हो

13. आवेदक ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से निर्यातित संबद्ध वस्तु में कोई ज्ञात अंतर नहीं है । घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तुएं भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, कार्य एवं उपयोग, उत्पाद विनिर्देशन, वितरण एवं विपणन तथा वस्तु के टैरिफ वर्गीकरण जैसी विशेषताओं के संबंध में तुलनीय है ।

14 प्राधिकारी नोट करते हैं कि मैसर्स गिन्नी फिलामेंट्स ने अपना निवेदन प्रस्तुत करते समय अपने दावे के साथ तत्संबंधी कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है । जबकि घरेलू उद्योग ने विशिष्ट किस्म के फाइबर की (क) गिन्नी फिलामेंट (ख) भारत के अन्य उपभोक्ताओं जो समान वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं, (ग) अनेक वैश्विक ग्राहकों को की गई बिक्री का प्रमाण प्रस्तुत किया है । घरेलू उद्योग ने प्रमाण प्रस्तुत करते हुए यह भी दर्शाया है कि गिन्नी फिलामेंट दरअसल घरेलू उद्योग से और अधिक सामग्री की खरीद के संबंध में बातचीत कर रहा है । यह भी सिद्ध नहीं किया गया है कि ग्रेसिम इंडस्ट्रीज द्वारा इस किस्म के फाइबर का उत्पादन नहीं किया जाता अथवा यह कि उनके पास इस किस्म के फाइबर का उत्पादन करने के लिए उत्पादन सुविधाओं अथवा क्षमताओं का अभाव है । प्राधिकारी के पास रिकार्ड में उपलब्ध सूचना से यह पता नहीं चलता है कि घरेलू समान वस्तु तथा आयातित संबद्ध वस्तु में कोई खास अंतर है । इस प्रकार घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ पाटनरोधी नियमावली के अनुसार संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तु के समान वस्तु माना जा रहा है ।

ग. घरेलू उद्योग का क्षेत्र

घ.1 घरेलू उद्योग के विचार

15. घरेलू उद्योग के दावे के संबंध में आवेदक द्वारा किया गया निवेदन निम्नानुसार है :-

(i) मैसर्स ग्रेसिम इंडस्ट्रीज भारत में विचाराधीन उत्पाद की एकमात्र उत्पादक है । अतः आवेदक द्वारा किया गया उत्पादन भारतीय उत्पादन का प्रमुख अनुपात बनता है; आवेदन का स्पष्ट रूप से समर्थन करने वाले घरेलू उत्पादकों का योगदान घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित समान उत्पाद के कुल उत्पादन में 50% से अधिक है; और यह आवेदन घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उसकी ओर से प्रस्तुत किया गया है ।

(ii) अतः यह आवेदन पाटनरोधी नियमावली के अंतर्गत आधार की अपेक्षा को संतुष्ट कर रहा है। इसके अलावा आवेदक पाटनरोधी नियमावली के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग है।

(iii) आवेदक की चीन जन.गण. और इंडोनेशिया में संबद्ध कंपनियां हैं जो इस उत्पाद का उत्पादन व बिक्री करती हैं अर्थात् बिरला जिगवाई फाइबर्स कंपनी लिमिटेड, चीन तथा पी टी इंडो भारत रेयान, इंडोनेशिया। इन सत्ताओं के संबंध का ब्यौरा निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:-

क्र.सं.	सत्ता का नाम	समान निदेशक
1	ग्रेसिम इंडस्ट्रीज लि.	*** *** ***
2	बिरला जिगवाई फाइबर्स कंपनी लिमिटेड, चीन जन.गण.	***
3	पी टी इंडो भारत रेयान, इंडोनेशिया	*** *** ***

- (iv) चूंकि आवेदक ने स्वयं यह कहा है कि ये सत्ताएं एक दूसरे से संबंधित हैं अतः जिस आधार पर ये कंपनियां संबंधित हैं, अप्रासंगिक हो जाता है। संबंध को स्थापित करने वाली सूचना उसी स्थिति में प्रासंगिक होती है जब कोई पक्षकार ऐसे किसी संबंध के अस्तित्व का प्रतिवाद करता है।
- (v) संबद्ध उत्पादक अपने अधिकांश उत्पादों की बिक्री संबंधित घरेलू बाजारों में कर रहे हैं अथवा अन्य देशों को निर्यात कर रहे हैं। सामान्यतः भारत को कोई निर्यात नहीं किया जा रहा है।
- (vi) चीन की संबद्ध कंपनी ने उत्पाद का निर्यात भारत को नहीं किया है, जबकि इंडोनेशियाई कंपनी ने अल्प मात्रा का निर्यात भारत को किया है, जो आयातों के 3% से भी कम है और भारतीय उत्पादन के संदर्भ में नगण्य है। ये निर्यात इसलिए किए गए, क्योंकि आवेदक के कुछेक ग्राहकों, शुल्क छूट स्कीमों के अंतर्गत आयातित सामग्री की आवश्यकता थी। चूंकि इन आयातों की मात्रा बहुत कम है अतः प्राधिकारी का यह विचार सही है कि आवेदक को नियमावली के अंतर्गत अपात्र नहीं माना जाना चाहिए।
- (vii) प्राधिकारी का यह अभिमत सही है कि आवेदक ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) और 5(3) की अपेक्षाओं को संतुष्ट किया है, अतः मेसर्स ग्रेसिम इंडस्ट्रीज लि. को पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर "घरेलू उद्योग" माना जा रहा है।
- (viii) वर्तमान मामले में विचारार्थ एवं निर्धारणार्थ एक मुद्दा यह है कि ऐसी स्थिति में जब उत्पादक निर्यातक देशों में से एक देश के निर्यातक से संबंधित है, तो क्या उस उत्पादक को पात्र घरेलू उद्योग समझा जाए। अन्य शब्दों में क्या नियम 2(ख) के अंतर्गत निर्दिष्ट प्राधिकारी को विवेकाधिकार है और यदि हां तो उस विवेकाधिकार को किस प्रकार लागू किया जाना अपेक्षित है। पाटनरोधी नियमावली में वर्ष 1999 में संशोधन किया गया था, जिसके संशोधनों में से एक संशोधन घरेलू उद्योग की परिभाषा से संबंधित था। इस संशोधन से पूर्व नियम 2(ख) निम्नानुसार था :-

2(ख) "घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा उन उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है, परंतु जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं या वे स्वयं उसके आयातक होते हैं तो ऐसे मामले में ऐसे उत्पादकों को घरेलू उद्योग का भाग नहीं माना जाएगा।

(ix) संशोधन के पश्चात नियम निम्नानुसार है :-

2(ख) "घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा उन उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है, परंतु जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं या वे स्वयं उसके आयातक होते हैं तो ऐसे मामले में ऐसे उत्पादकों को घरेलू उद्योग का भाग माना जा सकता है ।

(x) यह कि इस नियम में संशोधन निर्दिष्ट प्राधिकारी को यह विवेकाधिकार प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया था कि वह गुण दोषों के आधार पर यह निर्णय दे सकें कि क्या एक कंपनी जो विचाराधीन उत्पाद का आयात कर रही है अथवा जो किसी निर्यातक अथवा आयातक से संबद्ध है तो क्या उसे घरेलू उद्योग के निर्धारण में शामिल किया जाना चाहिए अथवा बाहर रखा जाना चाहिए । नियम 2(ख) में संशोधन निर्दिष्ट प्राधिकारी को विवेकाधिकार प्रदान करने के एकमात्र उद्देश्य से किया गया है कि वह निर्णय कर सकें कि क्या जिस कंपनी ने स्वयं कथित पाटित उत्पाद का आयात किया हो अथवा जो संबद्ध वस्तु के निर्यातक अथवा आयातक से संबंधित हो, उसे घरेलू उद्योग में शामिल किया जाए अथवा बाहर रखा जाए । प्रस्तुत मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने एक समान तरीके से ऐसे विवेकाधिकार का प्रयोग किया है ।

(xi) संबद्धता से संबंधित तथ्य प्राधिकारी की पूर्ण जानकारी में है । इस संबंध में तथ्यात्मक सूचना सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है । इसके होते हुए भी हितबद्ध पक्षकार यह सिद्ध करने में समर्थ नहीं रहे कि संबंधों का स्वरूप वर्तमान जांच को किस प्रकार दूषित करता है ।

(xii) अपने तर्कों के समर्थन में आवेदक ने निम्नलिखित का हवाला दिया है :-

- डंपिंग एंड सब्सिडीज - द लॉ एंड प्रोसीजर्स गवर्निंग द इम्पोजीशन ऑफ एंटी डंपिंग एंड काउंटरवेलिंग ड्यूटीज इन द यूरोपीयन कम्युनिटी- लेखक मेसर्स क्लाइव स्टैनबुक एवं फिलिप बेन्टले, कुमार लॉ इंटरनेशनल, तीसरा संस्करण
- एक हैंडबुक ऑन एंटी डंपिंग इन्वेस्टीगेशंस - लेखक जुडिथ झेको, जॉन ह्यूमन एवं जार्ज मीरांडा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, पृष्ठ सं. 234
- परिशिष्ट - एफ, एंटी डंपिंग एंड काउंटरवेलिंग ड्यूटी हैंडबुक - प्रकाशन 3482, 9 वां संस्करण, यूनाइटेड स्टेट्स इन्टरनेशनल ट्रेड कमीशन पृष्ठ परिशिष्ट एफ-33

(xiii) संबंधित निर्यातक से स्वयं आवेदक द्वारा किए गए निर्यातों के संबंध में जांच प्राधिकारियों के विभिन्न निर्णयों का हवाला आवेदक ने दिया है, जैसे :

क. दिनांक 3 मार्च, 1997 का परिषद विनियमन (ईसी) सं. 423/97, जिसमें थाईलैंड, फिलीपींस एवं मैक्सिको के मूल के गैस फ्यूएल्ड, नॉन रिफिलेबल पॉकेट फ्लैट लाइटर्स के आतों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाते हुए विनियमन (ई ई सी) सं. 3433/91 में संशोधन । ऑफिशियल जर्नल एल 065, 06/03/1997 पृ. 0001-0016

ख. दिनांक 27 सितंबर, 1995 का आयोग विनियमन (ईसी) सं. 2318/95 जिसमें चीन जनवादी गणराज्य के मूल के लोहे अथवा इस्पात के कतिपय ट्यूब अथवा पाइप फिटिंग्स पर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था

और स्लोवाक गणराज्य और ताइवान के मूल की उन फिटिंग्स के आयातों के संबंध में पाटनरोधी कार्यवाही को समाप्त कर दिया गया । ऑफिशियल जर्नल एल-234, 03/10/1995 पृ. 0004-0015

- ग. 16 अगस्त, 1995 का परिषद विनियमन (ई सी) सं. 2022/95 जिसमें रूस के मूल के अमोनियम नाइट्रेट के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया गया । ऑफिशियल जर्नल एल 198, 23/08/1995 पृ. 0001-0014
- घ. दिनांक 10 अप्रैल, 1995 का आयोग विनियमन (ईसी) सं. 823/95, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल के डाई सोडियम कार्बोनेट के आयातों पर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाया गया । ऑफिशियल जर्नल एल 083, 13/04/1995 पृ. 0008-0018
- ङ. दिनांक 15 अक्टूबर, 1997 का परिषद विनियमन (ई सी) सं. 2025/97 जिसमें जापान के मूल के कंप्यूनिटी ऑफ एडवर्टाइजिंग मैचेज के भीतर आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया गया और लगाए गए अनंतिम शुल्क का निश्चयात्मक संग्रहण । ऑफिशियल जर्नल एल 284, 16/10/1997 पृ. 0057-0067
- च. दिनांक 27 अगस्त, 1998 का आयोग विनियमन (ई सी) सं. 1845/98, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका के तथा थाईलैंड के मूल के कतिपय बड़े इलेक्ट्रोलिटिक-एल्युमिनियम संधारियों के आयातों पर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाया गया ।
- छ. इंडोनेशिया, द. कोरिया, थाइलैण्ड तथा ताइवान से नायलान टायर कॉर्ड फैब्रिक (एन टी सी एफ) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच निर्दिष्ट प्राधिकारी के अंतिम जांच परिणाम
- ज. चीन जन.गण. तथा स्वीडन के मूल के अथवा वहां से निर्यातित पेंटाएरिथ्रिटॉल के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच
- झ. आस्ट्रेलिया, चीन जन.गण., ईरान, मलेशिया, रूस तथा थाइलैण्ड के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "रबड़ अनुप्रयोगों में प्रयुक्त कार्बन ब्लैक" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच के मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी के अंतिम जांच परिणाम

(xiv) असंबंधित निर्यातक ने स्वयं आवेदक द्वारा किए गए आयातों के संबंध में जांच प्राधिकारियों के विभिन्न निर्णयों का भी हवाला दिया गया है, जैसे:

क. आयोग का निर्णय सं. 307/2000/ईसीएससी दिनांक 10 फरवरी, 2000, जिसमें चीन जन.गण., भारत तथा रोमानिया के मूल के नॉन एलॉय स्टील के कतिपय हॉट रोल्ड फ्लैट उत्पादों के आयातों पर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाया गया । ऑफिशियल जर्नल एल 036, 11/02/2000 पृ. 0004-0019

(ख) आयोग विनियमन (ईसी) सं. 1497/2001 दिनांक 20 जुलाई, 2001, जिसमें बेलारूस, बुल्गारिया, क्रोएशिया, एस्टोनिया, लीबिया, लिथुआनिया, रोमानिया और यूक्रेन के मूल के यूरिया के आयातों पर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाया गया और बुल्गारिया के निर्यातक उत्पादक का अभिवचन स्वीकार किया गया एवं मिस्र एवं पोलैण्ड के मूल के यूरिया के आयातों से संबंधित कार्यवाही समाप्त की गई । ऑफिशियल जर्नल एल 197, 21/07/2001 पृ. 0004-0027

(ग) आयोग विनियमन (ईसी) सं. 1418/88 दिनांक 17 मई, 1988, जिसमें जापान के मूल के सीरियल इम्पेक्ट डॉट-मॉट्रिक्स प्रिंटरों के आयातों पर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाया गया । ऑफिशियल जर्नल एल 130, 26/05/1988 पृ.सं. 0012-0033

(घ) आयोग विनियमन (ई सी) सं. 165/97 दिनांक 28 जनवरी, 1997, जिसमें चीन जनवादी गणराज्य एवं इंडोनेशिया के मूल के टेक्सटाइल अपर युक्त कतिपय फुटवियर के आयातों पर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाया गया । ऑफिशियल जर्नल एल 029, 31/01/1997 पृ. 0003-0018

(ङ) आयोग विनियमन (ईसी) सं. 1069/97 दिनांक 12 जून, 1997, जिसमें मिस्र, भारत तथा पाकिस्तान के मूल के सूती बिछावनों के आयातों पर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाया गया । ऑफिशियल जर्नल एल-156 पृ. 13/06/1997 पृ. 0011-0033

(च.) आयोग विनियमन (ईसी) सं. 1023/97 दिनांक 6 जून, 1997, जिसमें पोलैण्ड के मूल के काष्ठ के चपटे पैलेटों के कतिपय आयातों पर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाया गया और इन आयातों के संबंध में कतिपय निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत अभिवचन स्वीकार किया गया । ऑफिशियल जर्नल एल 150 07/06/1997 पृ. 0004-0017

(छ) आयोग विनियमन (ई सी) सं. 255/2001 दिनांक 7 फरवरी, 2001, जिसमें चीन जन.गण. के मूल के इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पेक्स फ्लोरेसेंट लैम्पों (सी एफ एल , आई) के आयातों पर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाया गया । ऑफिशियल जर्नल एल 038, 08/02/2001 पृ. 0008-0021

(ज) आयोग विनियमन (ई सी) सं. 1833/98 दिनांक 25 अगस्त, 1998, जिसमें ताइवान के मूल की साइकिलों के आयातों पर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाया गया है । ऑफिशियल जर्नल एल 238, 26/08/1998 पृ. 0010-0026

(झ) चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित मेट्रोनिडाजोल से संबंधित पाटनरोधी जांच (निर्णायक समीक्षा) संबंधी मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी के अंतिम जांच परिणाम ।

(अ) आस्ट्रिया, चेक गणराज्य, रूस, रोमानिया तथा यूक्रेन से सीमलेस ट्यूबों के आयातों की पाटनरोधी जांच के मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी के अंतिम जांच परिणाम ।

(xv) संबद्ध देश को छोड़कर अन्य देश से आवेदक द्वारा स्वयं किए गए आयातों के संबंध में अन्य जांच प्राधिकारियों के निर्णय का हवाला भी आवेदक द्वारा दिया गया है :

- परिषद विनियमन (ईसी) सं. 769/2002 दिनांक 7 मई, 2002, जिसमें चीन जन.गण. के मूल के कुघारीन के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया गया है । ऑफिशियल जर्नल एल 123, 09/05/2002 पृ. 0001-0009

(xvi) संबद्ध कंपनी द्वारा संबंधित निर्यातक से किए गए आयातों के संबंध में जांच प्राधिकारियों के निर्णय का आवेदक द्वारा दिया गया हवाला निम्नानुसार है :-

- आयोग विनियमन (ईसी) सं. 362/1999 दिनांक 18 फरवरी, 1999, जिसमें चीन, भारत, मैक्सिको, द.अफ्रीका और यूक्रेन के मूल की इस्पात से बनी रस्सियों एवं केबलों के आयातों पर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाया गया है और हंगरी तथा पोलैण्ड स्थिति कतिपय निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत अभिवचन स्वीकार किए गए । ऑफिशियल जर्नल एल 045 19/02/1999 पृ. 0008-0025

(xvii) भारत स्थित संबद्ध कंपनी द्वारा असंबंधित निर्यातक से किए गए आयातों के संबंध में जांच प्राधिकारियों के निर्णय का आवेदक द्वारा दिया गया हवाला निम्नानुसार है:-

- परिषद विनियमन (ईसी) सं. 2320/97 दिनांक 17 नवंबर, 1997 जिसमें हंगरी, पोलैण्ड, रूस, चेक गणराज्य, रोमानिया तथा स्लोवाक गणराज्य के मूल के इस्पात अथवा नॉन एलॉय इस्पात से निर्मित कतिपय सीमलेस पाइपों एवं ट्यूबों के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया गया, विनियम (ईईसी) सं. 1189/3 को वापस लिया गया और क्रोएशिया गणराज्य के मूल के ऐसे आयातों से संबंधित कार्यवाही को समाप्त किया गया । ऑफिशियल जर्नल एल एल 322, 25/11/1997 पृ. 0001-0024

(xviii) जांच अवधि के दौरान निर्यात करने वाले निर्यातक से संबंध के बारे में जांच प्राधिकारियों के विभिन्न निर्णयों का आवेदक द्वारा दिया गया हवाला निम्नानुसार है:-

- आयोग विनियमन (ईसी) सं. 1742/2000 दिनांक 4 अगस्त, 2000 जिसमें भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया, कोरिया गण. ताइवान एवं थाईलैंड के मूल के कतिपय पॉलीएथिलीन टैरेफ्थेलेट (पीईटी) के आयातों पर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाया गया ।
- आयोग विनियमन (ईसी) सं. 173/2000 दिनांक 24 जनवरी, 2000 जिसमें जापान, कोरिया गण. तथा ताइवान के मूल के कतिपय बड़े

एल्युमिनियम इलेक्ट्रोलिटिक संधारित्रों के आयातों से संबंधित पाटनरोधी कार्यवाही को समाप्त किया गया ।

- आयोग विनियमन (ई सी) सं. 1472/2000 दिनांक 6 जुलाई, 2000, जिसमें भारत तथा कोरिया गण. के मूल के पॉलिएस्टर स्टेपल फाइबर के आयातों पर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाया गया । ऑफिशियल जर्नल एल 166, 06/07/2000 प. 0001-0013

(xix) उन मामलों, जिनमें घरेलू उद्योग निर्यातकों से संबद्ध है परंतु जांच अवधि के दौरान कोई निर्यात नहीं किया गया है, के संबंध में जांच प्राधिकारियों के विभिन्न निर्णयों का आवेदक द्वारा दिया गया हवाला निम्नानुसार है :-

- परिषद विनियमन (ई सी) सं. 771/98 दिनांक 7 अप्रैल, 1998, जिसमें चीन जन.गण. के मूल के टंगस्टन कारबाइड एवं फ्यूज्ड टंगस्टन कारबाइड के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया गया । ऑफिशियल जर्नल एल III, 09/04/1998 पृ. 0001-0009
- परिषद विनियमन (ई ई सी) सं. 535/87 दिनांक 23 फरवरी, 1987, जिसमें जापान के मूल के प्लेन पेपर फोटोकॉपियर के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया गया । ऑफिशियल जर्नल एल 054, 24/02/1987 पृ. 0012-0035

(xx) ऐसे मामलों, जिनमें उत्पादकों में से एक उत्पादक निर्याताकें में से एक निर्यातक से संबंधित है, का आवेदक द्वारा दिया गया हवाला निम्नानुसार है :-

- थाईलैंड के मूल के गैस-फ्यूएल्ड, नॉन रिफिलबल पॉकेट फ्लिंट लाइटर ।
- चीन जन.गण., क्रोएशिया तथा थाईलैंड के मूल की लौह एवं इस्पात से निर्मित कतिपय ट्यूब्स तथा पाइप फिटिंग्स ।
- भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया तथा कोरिया गण. से पॉलीएथिलीन टेरैफ्थेलेट (पी ई टी) फिल्म ।
- आस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एवं थाईलैंड से पालीस्टर के सिंथेटिक स्टेपल फाइबर ।

घ.2 आयातकों, उपभोक्ताओं, निर्यातकों तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

16. घरेलू उद्योग के "आधार" के संबंध में भारतीय स्पिनर एसोसिएशन, राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन तथा पी टी साउथ पैसिफिक विस्कोस इंडोनेशिया द्वारा निम्नलिखित निवेदन किए गए हैं :-

- इस मामले में जांच की शुरुआत न्यायाधिकार के बिना है, क्योंकि संबद्ध देशों में आवेदक की संबंधित कंपनियां हैं । इसके अलावा चूंकि आवेदक के संपूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी पी टी इंडो भारत रेयान, इंडोनेशिया पाटन करती पाई गई हैं, अतः नियमावली के अंतर्गत एवं इस विषय के न्याय क्षेत्र के अंतर्गत आवेदक को वर्तमान आवेदन दायर करने की अर्हता नहीं है । ऐसी परिस्थिति में एकमात्र घरेलू उत्पादक को हुई क्षति स्व-आरोपित क्षति है

जिसका संरक्षण पाटनरोधी शुल्क के माध्यम से नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा भारतीय उत्पादक तथा इंडोनेशिया स्थित इसकी सहायक कंपनी ने सांठगांठ करके यह सुनिश्चित किया है कि अन्य प्रतिस्पर्धी पहले अपनी कीमतें घटाने पर विवश हो जाएं और फिर भारत स्थित शाखा भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा को अवरुद्ध करने के एकमात्र उद्देश्य से पाटनरोधी जांच का अनुरोध करें। यह निवेदन किया जाता है कि भारत में एकमात्र एकाधिकार वाले उत्पादक को पाटनरोधी जांच प्रक्रिया का इतना खुला दुरुपयोग करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

- यह तथ्य कि आवेदक से संबद्ध सत्ता ने अलग-अलग पाटन मार्जिन के निर्धारण का अनुरोध किया है, नियम 2(ख) को लागू करने के उद्देश्य एवं प्रयोजन के विरुद्ध है, जिसमें यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी उचित समझें तो ऐसे उत्पादकों को बाहर रखा जा सकता है जो निर्यातकों से संबद्ध हैं। घरेलू उद्योग के पक्ष में विवेकाधिकार का प्रयोग करना नियम 2(ख) को लागू करने के उद्देश्य एवं प्रयोजन के विपरीत होगा।
- संबद्ध पक्षकार सौदे का पूरा मुद्दा "एकल आर्थिक उद्यम" के सिद्धांत पर आधारित है। यू एस हॉट रोल्ड स्टील के मामले में पैराग्राफ 141-158 के संदर्भ डब्ल्यू टी/डी एस - 184/एबी/आर में अपीलीय निकाय ने अभिमत व्यक्त किया है कि "निगमित कानून एवं कार्यनीति तथा राजकोषीय कानून से संबंधित अनेक कारण हैं, जिनकी परिणति संसाधनों को इस प्रकार से एकल आर्थिक उद्यम में आवंटित करने में होती है"।
- ई सी न्यायाधिकार एवं अकादमिक साहित्य के अंतर्गत प्राधिकारियों द्वारा घरेलू उत्पादक को "घरेलू उद्योग" के दायरे से बाहर रख दिया जाता है। यदि यह पाया जाता है कि :-
 - (i) संबद्ध निर्यातक पाटन कार्यवाहियों में शामिल था, अथवा
 - (ii) बाजार में कीमतें गिराने में संबद्ध निर्यातक संलिप्त था अथवा उसमें उसका योगदान था।
- ई सी न्यायशास्त्र के अनुसार संबद्ध उत्पादकों, जो उपर्युक्त दो शर्तों में से किसी एक को पूरा करते हैं, को घरेलू उद्योग की परिभाषा से बाहर रखा जाता है। तथापि, प्रस्तुत मामले में दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं क्योंकि इंडोनेशिया के संबद्ध निर्यातक की पाटन मार्जिन इंडोनेशिया के अन्य सहयोगी निर्यातक की तुलना में अत्यधिक है और विस्तृत विश्लेषण से ज्ञात होगा कि कीमतें गिराने में स्वयं निर्यातक का ही योगदान था। उपर्युक्त को ध्यान में रखकर भी आवेदक को घरेलू उद्योग के दायरे से बाहर न रखे जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता।
- विवेकाधिकार के प्रयोग हेतु आयातों की मात्रा निर्णायक कारक नहीं हो सकती। इस संबंध में नियम 2(ख) में कोई मानदंड नहीं है।
- आवेदन प्रपत्र में आयात की मात्रा के बारे में नहीं पूछा गया है। इसमें केवल संबंध के बारे में पूछा गया है।
- आवेदक द्वारा संदर्भित विभिन्न मामले एसी स्थितियों से संबंधित हैं, जिनमें संबद्ध उत्पाद का आयात स्वयं आवेदक न किया था; वर्तमान मामले में स्थिति यह नहीं है।

घ. प्राधिकारी द्वारा जांच

17. इस जांच की शुरुआत के समय पाटनरोधी नियमावली का नियम 2(ख) निम्नानुसार था :-

2(ख) "घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा उन उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है, परंतु जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं या वे स्वयं उसके आयातक होते हैं तो ऐसे मामले में ऐसे उत्पादकों को घरेलू उद्योग का भाग माना जा सकता है।

17.1 तथापि, जांच शुरूआत के बाद इस नियम को निम्नानुसार संशोधित किया गया है :

(ख) "घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा उन उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है, परंतु जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं या वे स्वयं उसके आयातक होते हैं तो ऐसे मामले में केवल शेष बचे उत्पादकों को घरेलू उद्योग का भाग माना जाएगा।

17.2 इस प्रकार, पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) में यह व्यवस्था है कि ऐसे घरेलू उत्पादक जो निर्यातकों या आयातकों से संबंधित हों या जो स्वयं कथित पाटित वस्तु के आयातक हों, को कतिपय स्थिति में घरेलू उद्योग का निर्धारण करते समय शामिल नहीं किया जाए।

नियम 2(ख) में माना जाए शब्द का प्रयोग दो प्रकार के जांचाधीन उत्पादकों अर्थात् संबंधित उत्पादक और पाटित उत्पाद का आयात करने वाले उत्पादकों के संदर्भ में है जिन्हें स्वतः ही घरेलू उद्योग का हिस्सा मानने से इंकार नहीं किया जाएगा बजाए इसके जांचकर्ता प्राधिकारियों की यह संगत प्रक्रिया रही है कि ऐसे उत्पादकों को शामिल नहीं किए जाने का निर्णय सभी विधिक और आर्थिक पहलुओं पर विचार करते हुए तर्कसंगत और समतुल्य आधारों के अनुसार मामला दर मामला आधार पर किया जाना चाहिए।

17.3 किसी घरेलू उत्पादक को घरेलू उद्योग के दायरे और उसके कार्य क्षेत्र से बाहर रखने या उसमें शामिल करने का प्रश्न दो पहलुओं की दृष्टि से व्यवहारिक महत्व का है। सर्वप्रथम यह प्रश्न यह उठता है कि क्या वे पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के तात्पर्य के अनुसार घरेलू उद्योग का वस्तुतः हिस्सा हैं अथवा नहीं। इससे आवेदन की स्थिति भी प्रभावित हो सकती है अर्थात् उनका (वह घरेलू उत्पादक जिन्होंने आवेदन दायर किया है अथवा उसका समर्थन किया है) उत्पादन पाटनरोधी नियमावली के अंतर्गत यथानिर्धारित प्रतिनिधित्व के आवश्यक स्तर तक पहुंचता है अथवा नहीं; क्योंकि उन घरेलू उत्पादकों, जिन्हें आयातकों अथवा निर्यातकों के साथ उनके संबंध के कारण या उनके अपने पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की परिभाषा से बाहर रखा गया है, के उत्पादन पर कुल घरेलू उत्पादन की गणना करते समय विचार नहीं किया जाएगा और निर्धारण के समय यदि आवेदक और उसके समर्थक घरेलू उत्पादक ऐसे उत्पादन के प्रमुख हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं।

17.4 प्राधिकारी नोट करते हैं कि नियम 2 (ख) को दो बार संशोधित किया गया है। नियमों के अंतर्निविष्ट नियम 2 को 1-1-1995 के संशोधन के माध्यम से लाया गया था और इसमें ऐसी स्थिति में निर्दिष्ट प्राधिकारी के लिए स्व-विवेक का कोई प्रावधान नहीं था, जहां एक या उससे अधिक घरेलू उत्पादक ने विचाराधीन उत्पाद का आयात किया हो अथवा विचाराधीन उत्पाद के आयातक अथवा निर्यातक से संबंधित हों। तथापि, डब्ल्यू टी ओ के पाटनरोधी करार और अन्य जांचकर्ता प्राधिकारियों की नियमावली में ऐसी स्थिति में जांचकर्ता प्राधिकारियों के स्वविवेक को विहित किया गया है, जिन्हें मामला दर मामला आधार पर लागू किया जाता है। इस प्रकार ऐसी स्थिति में निर्दिष्ट प्राधिकारी को स्व-विवेक का अधिकार प्रदान करने के लिए नियम 2(ख) को संशोधित करना उचित समझा गया था, जिसका प्रयोग मामला दर मामला आधार पर किया जा सकता है। प्राधिकारी का विचार है कि यह स्व-विवेक निम्नलिखित स्थितियों की पूर्ति के लिए है, जिनमें:

(क) कुछ घरेलू उत्पादक शायद केवल इसलिए आवेदन का समर्थन करना नहीं चाहते हैं क्योंकि वे स्वयं उत्पाद का आयात कर रहे हों अथवा वे उत्पाद के आयातक या निर्यातक से संबंधित हों। ऐसे घरेलू उत्पादक पाटन की अनुचित प्रक्रिया के माध्यम से प्रतिस्पर्धा को समाप्त करने के लिए अन्य घरेलू उत्पादकों को उत्पादन बंद करने के लिए बाध्य कर सकते हैं। प्राधिकारी को स्वविवेक का अधिकार दिए जाने का एक कारण ऐसी संबंधित सत्ताओं को जांच से बाहर रखना है जो शेष घरेलू उत्पादकों द्वारा पाटनरोधी आवेदन करके और पाटन की अनुचित व्यापार प्रक्रिया के विरुद्ध उपयुक्त राहत की मांग करके उन्हें हुई क्षति की क्षतिपूर्ति की मांग करने के प्रयास को बाधित कर सकते हों। यदि ऐसा नहीं है तो शेष घरेलू उत्पादक पाटनरोधी आवेदन दायर करने और पाटन की अनुचित व्यापार प्रक्रिया के विरुद्ध उपयुक्त उपचार की मांग करने के लिए कानून में यथाप्रदत्त "योग्यता संबंधी अपेक्षा" को पूरा नहीं कर पाएंगे। संक्षेप में घरेलू उद्योग के दायरे से कतिपय कंपनियों को बाहर रखे जाने की जरूरत थी ताकि प्राधिकारी देश में क्षतिकारी पाटन का समाधान कर सकें।

(ख) एक या उससे अधिक घरेलू उत्पादकों ने संभवतः विचाराधीन उत्पाद का आयात किया है अथवा उनकी संबंधित कंपनी ने एक या उससे अधिक सकारात्मक कारणों से विचाराधीन उत्पाद का आयात अथवा निर्यात किया है। इनमें से कुछ कारण नीचे सूचीबद्ध किए गए हैं :

- (i) आयात अग्रिम लाइसेंस के अंतर्गत किए गए ताकि उत्तरवर्ती उत्पाद के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा की जा सके।
- (ii) आयात उत्पादन के अस्थायी निलंबन के समय किए गए हैं (जो अनेक वास्तविक कारणों जैसे आग लगने, हड़ताल होने, प्राकृतिक आपदा आदि के चलते हो सकता है)।
- (iii) आयात किसी विशेष किस्म के आयात के द्वारा उत्पाद की व्यवस्था को पूरा करने के लिए किए गए हैं जिसका उत्पादन शायद आवेदक न कर रहा हो और जो उसके कुल व्यावसायिक प्रचालनों का महज एक छोटा सा हिस्सा हो।
- (iv) आयात परीक्षण, अनुसंधान और विकास, बीज विपणन के प्रयोगों के लिए किए गए हों (घरेले उत्पादकों द्वारा कम कीमत के आयातों का सामना करते समय उत्पाद की

गुणवत्ता और अन्य मापदंडों की जांच के लिए आयात किया जाना एक आम समस्या है।

- (v) उत्पाद के किसी हिस्से का आयात उस उत्पाद के विनिर्माण में मुख्य कार्यकलाप नहीं होता है ।

स्वतः ही कुछ सदाशयी घरेलू उत्पादकों को केवल पूर्ववर्ती नियम 2(ख) के तहत अनिवार्य रूप से बाहर रखने की शर्त के कारण घरेलू उद्योग के दायरे से बाहर रखना उचित नहीं होगा।

17.5 इस प्रकार, प्राधिकारी का यह विचार है कि संशोधित नियम में उपर्युक्त स्थितियां प्राधिकारी के स्व-विवेकाधिकार का प्रावधान है । दूसरे शब्दों में पाटनरोधी नियमावली को निर्दिष्ट प्राधिकारी को स्व-विवेक प्रदान करने के लिए संशोधन किया गया है ताकि कतिपय स्थितियों में किसी घरेलू उत्पादक को शामिल किया जा सके या कतिपय स्थिति में किसी घरेलू उत्पादक को जांच से बाहर किया जा सके ।

17.6 किसी घरेलू उत्पादक को शामिल करने अथवा बाहर रखने के संबंध में पर्याप्त न्यायिक व्यवस्थाएं मौजूद हैं, जो निम्नानुसार संकेत करती हैं :

(क) इस संबंध में एक महत्वपूर्ण कारक विनिर्माण और आयात के बीच घरेलू उत्पादक के व्यापार का संतुलन है । यदि वह कंपनी अधिकांशतः भारत में उत्पाद का विनिर्माण करती है तो उसे शामिल किया जाना चाहिए । तथापि, यदि घरेलू उत्पादक उत्पादन बंद कर देता है या उसे घटा देता है और बजाए इसके उस उत्पाद का आयात करता है या व्यापार का सामान्य ध्यान उत्पादन से हटकर आयातों की ओर चला जाता है तो उसे बाहर रखा जाना चाहिए ।

(ख) यदि किसी घरेलू उत्पादक ने किसी संबंधित पक्षकार से आयात अथवा निर्यात का सहारा लेकर पाटन के प्रभाव से स्वयं को सुरक्षित रखने का प्रयास किया है, तो उस कंपनी को बाहर रखा जाना चाहिए ।

(ग) यदि किसी घरेलू उत्पादक ने किसी प्रकार से पाटन प्रक्रियाओं में भाग लिया है या अन्यथा अनुपयुक्त ढंग से उससे लाभान्वित हुआ है तो उसे बाहर रखा जाए ।

(घ) यदि किसी घरेलू उत्पादक को शामिल करने से क्षति संबंधी निष्कर्ष में गड़बड़ी आ जाएगी तो उसे बाहर रखा जाए ।

(ङ) यदि कोई घरेलू उत्पादक प्राधिकारी के साथ सहयोग नहीं करता है तो प्राधिकारी ऐसे घरेलू उत्पादक को अयोग्य मान सकते हैं ।

17.7 प्राधिकारी ने यह भी नोट किया है कि मै. जाको द्वारा लिखित पाठ्य पुस्तक ह्यूमैन एंड मिरांडा में अन्य बातों के साथ-साथ ऐसी स्थिति में अन्य डब्ल्यू टी ओ सदस्यों द्वारा अपनाए जाने वाले मापदंडों का उल्लेख है जो निम्नानुसार है :

(क) विचाराधीन उत्पाद के घरेलू उत्पादन का प्रतिशत जिसे संबंधित उत्पादकों द्वारा लेखांकित किया गया है ।

(ख) क्या संबंधित उत्पादकों द्वारा विचाराधीन उत्पाद के आयातों से उन्हें लाभ हुआ है या पाटन के प्रभावों से उनका संरक्षण हुआ है ।

(ग) क्या संबंधित पक्षकारों को बाहर रखने से उद्योग के शेष सदस्यों के आंकड़ों में अनुचित विकृति आ जाएगी ।

(घ) घरेलू उत्पादन के लिए उत्पादक द्वारा दर्शायी गई वचनबद्धता का स्तर या दीर्घावधिक प्रकृति जो आयात संबंधी कार्यकलापों के विरुद्ध हो ।

(ङ) संबंधित उत्पादकों के लिए घरेलू उत्पादन हेतु आयात संबंधी पोतलदानों का अनुपात ।

17.8 प्राधिकारी का यह मानना है कि कतिपय घरेलू उत्पादकों को शामिल करने अथवा बाहर रखने संबंधी स्वविवेक का प्रयोजन संगत घरेलू उद्योग से ऐसे घरेलू उत्पादकों, जिन्होंने क्षतिकारी पाटन में भाग लिया है को बाहर रखकर भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभावों के संबंध में वस्तुनिष्ठ और विशुद्ध निर्धारण करने में प्राधिकारी को सक्षम बनाना है । जांचकर्ता प्राधिकारी किसी संबंधित उत्पादक को बाहर रख सकते हैं जहां संबंधित पक्षकार ने

(क) बाजार पर कीमतों में गिरावट को उत्पन्न किया है या उसमें योगदान दिया है ।

(ख) उसके प्रभावों से स्वयं को संरक्षित किया है या

(ग) वे उससे अनुचित रूप से लाभान्वित हुए हैं ।

प्रथम श्रेणी अर्थात् पाटन की प्रथाओं में भागीदारी करने के संबंध में अनेक विशिष्ट स्थितियों में विभेद किया जा सकता है । एक ओर ऐसी स्थिति में बाहर रखना वस्तुतः उचित है जहां किसी घरेलू उद्योग की क्षति स्व-आरोपित है क्योंकि पाटित उत्पादकों से हुए आयातों ने घरेलू उत्पादक की अपनी क्षमता के प्रयोग को घटा दिया है या जिनके परिणामस्वरूप घरेलू उत्पादक को अपने स्वयं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए तैयार की गई परियोजनाओं को छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा है ।

17.9 दूसरी ओर किसी घरेलू उत्पादक को बाहर रखना प्रथम दृष्टया उचित नहीं है यदि पाटन में उसकी भागीदारी आत्मरक्षा का एक कार्य था । अतः ऐसे घरेलू उत्पादक को संगत घरेलू उद्योग को परिभाषित करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए ।

17.10 ऐसे घरेलू उत्पादकों, जो पाटित उत्पाद का आयात करते हैं या जिनका संबंधित निर्यातक पाटित उत्पाद का निर्यात करता है या जिनका संबंधित उत्पादक पाटित आयात का उत्पाद करता है और जो पाटन की प्रक्रिया से अनुचित रूप से लाभान्वित नहीं होते हैं । यदि ऐसे आयात उनकी बिक्रियों या बाजार के आकार के बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व नहीं करते हों । वस्तुतः ऐसे घरेलू उत्पादकों को बाजार में अन्य आपूर्तिकर्ताओं से प्रतिस्पर्धा के कारण इसका कोई लाभ नहीं मिलता । जांचकर्ता प्राधिकारी द्वारा इस बात का निर्णय लेने के लिए कि क्या किसी घरेलू उत्पादक को

बाहर रखा जाए, बनाया गया एक अन्य तरीका यह है कि क्या घरेलू उत्पादक कुछ पाटित आयातों के द्वारा अपने घरेलू उत्पादन की पूर्ति कर रहा है अथवा क्या वह प्राथमिक रूप से सीमित उत्पादन करने वाला कोई आयातक है। दूसरे मामले में ऐसी कंपनी को घरेलू उद्योग के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए। एक अन्य तत्व जिस पर विचार किया जा सकता है, यह है कि क्या जांचाधीन घरेलू उत्पादक को आयात के देश में उत्पादन के लिए वचनबद्ध कंपनी के रूप में समझा जा सकता है अथवा नहीं।

17.11 मै. ग्रासिम इंडस्ट्रीज लि. के घरेलू उद्योग होने के दावे पर प्रश्न उठाते हुए प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकार ने यह तर्क दिया है कि मै. ग्रासिम इंडस्ट्रीज लि. को घरेलू उद्योग बनने का हकदार नहीं माना जाना चाहिए। यू एस हॉट रोल्ड स्टील केस के मामले में डब्ल्यू टी ओ के अपीलीय निकाय के निर्णय का संदर्भ भी दिया गया है, जो सामान्य मूल्य के निर्धारण के संदर्भ में है और संबंधित पक्षकारों के बीच सौदों संबंधी व्यवहार से संबंधित है।

17.12 मामले के विधिक प्रावधानों और तथ्यों की सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान मामले में रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्य मै. ग्रासिम इंडस्ट्रीज लि. को घरेलू उद्योग नहीं माने जाने को न्यायोचित नहीं ठहराते हैं। प्रतिवादी पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग द्वारा संदर्भित मामले वर्तमान स्थितियों से संगत नहीं हैं तथापि, यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग द्वारा अपनाए गए मामले उन स्थितियों तक सीमित नहीं हैं जहां आवेदक कंपनी (कंपनियों) ने विचाराधीन उत्पाद का आयात किया हो। आवेदक ने कुछ निर्णयों का हवाला दिया है जिनमें एक घरेलू उत्पादक संबद्ध अथवा असंबद्ध देश के निर्यातक से संबंधित था और जांचकर्ता प्राधिकारियों द्वारा यह पाया गया था कि ऐसे घरेलू उत्पादक को घरेलू उद्योग की श्रेणी में शामिल किया जाना न्यायसंगत है।

प्रतिवादी पक्षकारों का यह तर्क कि घरेलू उद्योग को साधारणतया बाहर रखा जाए, न तो कानून के सामान्य पठन से सिद्ध होता है या न ही इस विषय संबंधी न्यायशास्त्र से सिद्ध होता है।

17.13. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग को परिभाषित करने वाले संगत प्रावधान प्राधिकारी को किसी संबंधित घरेलू उत्पादक को घरेलू उद्योग का हिस्सा मानने अथवा नहीं मानने का विवेक प्रदान करते हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऐसी स्थिति में जहां आवेदक निर्यातक देश में किसी उत्पादक से संबंधित है, वहां ऐसे संबंध के तथ्य मात्र से उस उत्पादक को घरेलू उद्योग के दायरे और कार्यक्षेत्र से स्वतः बाहर रखा जाना संभव नहीं है। वस्तुतः ऐसे मामलों में प्राधिकारी को स्व-विवेक मामला दर मामला आधार पर आगे जांच करने के लिए और इस बात की जांच करने के लिए प्रदान किया गया है कि क्या ऐसे संबंधित उत्पादक को घरेलू उद्योग में शामिल किए जाने का पात्र अथवा अपात्र समझा जाए। स्वयं सिद्ध ढंग से इस मामले के तथ्यों पर संबंध के प्रभाव पर इस प्रयोजनार्थ ध्यान देने की जरूरत है। इस प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित पर विचार किया है :

(क) क्या संबंधित पक्षकारों का व्यवहार असंबंधित पक्षकारों की तुलना में अलग और भिन्न है।

(ख) क्या यह दर्शाने वाला कोई साक्ष्य है कि ऐसे संबंधित उत्पादक ने भारतीय बाजार में पाटन शुरू किया अथवा उसे तेज किया।

(ग) क्या संबंधित घरेलू उत्पादक पाटन के प्रभाव से सुरक्षित रहा या उससे अनुचित ढंग से लाभान्वित हुआ ।

(घ) क्या संबंधित घरेलू उत्पादक ने भारतीय बाजार में प्रतिस्पर्धा को समाप्त करने का प्रयास किया ।

(ङ) क्या यह एक स्वयं आरोपित क्षति का मामला है ?

17.14. एक संबंधित पक्षकार होने के अलावा, वर्तमान मामले में संबंधित पक्षकार द्वारा किए गए निर्यातों यदि कोई हों, के प्रभाव का मूल्यांकन करना भी संगत है कि क्या ऐसे संबंधित पक्षकार ने इस अवधि के दौरान भारत को उत्पाद का निर्यात किया था । यदि हां तो क्षति के दावों पर उनका प्रभाव क्या है ? यदि नहीं, तो क्या ऐसा कोई अन्य आधार है जो अब भी बाहर रखे जाने को न्यायोचित ठहराता हो । यदि संबंधित पक्षकार ने भी संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है तो निम्नलिखित की भी जांच किया जाना अपेक्षित है ।

- ऐसे संबंधित पक्षकार द्वारा किए गए निर्यात की मात्रा
- संबंधित पक्षकार द्वारा किए गए ऐसे निर्यातों का प्रयोजन
- क्या यह बात दर्शाने वाला कोई साक्ष्य है कि घरेलू उद्योग को हुई क्षति संबंधित पक्षकार द्वारा ऐसे निर्यातों के कारण हुई थी ।
- क्या संबंधित घरेलू उत्पादक का सामान्य ध्यान संबद्ध वस्तु के उत्पादन पर था अथवा सामान्य ध्यान धीरे-धीरे अथवा निरंतर आयातों की ओर स्थानांतरित हुआ है ।
- क्या ऐसे संबंधित पक्षकार द्वारा किए गए निर्यातों की मात्रा इतनी रही थी कि संबंधित निर्यातक धीरे-धीरे अथवा निरंतर असंबंधित घरेलू उत्पादकों के बाजार के प्रतिस्थापित कर रहा था ।
- कोई अन्य कारक जिसे कार्यवाही की प्रक्रिया के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा संभवतः प्राधिकारी के ध्यान में लाया गया हो ।

17.15 पी टी साउथ पेसिफिक विस्कोस ने अन्य बातों के साथ-साथ यह तर्क दिया है कि उन्हें पी टी इंडो भारत रेयान द्वारा पाटन का सहारा लेने के लिए बाध्य किया गया है अर्थात् उन्होंने पाटन के रूप में अनुचित प्रतिस्पर्धा का सहारा इसलिए लिया क्योंकि अन्य पक्षकार पाटन कर रहा था । तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटन के कारण कानून के अंतर्गत पूर्णतः असंगत हैं और केवल पाटन का तथ्य संगत है । पाटनरोधी कार्रवाई में केवल पाटन की मौजूदगी और मात्रा संगत हैं और ऐसा पाटन किए जाने के कारण कोई महत्व नहीं रखते हैं । यदि एक या उससे अधिक विदेशी उत्पादकों (एक ही या भिन्न-भिन्न देशों के) को एक या उससे अधिक अन्य विदेशी उत्पादकों द्वारा पाटन का सहारा लेने के लिए बाध्य किया गया हो, तो कानून इसकी अनदेखी नहीं करता है । इसके अलावा, इस मामले के तथ्यों के आधार पर इस आरोप को गलत पाया गया था क्योंकि पी टी साउथ पेसिफिक विस्कोस ने पी टी इंडो भारत रेयान द्वारा निर्याति पोतलदानों से काफी पहले संबद्ध वस्तु का निर्यात किया था । पी टी साउथ पेसिफिक विस्कोस द्वारा किए गए निर्यातों

की मात्रा पी टी इंडो भारत द्वारा किए गए निर्यातों की मात्रा से काफी अधिक रही है । पी टी साउथ पेसिफिक विस्कोस को उसके घरेलू बाजार में भी संबंधित उत्पाद की घाटे पर बिक्री करते हुए पाया गया था और इसलिए यह आरोप कि उन्होंने अन्य पक्षकार द्वारा पाटन किए जाने के कारण पाटन किया है, तथ्यों पर आधारित नहीं है ।

17.16 प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों ने आगे यह तर्क दिया है कि प्राधिकारी को भारत में "एकमात्र एकाधिकारी उत्पादक" द्वारा पाटनरोधी प्रक्रिया का दुरुपयोग किए जाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए । तथापि, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि "पाटन" एक अनुचित व्यापार प्रक्रिया है और यदि इससे घरेलू उद्योग को क्षति साबित होती है तो इसकी भर्त्सना की जानी चाहिए, चाहे केवल एक घरेलू उत्पादक ही हो; क्योंकि पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य पाटन की अनुचित व्यापार प्रथाओं के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति का समाधान करना ही है । शुल्क लगाए जाने से भारतीय बाजार में अपाटित कीमतों पर संबद्ध वस्तुओं की बिक्री करने के विदेशी उत्पादकों के अधिकार प्रतिबंधित नहीं होंगे ।

17.17 इसके अलावा, प्राधिकारी नोट करते हैं कि न तो भारतीय कानून और न ही डब्ल्यू टी ओ पाटनरोधी करार में यह व्यवस्था है कि प्राधिकारी को केवल इसलिए किसी घरेलू उत्पादक को अयोग्य मान लेना चाहिए यदि वह विदेशी उत्पादक से संबंधित हो, यदि ऐसा संबंधित विदेशी उत्पादक जांच में भाग लेता हो और उसके निर्यातों के संबंध में सकारात्मक पाटन मार्जिन सिद्ध हुआ हो । इसके अलावा, प्रत्येक ज्ञात निर्यातक के संबंध में अलग-अलग पाटन मार्जिन निर्धारित किया जाना अपेक्षित है और यह अधिनियम अथवा पाटनरोधी नियमावली इस संबंध में किसी संबंधित और असंबंधित निर्यातक के बीच कोई भेद नहीं करती है । जहां तक नियम 2(ख) के अंतर्गत मान्यता संबंधी भ्रम का संबंध है, उसमें भी ऐसे मामले में स्पष्ट रूप से प्राधिकारी को स्वविवेक प्रदान किया गया था । तथापि, ऐसे स्व-विवेक का प्रयोग निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ ढंग से किया जाना चाहिए ।

17.18 प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क देते समय गलती की है कि आयातों की मात्रा पर आधारित मापदंड कोई तर्कसंगत मापदंड नहीं है । चूंकि वर्तमान मुद्दा किसी संबंधित निर्यातक द्वारा किए गए "निर्यात" का है, इसलिए प्राधिकारी मानते हैं कि आयातों की मात्रा वस्तुतः संबंधित घरेलू उत्पादक को बाहर रखने संबंधी निर्णय लेने के लिए एक प्रमुख कारक है । इसके अलावा यह अन्य बातों के साथ-साथ इस बात का आकलन करने में एक कारक होगा कि क्या दावा की गई क्षति स्वआरोपित क्षति है अन्यथा कुछ और है ।

17.19 प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान मामले में मै. ग्रासिम इंडस्ट्रीज लि. के पास इंडोनेशिया और चीन जन.गण में संबद्ध कंपनियां हैं जो संबंधित उत्पाद का उत्पादन और बिक्री करती हैं, जिनके नाम हैं बिरला जिगवाई फाइबर्स कं. लि., चीन जन.गण. और पी टी इंडो भारत रेयान, इंडोनेशिया है । पी टी इंडो भारत रेयान-इंडोनेशिया ने भेजी गई प्रश्नावली का अपना विस्तृत उत्तर भी दिया है जिसका सत्यापन प्राधिकारी द्वारा किया गया है और इन जांच परिणामों के संगत खंडों में उचित ढंग से उन पर विचार किया गया है । पी टी इंडो भारत रेयान मै. ग्रासिम इंडस्ट्रीज लि. की सहायक कंपनी नहीं है । यह नोट किया जाता है कि मै. ग्रासिम इंडस्ट्रीज लि. की पी टी इंडो भारत रेयान इंडोनेशिया में केवल ***% की शेयरधारिता और बिरला जिगवाई फाइबर्स कं. लि., चीन जन.गण में ***% की शेयरधारिता है । मै. ग्रासिम इंडस्ट्रीज लि. भारत में संबद्ध वस्तु का

एकमात्र उत्पादक है और उसने संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण क्षति का दावा किया है। एक संबंधित पक्षकार होने के बावजूद प्राधिकारी की जानकारी में उनके व्यवहार में ऐसा कोई अंतर नहीं आया है जिनसे ऐसा लगता हो कि वह कोई संबंधित पक्षकार है। मै. ग्रासिम इंडस्ट्रीज लि. द्वारा प्रतिस्पर्धा को समाप्त करने या वर्तमान मामले में पाटनरोधी शुल्क का आवेदन करके कोई अन्य अनावश्यक लाभ लेने के संबंध में प्राधिकारी को कोई साक्ष्य नहीं मिला है।

17.20 इसके अलावा, पी टी इंडो भारत रेयान द्वारा की गई निर्यातों की मात्रा काफी कम है और छिन्न-भिन्न प्रकृति की है; ये आयात शुल्क छूट श्रेणी के अंतर्गत असंबंधित आयातकों के द्वारा किए गए हैं। मै. ग्रासिम इंडस्ट्रीज लि. ने संबद्ध वस्तु का आयात नहीं किया है। इस संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऐसी स्थिति में जहां अधिकांश निर्यात असंबंधित इंडोनेशियाई निर्यातक द्वारा किए गए हैं और जहां पी टी इंडो भारत रेयान और भारतीय आयातक/उपभोक्ता के बीच केवल 3 बिक्री संबंधी सौदे (जांच अवधि के दौरान) हुए हैं, और वह भी शुल्क छूट योजना के अंतर्गत सामग्री के आयात के लिए, तो यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि इन पक्षकारों ने अन्य प्रतिस्पर्धियों को भारत से बाहर निकालने के लिए संधि की थी। इसके अलावा, यह नोट किया जाता है कि पी टी इंडो भारत रेयान से किए गए आयात शुल्क छूट योजना के अंतर्गत किए गए हैं। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यह सिद्ध करने के लिए कोई भी साक्ष्य नहीं दिया गया है कि इन दोनों पक्षकारों ने कोई मिलीभगत की है। इसके अलावा, यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है कि असंबंधित इंडोनेशियाई उत्पादक को पी टी इंडो भारत रेयान द्वारा उद्धरित कथित कम कीमतों के कारण कीमतों को कम करना पड़ा था। पी टी साउथ पेसिफिक विस्कोस द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ लगाये गये इस आरोप कि पी टी इंडो भारत रेयान-इंडोनेशिया द्वारा पाटन उत्पन्न और शुरू किया गया है की इन दोनों कंपनियों के सत्यापन के दौरान जांच की गई थी और इसे निराधार और गलत पाया गया था। यह विचार इंडोनेशिया से संबद्ध वस्तु के आयातों के विश्लेषण द्वारा और भी सुदृढ़ हो जाता है, जैसा कि निम्नांकित तालिका से देखा जा सकता है।

	आयात मी.ट. में		कुल आयात	का हिस्सा	का हिस्सा
	पी इंडो भारत रेयान एक्सपोर्ट्स	पी टी साउथ पेसिफिक विस्कोस एक्सपोर्ट्स	इंडोनेशिया से	पी इंडो भारत रेयान	पी टी साउथ पेसिफिक विस्कोस
2006	-	***	***	0.00%	100.00%
2007	***	***	***	5.51%	94.49%
2008	-	***	***	0.00%	100.00%
जन.-जून					
जांच अवधि	***	***	***	2.29%	97.71%

17.21 इसके अलावा, प्राधिकारी ने भारत में विचाराधीन उत्पाद के आयातों के संबंध में इंडोनेशिया के हिस्से की जांच की थी। यह पाया गया था कि यद्यपि, वर्ष 2006-07 में इंडोनेशिया से हुए आयात भारत में हुए कुल आयातों का केवल लगभग 38% रहे थे, परंतु 2007-08 में ये बढ़कर 74% हो गए, अप्रैल-जून, 2008 में 93% और जांच अवधि के दौरान 84% हो गए। इस

प्रकार यह स्पष्ट है कि इंडोनेशियाई आयातों के हिस्से में भारत में संबद्ध वस्तुओं के कुल आयातों की दृष्टि से निरंतर वृद्धि हुई है। इसके अलावा पी टी साउथ पेसिफिक विस्कोस का हिस्सा इंडोनेशिया से इन आयातों में काफी अधिक रहा था जैसा कि निम्नलिखित तालिका से देखा जा सकता है :

	भारत में कुल आयात	इंडोनेशिया से आयात	सकल आयातों में इंडोनेशिया का हिस्सा	पी टी साउथ पेसिफिक विस्कोस द्वारा निर्यात	कुल आयातों में पी टी साउथ पेसिफिक विस्कोस का हिस्सा
2006-07	6,774	2,554	37.70%	***	29.02%
2007-08	6,842	5,069	74.09%	***	71.67%
अप्रैल-जून 08	1,890	1,757	92.95%	***	92.95%
जांच अवधि	6,329	5,305	83.82%	***	81.90%

17.22 हितबद्ध पक्षकारों द्वारा संदर्भित डब्ल्यू टी ओ के निर्णय के संबंध में प्राधिकारी ने नोट किया है कि उस मामले का मुद्दा वर्तमान मामले में संगत नहीं है। उस मामले में मुद्दा यह था कि क्या संबद्ध पक्षकारों के बीच हुए सौदों को सामान्य मूल्य के निर्धारण के प्रयोजनार्थ व्यापार के सामान्य प्रक्रिया में हुए सौदे माना जा सकता है। इस प्रकार यद्यपि, उस मामले में मुद्दा सामान्य मूल्य और संबंधित पक्षकारों के बीच हुए सौदों के संदर्भ में उठाया गया था; वर्तमान मामले में विचाराधीन मुद्दा यह है कि क्या मै. ग्रासिक इंडस्ट्रीज लि. को संबद्ध देशों में उनकी संबद्ध कंपनियों के साथ उनके संबंधों के मद्देनजर नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग माने जाने हेतु अपात्र समझा जाना चाहिए। यह भी नोट करना संगत है कि सामान्य मूल्य के निर्धारण के संदर्भ में भी; संबंधित पक्षकारों के बीच सभी सौदों को विश्वसनीय अथवा अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता है और इस प्रकार उनकी जांच प्रत्येक मामले के गुण-दोष के आधार पर की जा सकती है। यद्यपि वर्तमान मामले में सौदे ऐसे संबंधित पक्षकारों के बीच भी नहीं हुए हैं अपितु पी टी इंडो भारत और असंबंधित भारतीय उपभोक्ताओं के बीच हुए हैं।

17.23 पी टी साउथ पेसिफिक विस्कोस ने अन्य बातों के साथ-साथ यह तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग और पी टी इंडो भारत रेयान का उद्देश्य भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा को अवरुद्ध करना है। तथापि, वर्तमान मामले में सिद्ध सकारात्मक पाटन मार्जिन को देखते हुए यह स्पष्ट है कि असंबंधित इंडोनेशियाई उत्पादक ने पाटन नहीं किया है, जिसे उकसाया गया नहीं पाया गया है और वह पी टी इंडो भारत रेयान द्वारा की गई 3 छोटी पोतलदानों के कारण ही सिद्ध नहीं होता है। पी टी साउथ पेसिफिक विस्कोस द्वारा पाटित कीमतों पर संबद्ध वस्तु का भारी मात्रा में निर्यात किया गया है। जांच करने पर प्राधिकारी का यह निष्कर्ष है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को "क्षति" हुई है जैसा कि इन जांच परिणामों के संगत खंडों में देखा जा सकता है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि छोटे और छिटपुट निर्यात इस क्षति के खास कारक नहीं रहे हैं। इसके अलावा, मै. ग्रासिक इंडस्ट्रीज लि. का मुख्य ध्यान संबद्ध वस्तु के उत्पादन और बिक्री करने पर रहा है। इस प्रकार यह स्व आरोपित क्षति का मामला प्रतीत नहीं होता है। प्राधिकारी ने ऐसे पाटनरोधी मामलों को भी नोट किया है जिनमें यद्यपि आयात संबंधित घरेलू उत्पादकों द्वारा अपनी संबद्ध कंपनियों से किए गए थे, तब भी जांचकर्ता प्राधिकारियों द्वारा उन्हें घरेलू उद्योग का हिस्सा माना गया है। इस प्रकार प्राधिकारी को घरेलू

उद्योग के दायरे और कार्यक्षेत्र से मै. ग्रासिम इंडस्ट्रीज को बाहर रखे जाने का कोई न्यायसंगत कारण दिखाई नहीं दिया है।

17.24 अतः प्राधिकारी इस बात को दोहराते हैं कि आवेदक को पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अंतर्गत घरेलू उद्योग के दायरे से बाहर रखा जाना अपेक्षित नहीं है। इस प्रकार, एसोसिएशन ऑफ़ मैनमेड फाइबर इंडस्ट्रीज आफ़ इंडिया द्वारा घरेलू उद्योग की ओर से आवेदन दायर किया गया है। आवेदक के इस दावे कि भारत में समान वस्तु का कोई अन्य उत्पादक नहीं है, पर किसी हितबद्ध पक्षकार ने प्रश्न नहीं उठाया है। रिकॉर्ड में उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार मै. ग्रासिम इंडस्ट्रीज लि. का उत्पादन संबद्ध वस्तु के घरेलू उत्पादन का एक प्रमुख हिस्सा बनता है। मै. ग्रासिम इंडस्ट्रीज लि. का उत्पादन भारती उत्पादन का 50% से अधिक है।

17.25. इस प्रकार प्राधिकारी अपने इस विचार को दोहराते हैं कि पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अंतर्गत मै. ग्रासिम इंडस्ट्रीज लि. को घरेलू उद्योग मानना उचित है। तदनुसार प्राधिकारी ने यह निर्धारित किया है कि यह आवेदन पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) और नियम 5(3) की अपेक्षाओं को पूरा करता है।

इ अन्य मुद्दे

ड1 इंडियन स्पिनर्स एसोसिएशन, राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स एसो. और पी टी साउथ पेसिफिक विस्कोस द्वारा किए गए अनुरोध

18. इंडियन स्पिनर्स एसोसिएशन, राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स एसो. और पी टी साउथ पेसिफिक विस्कोस द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :

- उन्होंने घरेलू उद्योग द्वारा गौण स्रोत से आंकड़े एकत्र करने पर आपत्ति जताई है। वे मानते हैं कि आवेदक की यह पूरी जिम्मेदारी है कि वह सरकारी आंकड़े उपलब्ध कराए। चूंकि आवेदक द्वारा दिए गए आंकड़े आधिकारिक नहीं हैं, इसलिए आवेदक द्वारा निकाला गया निष्कर्ष गलत है।
- संबंधित उत्पाद का समर्पित सीमाशुल्क कोड है; इसलिए आयातों के आधार के रूप में गौण स्रोत पर विचार करना न्यायोचित नहीं है। डी जी सी आई एंड एस के आंकड़ों में द्वितीयक स्रोतों की तुलना में काफी अधिक मात्राओं और अधिक कीमतों को दर्शाया गया है।
- डी जी सी आई एंड एस के अनुसार अन्य देशों से आयात किए गए हैं। तथापि, आवेदक यह दावा करता है कि संबद्ध देशों के अलावा, कहीं से भी आयात नहीं हुए हैं।
- मंदी की स्थितियों के कारण इस फैब्रिक की खपत पर पूरे विश्व भर में काफी प्रभाव पड़ा है और इससे न केवल फैब्रिक की कीमतें प्रभावित हुई हैं बल्कि विस्कोस स्टेपल फाइबर समेत यार्न और फाइबर की कीमतें भी प्रभावित हुईं।
- आवेदक अपने एन ए जी डी ऐ संयंत्र में पानी की कमी के समय को छोड़कर सदैव पूर्ण क्षमता पर प्रचालन करता रहा है, परंतु वर्ष 2008-09 में मंदी के कारण उसने अपना खराब संयंत्र बंद कर दिया है और इससे क्षमता उपयोग भी प्रभावित हुआ।

- जांच अवधि के दौरान आयातों की औसत सी आई एफ कीमत वर्ष 2007-08 की औसत सी आई एफ कीमत से अधिक रही है ।
- घरेलू उद्योग के साथ मूल समस्या प्रवृत्तियों में बदलावा पर विचार किए बिना क्षमता में लगातार विस्तार करने की रही है ।
- आवेदक के पास व्यापक संसाधन और विश्व भर में संपर्क हैं और इसे स्पिनिंग उद्योग की मदद के लिए निश्चित रूप से आगे होना चाहिए ।
- आवेदक भारत में संबंधित उत्पाद का एकमात्र उत्पादक है । पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से ग्रासिम और उसके समूह की कंपनियों, जिनके पास थाईलैंड समेत अन्य देशों में भारी वी एस एफ क्षमताएं हैं, के पक्ष में एकाधिकार की स्थिति सृजित हो जाएगी ।
- 6 महीने की जांच अवधि पाटन और घरेलू उद्योग को हुई क्षति के आकलन और विश्लेषण के लिए काफी कम है । निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा पहले जारी की गई व्यापारिक सूचना में भी यह स्पष्ट रूप से अधिदेशित है कि जांच अवधि सामान्यतः 12 महीने की होनी चाहिए । डी जी ए डी की परिपाटी जांच अवधि को वित्तीय वर्ष के रूप में निर्धारित करने की रही है । जांच अवधि का निर्धारण करते समय वित्तीय रिपोर्टिंग, आंकड़ों/सूचना की उपलब्धता, उत्पाद की विशेषताओं, मौसम से संबंध, चक्रीयता आदि जैसे कारकों पर विचार नहीं किया गया है । जांच के लिए 6 महीने की अवधि रखना पाटनरोधी प्रथाओं संबंधी समिति के दिशा निर्देशों के भी विरुद्ध है ।
- छः माह की जांच अवधि से विश्व को अभूतपूर्व वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा है, अतः उद्योग को भी सहना पड़ा है । वस्तुतः जांच अवधि सामान्यतः एक वर्ष करने की प्रक्रिया यह सुनिश्चित करने के लिए है कि मूल्यों में अल्पावधिक उतार-चढ़ाव के कारण कोई पाटनरोधी जांच आरंभ न हो । साथ ही प्राधिकारी इस बात से पूर्णतया अवगत है कि छः माह की अल्पतम अनुमेय जांच अवधि में करीब चार माह का समय ऐसा है, जब समूचा विश्व अभूतपूर्व आर्थिक और वित्तीय संकट से गुजर रहा था, जिसमें फाइबर और बाद में यार्न तथा फाइबर उद्योग पर काफी प्रभाव पड़ा । यह स्वीकार्य सत्य है कि निरंतर विकसित होते बाजार में काफी गिरावट आई थी और इसीलिए निर्दिष्ट प्राधिकारी को घरेलू उद्योग द्वारा चुनी गई अवधि को नहीं रखना चाहिए, चाहे वह अवधि कानूनम अनुमेय हो । यह स्पष्ट किया जाए कि यहां पर मामला 6 माह की जांच अवधि चुनने का नहीं है बल्कि उसके औचित्य और उपयुक्तता का है ।

ड2 घरेलू उद्योग के अनुरोध

19. याचिकाकर्ता द्वारा निम्नलिखित अन्य अनुरोध किए गए :-

- जांच अवधि - याचिका में जांच अवधि के रूप में 6 माह पर विचार करने के विशिष्ट कारण दिए गए हैं । ऐसा हितबद्ध पार्टियों के इस तर्क के बावजूद हुआ है कि 6 माह की जांच अवधि अनुमत्य नहीं है । यद्यपि व्यापार सूचना में "सामान्य" शब्द का उपयोग हुआ है न कि "सदैव" शब्द का । एचएएस के मामले में सेस्टेट के निर्णय के संगत उद्धरण संलग्न किए गए हैं जिसमें न्यायाधिकरण ने स्पष्ट तौर पर यह निर्णय दिया है कि जांच अवधि के रूप में 6 माह पर विचार करने पर कोई पाबंदी नहीं है । जहां तक 6 माह की अवधि को

चुनने का संबंध है, याचिका में इस बात का उल्लेख है। इस सीमा तक तर्क वस्तुतः सही नहीं है।

- निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा जांच शुरू करने हेतु जारी नोटिस में जांच अवधि के रूप में 6 माह का समय चुनने के कारण दिए गए हैं।
- माननीय न्यायाधिकरण द्वारा बिरघाऊ लेबोरेट्रीज लि. बनाम वित्त मंत्रालय के मामले में जांच अवधि के रूप में 6 माह की अवधि करने के निर्णय को बरकरार रखा गया है।
- यहां तक कि विश्व व्यापार संगठन के करार में भी जांच अवधि चुनने के संबंध में कोई विधिक प्रावधान नहीं है।
- याचिका में ही 6 माह की जांच अवधि के औचित्य का उल्लेख है। यह कहना सही नहीं है कि 6 माह की जांच अवधि अल्प अवधि है। निम्नलिखित कुछ ऐसे मामले हैं, जिनमें 6 माह की जांच अवधि रखी गई थी :-

अमरीका, थाईलैंड तथा कोरिया जन.गण. से एकेलिक फाइबर	अप्रैल 95-सितं. 95
कैमोड रे टेलीविजन पिकचर ट्यूब	जुलाई 09-दिसं. 09
सूक्ष्म बैटरी	अप्रैल 00-सितं.00
हाइड्रोलिक एसिड	अप्रैल 101-सितं. 01
हाइड्रोलिक एमिन सल्फेट	जुलाई 99-दिसं. 99
लीड एसिड बैटरी- बंगलादेश, जापान, कोरिया, चीन जन.गण.	सितं. 02-फरवरी 03
पैसिलीन जी तथा पोटेशियम 6 एपीए	अक्तू. 08-मार्च 09
बिनाइल एसिटेड मोनोमार	अप्रैल 01-सितं. 01
मिटिकाइड टाइल्स	सितं.04-फर. 05
	अप्रैल 05-सितं. 05
	सितं.05-फर.06

- याचिकाकर्ता ने स्पष्ट तौर पर यह उल्लेख किया गया है कि सूचना टिप्स से प्राप्त की गई है। ऐसा मानना होने के कारण यह तर्क निराधार है कि स्रोत का खुलासा नहीं किया गया है। जहां तक डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों के उपयोग का संबंध है, इन्हें इस कारण नहीं अपनाया गया है कि विचाराधीन उत्पाद का अनन्य सीमाशुल्क वर्गीकरण नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि हितबद्ध पार्टियों में कुछ गलतफहमी है कि विचाराधीन उत्पाद का अनन्य सीमाशुल्क वर्गीकरण है। इसके अलावा, सौदा-दर-सौदा आंकड़े निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष आवेदन दायर करने के बाद ही उपलब्ध कराए जा सकते हैं। जहां तक याचिका में उल्लिखित आंकड़ों के साथ डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों का संबंध है, धुंकी उत्पाद के दायरे में कभी प्रकार का वीएसएफ शामिल नहीं है, इसलिए डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों के साथ कोई तुलना भ्रामक होगी।
- कंपनी के वार्षिक संयंत्र में पूर्व में दो उत्पादन लाइनें थीं। दो और लाइनें जोड़ी गई थीं जिन्होंने उत्पादन मार्च-अप्रैल, 2008 की अवधि में शुरू किया था। क्षमता में यह वृद्धि ग्राहकों द्वारा प्रदत्त बाजार पूरक सूचना के आधार पर की गई थी। वस्तुतः कंपनी ने ग्राहकों से प्रदत्त इस आशय की पूरक सूचना पर ही क्षमता विस्तार की योजना बनाई थी

कि उत्पाद की मांग अच्छी है । तथापि, पाटन एवं प्रतिकूल बाजारी स्थिति के कारण जांच अवधि में इन दोनों लाइनों का पूर्ण उपयोग नहीं हो सका ।

ड3 प्राधिकारी द्वारा जांच

20. प्राधिकारी ने जांच अवधि के बारे में हितबद्ध पार्टियों द्वारा किए गए अनुरोधों को नोट किया है और उनका यह मत है कि वर्तमान मामले में चुनी गई जांच अवधि का चुनाव मामले के तथ्यों पर विचार करते हुए उचित ढंग से किया गया है जिसमें इस विषय पर उपलब्ध नवीनतम आंकड़े भी शामिल हैं ।

21. जांच अवधि के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि विरोध कर रहे हितबद्ध पक्ष यह मानते हैं कि जांच अवधि के रूप में 6 माह की अवधि निर्धारित करना गैर-कानूनी है । तथापि, उन्होंने यह तर्क दिया है कि वर्तमान मामले में अनेक तथ्यात्मक स्थितियों में यह अनुपयुक्त है । इस मामले की प्राधिकारी द्वारा ध्यानपूर्वक जांच की गई । यह कहना सही नहीं है कि डी जी ए डी में जांच अवधि के रूप में 12 माह की अवधि रखने की प्रथा है । जांच अवधि के रूप में किसी अवधि विशेष के लिए निर्णय प्रत्येक मामले के गुण-दोष के आधार पर लिया जाता है । इसके अलावा, जांच अवधि के रूप में 6 माह की अवधि रखने का निर्णय माननीय न्यायाधिकरण द्वारा बिरचाऊ लेबोरेट्रीज लि. बनाम वित्त मंत्रालय के मामले में बरकरार भी रखा गया है ।

22. जहां तक दिशा निर्देशों अथवा निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई प्रथा अथवा पाटनरोधी प्रक्रिया संबंधी समिति के दिशानिर्देशों का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि (क) वस्तुतः निर्दिष्ट प्राधिकारी ने अनेक मामलों में जांच अवधि के रूप में 6 माह की अवधि स्वीकार की है, (ख) हितबद्ध पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि जांच अवधि के रूप में 6 माह की अवधि के बारे में विचार करना गैर-कानूनी नहीं है । (ग) कथित दिशानिर्देशों को मामले के तथ्यों पर विचार किए बिना सभी स्थितियों में लागू अनिवार्य सलाह नहीं मना जा सकता । वित्तीय संसूचना जैसे कारकों को नहीं माना जा सकता क्योंकि यह जांच अवधि के रूप में केवल एक अवधि अर्थात् अप्रैल-मार्च पर विचार करने के लिए लागू होगा । जांच अवधि के रूप में 6 माह की अवधि मानने के कारणों के संबंध में, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यह प्रारंभिक जांच परिणामों में उल्लिखित है । इस तर्क के संबंध में कि 6 माह की जांच अवधि में मंदी की 4 माह की अवधि शामिल है, प्राधिकारी का मानना है कि मंदी के तथ्य का सामान्य मूल्य में कम निर्यात मूल्य के समान में इच्छानुसार तर्क नहीं दिया जा सकता क्योंकि मंदी का तथ्य सामान्य मूल्य के लिए भी समान रूप से लागू होगा । तथापि, यह नोट किया गया कि इंडोनेशिया में संबंधित समान के घरेलू मूल्य भारत को निर्यात किए गए मूल्य से वस्तुतः अधिक थे । अतः वैश्विक बाजार में मंदी को जांच अवधि निर्धारित करने में विचार करने हेतु औचित्यपरक कारण नहीं माना जा सकता ।

23. जहां तक मांग में कमी का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि मांग में कमी से घरेलू उद्योग तथा आयात समान रूप से प्रभावित हुआ होगा । तथापि, ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि मांग में कमी आई हो लेकिन संबंधित देशों से निर्यात की मात्रा में वृद्धि हुई हो । प्राधिकारी का यह मानना

है कि 6 माह की जांच अवधि आयात मूल्यों में काफी गिरावट तथा घरेलू उद्योग की वित्तीय स्थिति में महत्वपूर्ण ह्रास को देखते हुए न्यायोचित थी।

24 प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद बांस के फाइबर को छोड़कर विस्कोस स्टेपल फाइबर है। विचाराधीन उत्पाद के लिए सीमाशुल्क वर्गीकरण में बांस के फाइबर को अलग नहीं रखा गया है। अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत संक्षिप्त सूचना पर भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें विचाराधीन उत्पाद से भिन्न उत्पाद के आवात शामिल हो सकते हैं। घरेलू उद्योग ने टिप्स द्वारा प्रदत्त सूचना प्रस्तुत की है जिसे जांच की शुरुआत के समय स्वीकार किया गया था।

25. घरेलू उद्योग ने आरोप लगाया है कि सीमाशुल्क उपशीर्ष सं. 5504 9090 के अंतर्गत भारी मात्रा में आयात होने की सूचना दी गई है। प्राधिकारी ने सीमाशुल्क वर्गीकरण सं. 55041000 तथा 55049090 के लिए आयात की सूचना हेतु डीजीसीआईएंडएस के कार्यालय से अनुरोध किया था जिसे प्राप्त कर उसका विश्लेषण किया गया था। तदनुसार संबद्ध वस्तु की आयात मात्रा का निर्धारण किया गया है। आवेदक द्वारा टिप्स के आंकड़ों और डी जी सी आई एंड एस के आंकड़ों के अनुसार दावा किए गए आयातों की तुलना से निम्नानुसार पता चलता है:

	टिप्स आंकड़े		डी जी सी आई एंड एस आंकड़े	
	मात्रा किग्रा.	रु./किग्रा.	मात्रा किग्रा.	रु./किग्रा.
चीन जन.गण.	907252	96.03	1023971	94.13
इंडोनेशिया	4533741	98.44	4689364	98.47

26. रिकार्ड में उपलब्ध सामग्री से यह देखा गया है कि संबद्ध देशों को छोड़कर किसी अन्य देश से संबद्ध वस्तु का कोई आयात नहीं हुआ है। डी जी सी आई एंड एस और टिप्स के अनुसार मात्रा एवं कीमत मोटे तौर पर तुलनीय है।

घ. पाटन मार्जिन

घ.1 घरेलू उद्योग के विचार

- चूंकि चीन जन.गण. से किसी भी निर्यातक/उत्पादक ने उत्तर नहीं दिया है और बाजार अर्थव्यवस्था में सुधार के अपने दावे के संबंध में कोई याचिका दायर नहीं की है, अतः गैर-बाजार अर्थव्यवस्था देश के लिए लागू नियमों के अनुसार चीन जन.गण. से सभी निर्यातकों/उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य निर्धारित किया जाए।
- याचिकाकर्ता ने पाटनरोधी नियमों के अंतर्गत अनुबंध-1 के पैरा 7 का हवाला दिया है, जिसे दिनांक 15 जुलाई, 1999 की अधिसूचना सं. 44/99-सी यू एस (एन टी) द्वारा समाविष्ट किया गया है। नियमों में गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के मामले में सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए विभिन्न पद्धतियों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है।
- नियमों में दो बार संशोधन किया जा चुका है ताकि नियमों में विनिर्दिष्ट विस्तृत मानदंडों को पूरा करने पर चीन के उत्पादकों को इस बात की छूट दी जा सके कि वे बाजार की अर्थव्यवस्था के अनुरूप हो सके।

- चीन जन.गण. एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश है । किसी भी देश ने विस्तृत मूल्यांकन प्रक्रिया अपनाने के बाद चीन जन.गण. को बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा प्रदान नहीं किया है । चीन जन.गण. को यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य द्वारा गत तीन वर्षों में गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में माना गया है । यहां तक कि चीन जन.गण. ने संधि में इस बात को सहमति दी है कि विश्व को सहमति दी है कि विश्व व्यापार संगठन के सदस्य गैर-बाजार अर्थव्यवस्था पाटनरोधी प्रणाली का 11 दिसंबर, 2016 के अंत तक उपयोग कर सकते हैं । यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं । भारत में भी, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने चीन जन.गण. को संशोधन के बाद चीन जन.गण. के खिलाफ शुरू सभी जांच में व्यवहारिक रूप से गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में माना है । दिनांक 4.जनवरी .02 के संशोधन के बाद भी, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने चीन जन.गण. को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में माना है ।
- यूरोपीय कमीशन ने कुछ कंप्रेसरों, वायर रॉड, कुछ तैयार या संरक्षित खट्टे फलों (नामतः नारंगी आदि), लौह अथवा अलौह इस्पात की वेल्ड की गई ट्यूब और पाइप, चीन जन.गण. से साइट्रिक एसिड के मामले में चीन जन.गण. को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में माना गया है । संयुक्त राज्य अमरीका ने चीन जन.गण. को, बेरियम कार्बोनेट, कम व्यास वाले ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड, फोल्डिंग मेटल टेबल तथा चेयर टेपर्ड रोलर बीयरिंग तथा तैयार और बिना तैयार उनके पुर्जों के मामले में एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में माना है ।
- नियमों के अंतर्गत 15 अनिवार्य शर्तें निर्धारित हैं, जिनमें से प्रत्येक शर्त इच्छुक निर्यातक को पूरी करनी होती है ताकि वह बाजार की अर्थव्यवस्था के सुधार और ऐसे दावे के लिए संगत व आवश्यक सूचना तथा साक्ष्य का दावा कर सके । जब तक चीन के संबंधित निर्यातक इन मानकों को पूरा नहीं करते, निर्दिष्ट प्राधिकारी को नियमों के अनुलग्नक-1 के पैरा 7 के अनुरूप सामान्य मूल्य निर्धारित करना जरूरी होगा ।
- क्योंकि चीन के किसी भी निर्यातक/उत्पादक ने प्रतिक्रिया नहीं दी है, अतः चीन जन.गण. में सामान्य मूल्य का निर्धारण, (क) भारत में मूल्य तथा (ख) भारत में उत्पादन की लागत को बिक्री, सामान्य तथा प्रशासनिक व्यय व लाभ सहित समायोजित करके किया जाएगा ।
- प्राधिकारी द्वारा प्रारंभिक जांच परिणाम में निर्धारित पाटन मार्जिन अनंतिम अनुमान थे और पूर्व की परिभाषा व नियमों की जानकारी के आधार पर थे । प्रत्येक उत्पादक और निर्यातक के लिए अलग-अलग सामान्य मूल्य का निर्धारण हो जाने के बाद, याचिकाकर्ता यह अनुमान लगाता है कि एस पी वी के लिए पाटन मार्जिन प्रारंभिक जांच परिणाम में किए गए निर्धारण से काफी अधिक होगा ।
- पाटन मार्जिन में अंतर का तात्पर्य यह नहीं होता कि भारतीय बाजार आई बी आर मूल्य निर्धारित कर रहा है । जांच अवधि में निर्यातित 6329 मी.ट. में से आई बी आर ने केवल 121 मी.ट. निर्यात किया है, यह भी अगस्त, 2008, सितंबर, 2008 तथा दिसंबर, 2008 में सूचीबद्ध कर लिया गया था । इस मामले में यह केवल काल्पनिक है कि आई बी आर के कम मूल्यों के कारण एस पी वी मूल्यों को कम करने के लिए बाध्य हो गया ।

च.2 भारतीय स्पिनर्स की एसोसिएशन तथा पी टी साउथ पैसिफिक विस्कोस- इंडोनेशिया सहित निर्यातकों/आयातकों तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

- पी टी इंडो भारत रेयान का पाटन मार्जिन 11.26% है, जबकि पी टी साउथ पैसिफिक विस्कोस के लिए यह मात्र 6.30% है । पी टी इंडो भारत रेयान के लिए पाटन मार्जिन साउथ पैसिफिक विस्कोस का लगभग दो गुना है ।

- पी टी साउथ पैसिफिक विस्कास के पास पी टी इंडो भारत रेयान की कीमतों का अनुसरण करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है । पी टी इंडो भारत रेयान ने यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए हैं कि पी टी साउथ पैसिफिक विस्कोस पहले उत्पादों की कीमतों में कमी करने को बाध्य हो तथा याचिकाकर्ता पाटनरोधी शुल्क का मामला दायर करे ।
- पी टी इंडो भारत रेयान द्वारा अपना अलग से पाटन मार्जिन का दावा करना नियम 2(ख) के प्रयोजन तथा उद्देश्य के प्रतिकूल है ।

च.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

27. प्राधिकारी ने चीन जन.गण. के ज्ञात निर्यातकों को यह सलाह देते हुए प्रश्नावली भेजी कि निर्धारित प्रपत्र में और ढंग से सूचना उपलब्ध कराई जाए । तथापि, चीन के किसी भी उत्पादक/निर्यातक से प्रश्नावलियों का कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है । उपर्युक्त कुछ मामलों को प्राधिकारी द्वारा इन जांच परिणामों के संगत खंड में पहले ही उल्लेख किया जा चुका है ।

28. नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 में उपबंधित है कि:

गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयातों के मामले में सामान्य मूल्य का निर्धारण बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश की कीमत अथवा संरचित मूल्य, अथवा किसी तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहां यह संभव न हो, अथवा अन्य किसी समुचित आधार पर किया जाएगा, जिसमें भारत में समान वस्तु के लिए वास्तविक रूप से संदत्त अथवा भुगतान योग्य कीमत, जिसमें यदि आवश्यक हो तो लाभ की समुचित गुंजाइश भी शामिल की जाएगी । निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे समुचित देश का चयन उचित तरीके से किया जाएगा जिसमें संबंधित देश के विकास के स्तर तथा प्रश्नगत उत्पाद का ध्यान रखा जाएगा और चयन के समय उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना का भी ध्यान रखा जाएगा । जहां उचित हो उचित समयसीमा के भीतर किसी अन्य बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के संबंध में इसी प्रकार के मामले में की गई जांच पर भी ध्यान दिया जाएगा । जांच से संबंधित पक्षों को बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के उपर्युक्त प्रकार से चयन के बारे में बिना किसी अनुचित विलंब के सूचित किया जाएगा और उन्हें अपनी टिप्पणियां देने के लिए उचित अवधि प्रदान की जाएगी ।"

29 प्राधिकारी नोट करते हैं कि पिछले तीन वर्षों में भारत तथा डब्ल्यूटीओ के अन्य सदस्यों द्वारा की गई पाटनरोधी जांचों में चीन जन.गण. को गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में माना गया है । चीन जन.गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना गया है बशर्ते निर्यातक देश और अलग-अलग निर्यातकों द्वारा पाटनरोधी निषेधों के अनुसार इस अनुमान का खंडन किया गया हो ।

30. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध 1 के पैराग्राफ 8 के अनुसार गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के अनुमान का उस स्थिति में खंडन किया जा सकता है यदि चीन जन.गण. के निर्यातक (निर्यातकों) द्वारा पैराग्राफ 8 के उप पैरा(3) में विनिर्दिष्ट मानदंडों के आधार पर सूचना और पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध कराते हैं और उसके विपरीत सिद्ध करते हैं । चीन जन.गण. के संबद्ध वस्तु के निर्यातकों/उत्पादकों के लिए बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी व्यवहार विषयक प्रश्नावली के उत्तर में पैरा 8 के उप पैरा (3) में उल्लिखित आवश्यक सूचना/पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करना अपेक्षित है ताकि निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित मापदंडों पर विचार कर सकें कि क्या :-

- (क) कच्ची सामग्रियों सहित कीमत; लागत और निविष्टि तथा श्रम लागत, उत्पादन, बिक्रियां और निवेश के बारे में चीन जन.गण. में संबंधित फर्मों का निर्णय ऐसे बाजारी संकेतों के अनुसार किया जाता है जिसमें आपूर्ति और मांग परिलक्षित होती है और इस बारे में राज्य का अधिक हस्तक्षेप नहीं होता है और क्या प्रमुख निविष्टियों की लागत में बाजार मूल्य पर्याप्त रूप से प्रदर्शित होते हैं;
- (ख) इस प्रकार की फर्मों की उत्पादन लागत और वित्तीय स्थिति विशेषकर परिसंपत्तियों के मूल्यहास, अन्य बड़े खातों, वस्तु विनिमय-व्यापार और ऋणों की प्रतिपूर्ति के माध्यम से भुगतान के संदर्भ में पूर्ववर्ती गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाली प्रणाली से हुई महत्वपूर्ण विकृतियों के अध्यक्षीन हैं;
- (ग) इस प्रकार की फर्में दिवालियापन और संपत्ति कानूनों के अध्यक्षीन हैं जो फर्मों के प्रचालन की कानूनी निश्चितता और स्थिरता की गारंटी देते हैं; और
- (घ) विनिमय दर का परिवर्तन ब्याज की दर पर किया जाता है ।

31. प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्राधिकारी द्वारा जारी जांच शुरुआत संबंधी सूचना के बाद चीन के किसी उत्पादक/निर्यातक ने बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी प्रश्नावली के उत्तर सहित कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है और गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के अनुमान का खंडन नहीं किया है । जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना में ही प्राधिकारी ने यह संकेत दिया था कि आवेदक ने उचित प्रतिनिधि देश के रूप में इंडोनेशिया का सुझाव दिया है । हितबद्ध पार्टियों ने इस संबंध में अनुरोध करने का निवेदन किया था । तथापि, चीन जन.गण. के किसी भी निर्यातक/उत्पादक ने उत्तर नहीं दिया है और इस संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया है । अतः प्राधिकारी ने इस बात की जांच की है कि क्या इंडोनेशिया को चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारण के प्रयोजन से एक उचित प्रतिनिधि बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में माना जा सकता है । इस प्रयोजन के लिए प्राधिकारी ने इंडोनेशिया के विकास के स्तर और कथित सामानों को ध्यान में रखा । अन्य बातों के साथ-साथ यह भी नोट किया कि ये इंडोनेशिया में कथित सामान के दो प्रमुख उत्पादक हैं और संयोग से दोनों ने ही इस जांच में सहयोग किया है । साथ ही यह भी नोट किया गया है कि इन उत्पादकों द्वारा इंडोनेशिया के घरेलू बाजार में महत्वपूर्ण घरेलू बिक्री की गई है । अतः प्राधिकारी इस बात पर विचार करते हैं कि इंडोनेशिया को इस मामले विशेष में एक उचित प्रतिनिधि देश के रूप में मानना उचित होगा । अतः इंडोनेशिया को चीन जन.गण. के लिए एक उचित प्रतिनिधि देश मानकर प्राधिकारी ने इंडोनेशिया के औसतन सामान्य मूल्य को महत्व दिया है । जैसा कि चीन जन.गण. के लिए निर्धारित है, जिसे *** अम.डॉ. प्रति कि. ग्रा. निर्धारित किया गया ।

च.4 चीन जन.गण. के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण

32. चूंकि चीन जन.गण. के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने उत्तर नहीं दिया है इसलिए प्राधिकारी ने रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों के अनुसार निर्यात कीमत निर्धारित की है । प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक ने गौण स्रोतों के अनुसार सौदेवार सूचना प्रस्तुत की है । बाद में प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंडएस से आयात के आंकड़े प्राप्त किये । अतः प्राधिकारी ने चीन जन.गण. से जांच अवधि के दौरान कथित सामानों के भारित औसत निर्यात मूल्यों के आधार पर चीन जन.गण. के सभी निर्यातकों/उत्पादकों के लिए निर्यात कीमत निर्धारित की है । निर्यात कीमत में समुद्री भाड़े, समुद्री बीमा, कमीशन, अंतरदेशीय भाड़े, पत्तन व्यय तथा बैंक कमीशन को रिकार्ड में उपलब्ध सूचना के अनुसार समायोजित किया गया है । इस प्रकार निर्धारित निर्यात कीमत *** अम.डॉ. प्रति किग्रा. बनती है ।

च.5. इंडोनेशिया के निर्यातकों/उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य

33. प्राधिकारी ने इंडोनेशिया तथा चीन जन.गण. में विचाराधीन उत्पाद के ज्ञात निर्यातकों तथा उत्पादकों को प्रश्नावली भेजी । इस पर इंडोनेशिया के निम्नलिखित केवल दो उत्पादकों ने अपने उत्तर प्रस्तुत किए हैं :

1. मै. पी टी इंडो भारत रेयन
2. मै. पी.टी. साउथ पेसिफिक विस्कोस

इंडोनेशिया के सहयोगी निर्यातकों तथा उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण**पी.टी. साउथ पेसिफिक विस्कोस**

34. पी.टी. साउथ पेसिफिक विस्कोस, इंडोनेशिया ने उत्तर दिया है और सूचना उपलब्ध कराई है । प्रस्तुत उत्तर में कुछ कमियां पाई गई थीं और स्पष्टीकरण मांगे गए थे । कंपनी ने परिशिष्ट-1 में घरेलू बिक्री तथा परिशिष्ट-2 में भारत को किए गए निर्यातों के बारे में सूचना प्रस्तुत की है । आंकड़ों के अवलोकन से यह पता चलता है कि कंपनी की भारत औसत घरेलू बिक्री कीमत भारत औसत घरेलू उत्पादन लागत से कम है । प्रतिवादी की उत्पादन लागत की तुलना सौदेवार घरेलू बिक्री के साथ की गई है और यह पाया गया है कि ऋण लागतों में किए गए संशोधनों के कारण घरेलू बिक्रियों के ***% की तुलना में ***% घरेलू बिक्रियां लाभ में की गई हैं । इस प्रकार सामान्य मूल्य का निर्धारण लाभ योग्य घरेलू बिक्रियों के आधार पर किया गया है । कमीशन, बैंक प्रभारों एवं छूट के लिए किए गए समायोजनों की अनुमति दी जा रही है जैसा कि मौके पर सत्यापन के दौरान नोट किया गया है । इस प्रकार सामान्य मूल्य *** अम. डॉ. प्रति किग्रा. बनता है ।

पी.टी. इंडो भारत रेयन

35. इंडोनेशिया की पी.टी. इंडो भारत रेयन ने उत्तर दिया है और निर्धारित प्रपत्र में एवं ढंग से सूचना उपलब्ध कराई है । प्रतिवादी ने परिशिष्ट-1 में घरेलू बिक्री से संबंधित सूचना प्रस्तुत की है । प्रतिवादी ने परिशिष्ट 5 से 9 में उत्पादन लागत से संबंधित सूचना प्रस्तुत की है । प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रतिवादी ने अपनी घरेलू बिक्रियों पर समग्र आधार पर लाभ कमाया है । प्रतिवादी की उत्पादन लागत की तुलना सौदेवार घरेलू बिक्री के साथ की गई है और यह पाया गया है कि ***% घरेलू बिक्रियां लाभ में की गई हैं । इस प्रकार सामान्य मूल्य का निर्धारण लाभ योग्य घरेलू बिक्रियों के आधार पर किया गया है । परिवहन प्रभारों, आंतरिक बीमा छूट एवं ऋण लागत के लिए किए गए समायोजनों की अनुमति दी गई है जैसा कि मौके पर सत्यापन के दौरान नोट किया गया है । इस प्रकार सामान्य मूल्य *** अम. डॉ. प्रति किग्रा. बनता है ।

च.6 निर्यात कीमत**पी टी साउथ पेसिफिक विस्कोस**

36. प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत और प्राधिकारी द्वारा पुष्ट सूचना/आंकड़ों पर निर्यात कीमत के निर्धारण हेतु भरोसा किया जा रहा है । प्रतिवादी ने अंतर्देशीय परिवहन, समुद्री परिवहन, अंतर्राष्ट्रीय बीमा, ऋण लागत एवं बैंक प्रभारों के लिए समायोजनों का दावा किया है जिन्हें स्वीकार जा रहा है । जैसा कि सत्यापन के दौरान नोट किया गया है । इस प्रकार प्राधिकारी ने निर्यातक के लिए निर्यात कीमत *** अम.डॉ. प्रति किग्रा. निर्धारित की है ।

पी टी इंडो भारत रेयन

37. प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत और प्राधिकारी द्वारा पुष्ट सूचना/आंकड़ों पर निर्यात कीमत के निर्धारण हेतु भरोसा किया जा रहा है। प्रतिवादी ने अंतरराष्ट्रीय भाड़े, अंतरदेशीय परिवहन, अंतरराष्ट्रीय बीमा, आंतरिक बीमा एवं अन्य व्यय के लिए समायोजनों का दावा किया है जिन्हें स्वीकार किया जा रहा है जैसा कि मौके का सत्यापन के दौरान नोट किया गया है। इस प्रकार प्राधिकारी ने निर्यातक के लिए निर्यात कीमत *** अम.डॉ. प्रति किग्रा. निर्धारित की है।

इंडोनेशिया के असहयोगी निर्यातकों तथा उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य एवं निर्यात कीमत का निर्धारण

38. इंडोनेशिया के किसी अन्य निर्यातक तथा उत्पादक ने प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है। प्राधिकारी ने रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर उनके सामान्य मूल्य तथा निर्यात कीमत का निर्धारण किया है।

च.7. पाटन मार्जिन का निर्धारण

39. उपर्युक्तानुसार निर्धारित सामान्य मूल्य एवं निर्यात कीमत पर विचार करते हुए पाटन मार्जिन निम्नानुसार बनता है:

अम. डॉ. प्रति किग्रा.

	सामान्य मूल्य	निर्यात कीमत	पाटन मार्जिन	पाटन मार्जिन %
इंडोनेशिया				
मै. पी टी साउथ पेसेफिक विस्कोस	***	***	***	5-10 %
मै. पी टी इंडो भारत रेयन	***	***	***	5-10 %
ऊपर उल्लिखित दोनों कंपनियों को छोड़कर अन्य	***	***	***	30-35 %
चीन जन.गण.				
समस्त निर्यातक तथा उत्पादक	***	***	***	10-15 %

39.1 प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन जन.गण. और इंडोनेशिया से पाटन मार्जिन निर्धारित न्यूनतम सीमाओं से अधिक है।

छ. क्षति

छ.1 इंडियन स्पिनर्स एसोसिएशन, राजस्थान टैक्सटाइल्स मिल्स एसोसिएशन तथा पी.टी. साउथ पैसिफिक विस्कोस इंडोनेशिया सहित निर्यातकों/आयातकों तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

40. उन्होंने ये तर्क दिए हैं कि :-

- बाजार हिस्से में 2.3% की गिरावट बहुत ही कम है। यह समझने वाली बात है कि बाजार हिस्से में यह अल्प हानि अपूर्ण आंकड़ों के आधार पर है। किसी भी मामले में 6

माह की छोटी सी अवधि में बाजार हिस्से में करीब 2% की गिरावट, जिसमें से भी अधिकतर अवधि में काफी अधिक समस्याएं रही हैं, यदि इसमें से किसी बड़ी क्षति को निकाल दें तो यह क्षति का आधार नहीं हो सकता। इसके अलावा, भारत में मांग में क्षति जांच अवधि के दौरान 31813 मी.ट. तक की कमी आई है, जबकि निर्यात में कथित वृद्धि केवल 3977 मी.ट. है। तथापि, मांग में कमी के कारण याचिकाकर्ता की बिक्री में 27836 मी.ट. की गिरावट के शेष अंतर के कोई कारण नहीं हैं।

- जहां तक मांग में गिरावट के बावजूद आयात में वृद्धि का संबंध है, यह माना गया है कि आदेश काफी पहले किए गए थे, जिन्हें मांग में गिरावट के साथ रोका नहीं जा सकता था। अतः आयात में वृद्धि हुई।
- घरेलू उद्योग का उत्पादन और क्षमता उपयोग : यह कहना है कि विश्लेषण में पूर्णतया त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि इसमें इस तथ्य को शामिल नहीं किया गया कि याचिकाकर्ता ने 2008-09 के दौरान 25.30% वृद्धि करके अपनी संस्थापित क्षमता में वृद्धि की है। स्पष्टतः यह आशा नहीं की जा सकती कि नई क्षमता मौजूदा क्षमता के समान स्तरीय संचालन करेगी। इसके अलावा, यह प्रतीत होता है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मांग में कमी से निश्चय ही उत्पादन और अल्प जांच अवधि के दौरान क्षमता उपयोग में गिरावट आई है, जिसे भी नहीं लिया गया है।
- यह देखा जा सकता है कि इंडोनेशिया से कीमतों में कमी नहीं की गई है तथा चीन से की गई कटौती नगण्य है।
- वर्ष 2005-06 की जांच अवधि तथा 2008-09 के लिए प्रकाशित विवरणों के अनुसार याचिकाकर्ता के लिए विचाराधीन उत्पादन के लिए प्रयुक्त पूंजी पर प्राप्ति क्रमशः 43%, 17% तथा 23% है। उद्योग जांच अवधि सहित इन वर्षों के दौरान ऐसे ठोस वित्तीय निष्पादन के साथ क्षति का दावा नहीं कर सकता। यहां तक कि वित्त वर्ष 2008-09 के दौरान, जबकि अल्प जांच अवधि भी, विचाराधीन उत्पादन के लिए प्रयुक्त पूंजी पर प्राप्ति बढ़कर 23% हो गई है। जब किसी पूरे वित्त वर्ष की तरह किसी उचित अवधि के दौरान निष्पादन अनुकरणीय रहा हो तो निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा क्षति विश्लेषण के लिए किसी विशिष्ट अल्प अवधि को चुनकर निर्णय लिया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है।
- माने गए निर्यातों पर प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। यदि इन बिक्रियों पर सामान्य कीमत पर विचार किया गया होता तो वसूली में काफी परिवर्तन होगा।
- अंतिम निर्यातों के लिए घरेलू उद्योग द्वारा की गई बिक्री को, घरेलू उद्योग द्वारा घरेलू बिक्रियों में भी शामिल किया गया प्रतीत होता है।
- संबद्ध पक्षों को महत्वपूर्ण बिक्रियां की जा रही हैं; ऐसी बिक्रियों की अलग से जांच किए जाने की जरूरत है और उसका अगोपनीय भाग दिया जाए।
- मांग में कमी आई है, जिससे घरेलू उद्योग प्रभावित हुआ है। अतः कथित पाटित आयात घरेलू उद्योग की क्षति के लिए जिम्मेदार नहीं है।
- घरेलू उद्योग द्वारा कीमतों में कमी : याचिकाकर्ता ने याचिका में यह कहा है कि "विदेशी उत्पादकों द्वारा कीमतों में कमी करने की पेशकश को देखते हुए घरेलू उद्योग को कीमतों में अनेक प्रकार के संशोधन करने पड़े।" तथापि, यह प्रतीत होता है कि घरेलू उद्योग द्वारा कीमतों में कमी करने की पेशकश से संबद्ध देशों द्वारा संबद्ध वस्तुओं के कथित पाटन से कोई संबंध नहीं है। निस्संदेह यह स्पष्ट है कि कीमतों में निरंतर परिवर्तन, यदि कोई हो,

उपर्युक्त कारणों से किए गए थे न कि विस्कोस स्टेपल फाइबर के कथित पाटन के कारण, जैसा कि याचिकाकर्ता द्वारा दावा किया गया है ।

- याचिकाकर्ता की कीमत संबंधी नीति : यह प्रतीत होता है कि घरेलू उद्योग माने गए निर्यातों में अपनी आपूर्तियों के लिए छूट के रूप में प्रोत्साहन की पेशकश कर रहे हैं । याचिकाकर्ता की कीमत संबंधी नीति के अनुसार, माने गए निर्यातों में उनकी आपूर्ति के लिए यदि कुछ शर्तें पूरी की जाती हैं तो ही छूट दी जाती है । अतः योजना से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता उपभोक्ताओं को संबद्ध वस्तुओं की मूल कीमत से छूट के रूप में प्रोत्साहन योजनाएं पेश कर रहा है । प्राधिकारी का मानना है कि यदि सामान्य घरेलू बिक्री के लिए उपभोक्ताओं हेतु संबद्ध वस्तुओं की पेशकश की गई हो तो याचिकाकर्ता द्वारा प्रभारित कीमत अधिक होती । यह पाया गया है कि समझे गए निर्यातों के लिए आपूर्तियों हेतु प्रभारित कीमतें घरेलू बिक्रियों के लिए प्रभारित कीमतों से काफी कम हैं । इसे याचिकाकर्ता की कीमत संबंधी सूची से देखा जा सकता है । अतः कीमत संबंधी नीति और घरेलू उद्योग की नीति स्पष्ट है कि अंतिम निर्यातों के लिए उपभोक्ताओं को की गई कुछ बिक्रियां भी क्षति विश्लेषण के प्रयोजन से घरेलू बिक्रियों में शामिल की गई हैं । क्षति विश्लेषण के लिए ज्ञात निर्यात बिक्रियों को शामिल करना पाटनरोधी नियमों व विनियमों के अनुकूल नहीं है । यह देखा जा सकता है कि याचिकाकर्ता को इस बात की पूरी जानकारी है कि संबद्ध समान अंतिम निर्यातों के लिए हैं और इसीलिए वह अलग कीमत संबंधी नीति का अनुसरण कर रहा है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि निर्यात बाजार को हानि तो नहीं हो रही है । उसका घरेलू बाजार में अपने निष्पादन से कोई संबंध नहीं है, जो कानूनन अपेक्षित है । घरेलू उद्योग कथित पाटन के अंतर्गत क्षति का सहारा नहीं ले सकता, जबकि कथित क्षति उसकी अपनी कीमत संबंधी नीतियों के कारण हुई हो । अतः कथित पाटन और याचिकाकर्ता की क्षति के बीच कारणात्मक संबंध का स्पष्ट अभाव है ।
- तर्क यह भी है कि घरेलू उद्योग संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के कथित पाटन के कारण लाभ में कमी आने के कारण क्षति से प्रभावित हुआ है । विभिन्न वार्षिक रिपोर्टों और घरेलू उद्योग की निष्पादन समीक्षा का ध्यानपूर्वक विश्लेषण यह दर्शाता है कि कंपनी को कम लाभ का मुख्य कारण निविष्टि लागतों में वृद्धि, कम मात्रा तथा कम मार्जिन का होना है । इसके अलावा, घरेलू उद्योग द्वारा प्रफोर्मा IV क में किए गए अनुरोध से यह स्पष्ट है कि ब्याज और लागत का मूल्यहास घटक काफी अधिक प्रतीत होता है, जो कम लाभ के कारणों में से एक कारण हो सकता है । यह बिल्कुल स्पष्ट है कि यदि यह मान भी लिया जाए कि घरेलू उद्योग अपने लाभ में कुछ अस्थायी कमी आने से प्रभावित हुआ है तो भी उसे संबद्ध सामानों के कथित पाटन के कारण नहीं माना जा सकता ।
- सीमित परिदृश्य के बावजूद घरेलू उद्योग ने मार्च, 2008 में अपनी क्षमता में विस्तार किया । किसी औद्योगिक इकाई के लिए प्रचालन की शुरुआत में ही क्षमता का वही स्तर प्राप्त करना संभव नहीं होता है ।
- बिक्री मात्रा में गिरावट आई जिसकी वजह आरोपित पाटन नहीं था ।

- घरेलू उद्योग द्वारा संबद्ध वस्तु के आरोपित पाटन तथा वैश्विक मंदी के बावजूद परियोजना का विस्तार जारी है। अतः जहां तक निवेश एवं विस्तार कार्यक्रम का संबंध है, घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है।
- किसी वास्तविक क्षति के खतरे के बारे में कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है।
- घरेलू उद्योग एक ऐसी कीमत नीति का पालन करता है जिसके जरिए वह पर्याप्त रिबेट प्रदान करता है। निर्दिष्ट प्राधिकारी को घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बारे में कोई दावा स्वीकार करने से पूर्व कीमत नीति का विश्लेषण करना चाहिए।
- इंडोनेशिया से अधिकांश आयात अग्रिम लाइसेंस पर किए जाते हैं।
- आरोपित पाटन तथा घरेलू उद्योग को क्षति के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है।
- याचिकाकर्ता द्वारा माने गए निर्यात आधार पर घरेलू बाजार में भारी मात्रा में बिक्री की जा रही है जिस पर याचिकाकर्ताओं द्वारा अत्यधिक छूट प्रदान की जा रही है। ये बिक्रियां घरेलू बिक्रियां नहीं हैं और इन्हें वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ घरेलू बिक्री से अलग रखा जाना चाहिए।
- कंपनी द्वारा घरेलू बाजार में होने वाली बिक्री में भारी छूट दी जा रही है जो याचिकाकर्ताओं की कीमत सूची से ही स्पष्ट हो जाती है। घरेलू उद्योग को क्षति यदि कोई हो, उसकी खुद की कीमत नीति के कारण हुई है न कि आरोपित पाटन के कारण।
- रोजगार में कोई क्षति नहीं हुई है क्योंकि उसका स्तर वस्तुतः वही है।
- मजदूरी और उत्पादन : चूंकि प्रति व्यक्ति मजदूरी के लिए कोई सूचना नहीं दी गई है, अतः हम यह अनुमान लगाते हैं कि इसमें कोई क्षति नहीं हुई है। उत्पादन के लिए यह कहना है कि यदि अन्य कारणों से उत्पादन में गिरावट आती है और उत्पादकता को प्रति व्यक्ति उत्पादन के रूप में वर्णित किया जाता है तो गिरावट की प्रवृत्ति दिखाई देगी लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह भी कहना है कि यह कारक श्रम में अत्यधिक अस्थिरता होने पर ही संगत है, जो भारत के मामले में सत्य नहीं है।
- आरोपित पाटन और घरेलू उद्योग की क्षति के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है। याचिकाकर्ता को क्षति अधिकतर स्वयं के कारण अथवा स्पष्ट रूप से पाटन से इतर अन्य कारकों के कारण थी। घरेलू उद्योग ने ही अपनी वार्षिक रिपोर्ट अथवा विभिन्न निष्पादन समीक्षा रिपोर्टों में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि उत्पादन, बिक्री तथा लाभ में हास, अल्प मांग, मौजूदा वैश्विक मंदी के साथ-साथ निविष्टि लागतों में अचानक वृद्धि होने तथा भारतीय रुपया कमजोर होने के कारण है।

घरेलू उद्योग के अनुरोध

41. घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि:

- प्रत्येक संबद्ध देश से पाटन मार्जिन तथा प्रत्येक संबद्ध देश से निर्यात की मात्रा निर्धारित सीमा से अधिक है ।
- आयातों के प्रभावों का संचित मूल्यांकन उपयुक्त है क्योंकि संबद्ध देशों से निर्यात की प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग द्वारा पेश किए गए ऐसे ही समान वस्तु के साथ है ।
- ऐसे भी आम उपभोक्ता/पक्ष हैं, जो विभिन्न स्रोतों से आयातित सामग्रियों तथा घरेलू सामग्रियों का उपयोग करते हैं । आयातित और घरेलू सामग्री का उपयोग बदल-बदल कर किया जा रहा है और घरेलू उत्पाद तथा आयातित उत्पाद तथा परस्पर आयातित उत्पाद के बीच प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा है ।
- प्रत्येक संबद्ध देश से निर्यात का बाजार हिस्सा न्यूनतम से अधिक है । प्रत्येक संबद्ध देश से आयात की मात्रा अत्यधिक है ।
- संबद्ध देशों से घरेलू उत्पादक और निर्यातक एक से उत्पाद समान श्रेणी के उपभोक्ताओं को बेचते हैं और दोनों ही उसी बाजार में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं । उपभोक्ता दोनों का ही बदल-बदल कर प्रयोग कर रहे हैं ।
- विचाराधीन उत्पाद की मांग 2007-08 तक बढ़ रही थी । तथापि, इसमें जांच अवधि में गिरावट (आनुपातिक आधार पर) आई । हालांकि, जब विचाराधीन उत्पाद के लिए मांग में जांच अवधि में गिरावट दर्शाई गई है, तो आयात की मात्रा में 50% से अधिक (आनुपातिक आधार पर) वृद्धि हुई है । मांग में गिरावट का प्राकृतिक प्रभाव आयात के साथ-साथ आनुपातिक आधार पर भी पड़ना चाहिए था । तथापि, विदेशी उत्पादकों द्वारा पाटित कीमतों की पेशकश के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि विचाराधीन उत्पाद की मांग में कमी आई लेकिन आयात की मात्रा में वृद्धि हुई ।
- संबद्ध देशों से आयात में निरपेक्ष रूप से काफी वृद्धि हुई है ।
- भारत में संबद्ध सामानों के कुल आयात में संबद्ध देशों के आयात में अत्यधिक वृद्धि हुई है ।
- भारत में उत्पादन के संबंध में आयात में अत्यधिक वृद्धि हुई है ।
- भारत में खपत के संबंध में आयात में अधिक वृद्धि हुई है ।
- विदेशी उत्पादकों द्वारा कीमतों की प्रस्तावित कमी को देखते हुए घरेलू उद्योग को कीमतों के संबंध में अनेक संशोधन करने पड़े ।
- यदि घरेलू उद्योग ने कीमतों में कमी करके बचावपरक दूरदर्शी कार्रवाई नहीं की होती तो आयात मौजूदा मात्रा से बहुत ही अधिक होता ।
- देश में क्षमता और मांग को देखते हुए आयात में वृद्धि का स्थापित घरेलू उद्योग पर अत्यधिक गहृत प्रभाव पड़ता ।

- घरेलू उद्योग के समक्ष बाजार में विदेशी उत्पादकों द्वारा प्रस्तावित कीमतों के अनुसार अपनी कीमतें रखने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है। आयात की वर्तमान में बढ़ती मात्रा को घरेलू उद्योग द्वारा किए गए इन कीमत संशोधन उपायों के आलोक में देखा जा सकता है।
- यह देखा जाएगा कि संबद्ध देशों से आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की शुद्ध बिक्री वसूली से कम है, जिससे यह बात स्पष्ट होती है कि आयात से घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में कटौती हो रही है।
- क्षति अवधि के दौरान उत्पादन की लागत में वृद्धि हो रही थी, बिक्री कीमतों में 2007-08 तक वृद्धि हुई लेकिन जांच अवधि में कमी आई।
- घरेलू उद्योग बिक्री कीमतों में अत्यधिक कटौती करने पर विवश हुआ है।
- 2007-08 तक बिक्री और उत्पादन तथा क्षमता उपयोग में सुधार हो रहा था, लेकिन बाद में जांच अवधि में गिरावट आ गई।
- सकल घरेलू बिक्रियों पर लाभ, निवेश पर प्राप्ति तथा नकद लाभ में 2007-08 तक सुधार हो रहा था, लेकिन संबद्ध देशों से पाटित आयातों में वृद्धि तथा कटौती कीमतों पर बिक्री के प्रस्तावों के कारण जांच अवधि में एकाएक कमी आ गई।
- पूंजी और नकद लाभ पर प्राप्ति लाभ की प्रवृत्ति ही दर्शाती है। पूंजी पर प्राप्ति ऐसी स्थिति में निचले स्तर पर है, जहां पर कि घरेलू उद्योग के कुछ निवेश स्पष्टतः पुराने हैं तथा ज्यादातर परिस्थितियों के अब तक मूल्य घट चुके हैं।
- लाभप्रदता में इतनी गिरावट रह है कि कंपनी को जांच अवधि की अंतिम तिमाही में अत्यधिक न्यून नकद लाभ हुआ।
- घरेलू उद्योग ने वास्तव में जांच अवधि में बिचाराधीन उत्पादों की बिक्री तथा उत्पादन में वित्तीय घाटे का सामना किया है। दूसरे शब्दों में एक ओर जहां अन्य निविष्टियां यहां तक कथित मंदी की अवधि के दौरान भी लाभ कमाती रही, लेकिन पाटन इतना अधिक था कि उत्पादकों ने उत्पादन लागत से भी कम वी एस एफ कीमत करना शुरू कर दिया।
- घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा घट गया और संबद्ध आयात में वृद्धि हो गई। घरेलू उद्योग ने संबद्ध देशों से आयात के लिए बाजार हिस्सा खो दिया।
- घरेलू उद्योग द्वारा प्रभावित कीमत कटौतियों के साथ-साथ घटे हुए बाजार हिस्से का वर्तमान स्तर देखा जा सकता है। यदि घरेलू उद्योग ने अपनी कीमतें अपने लाभ को बचाने के लिए उसी स्तर पर रखी होती तो उसे अत्यधिक बाजार घाटा उठाना पड़ता।
- घरेलू उद्योग का मालसूची स्तर 2007-08 तक गिरा है और उसके बाद पुनः बढ़ा है। घरेलू उद्योग के साथ मालसूची में अत्यधिक वृद्धि हुई है। वास्तव में, मालसूचियों में इतनी अधिक वृद्धि थी कि याचिकाकर्ता को उत्पादन कटौती का सहारा लेने का निर्णय करना पड़ा।
- घरेलू उद्योग की वृद्धि 2007-08 तक सकारात्मक थी। आयात से बढ़ती प्रतिस्पर्धा के साथ ही जांच अवधि में वृद्धि नकारात्मक हो गई। उत्पादन, बिक्री, क्षमता उपयोग, बाजार हिस्से, मालसूचियों के संबंध में वृद्धि 2007-08 तक सकारात्मक थी जो जांच अवधि में नकारात्मक हो गई। इसके बावजूद, मालसूचियों में पर्याप्त वृद्धि हुई। मूल्य मानदंडों में

लाभ, निवेश पर आय तथा नकद प्रवाह में वृद्धि 2007-08 तक सकारात्मक थी और जांच अवधि में यह नकारात्मक हो गई ।

- इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने जांचोत्तर अवधि में हुए आयातों की सौदेवार सूचना एकत्र की है (नीचे दी गई तालिका) । यह देखा जा सकता है कि संबद्ध देशों से कीमतों में आगे और गिरावट आई है ।

	जन.-मार्च 09 अम.डॉ. किग्रा.	अप्रैल-जून 09 अम.डॉ. किग्रा.
चीन जन.गण.	1.57	1.57
इंडोनेशिया	1.79	1.65

- जांचोत्तर अवधि में संबद्ध देशों से निर्यात कीमत में आगे और गिरावट आई है । वस्तुतः ये ऑर्डर जांच अवधि की समाप्ति पर प्रस्तुत किए जाते हैं और इसलिए इन्हें प्रतिवादी निर्यातकों के प्रश्नावली के उत्तरों में शामिल किया जाना चाहिए ।
- वर्ष 2007-08 और जांच अवधि के बीच निर्यात कीमत में वृद्धि-वर्ष 2007-08 की तुलना में जांच अवधि में कच्ची सामग्री की लागत में गतिविधि जैसा कि निम्नलिखित तालिका से देखा जाएगा । इससे निर्यात कीमत में वृद्धि हुई ।

रू./किग्रा.	2007-08	जांच अवधि	परिवर्तन
कच्ची सामग्री	***	***	12.6
आयात कीमत			
चीन जन.गण.	107.09	94.13	-12.96
इंडोनेशिया	94.55	98.47	3.92

यह देखा जा सकता है कि यद्यपि जांच अवधि में कच्ची सामग्री की लागत में 23.48% की वृद्धि हुई तथापि, चीन से निर्यातित कीमत में 12.10% की गिरावट आई जबकि इंडोनेशिया के मामले में इसमें केवल 4.14% की वृद्धि हुई है ।

- नियमों के अंतर्गत कारणात्मक संबंध की अपेक्षा- ऐसा प्रतीत होता है कि हितबद्ध पार्टियां नियमों की व्याख्या इस तरीके से कर रही हैं जिससे यह पता चले कि क्षति का एकमात्र कारण पाटित आयात होना चाहिए । लेकिन, जरूरत यह नहीं है । नियमों के अंतर्गत क्षति के प्रमुख कारणों में से एक कारण पाटित आयात होना चाहिए । यह तथ्य कि घरेलू उद्योग अपने उत्पाद की कीमत आयात कीमत के अनुसार तय करता है और यह तथ्य कि घरेलू उद्योग कीमतों में अधोगामी संशोधन करने के लिए बाध्य हुआ है और वह भी कई बार सामान्य से अधिक सीमा तक, से इस बात की पुष्टि होती है कि पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है ।

42. जहां तक मानी गई निर्यात बिक्रियों और ऐसी बिक्रियों पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त पर्याप्त छूट से संबंधित मुद्दे का संबंध है, घरेलू उद्योग ने निम्नानुसार उल्लेख किया है :

- घरेलू उद्योग एक सुस्थापित कीमत नीति का अनुसरण करता है। घरेलू उद्योग "कीमत सूची" के अनुसार उत्पाद की निकासी और बिक्री करता है। प्रत्येक बिक्री सौदे के लिए कीमत पर बातचीत नहीं की जाती है। घरेलू उद्योग भाव दरों, कीमत वार्ताओं, खरीद एवं ऑर्डर के निष्पादन का उल्लेख करते हुए व्यापार पूछताछों का उत्तर देने की प्रणाली का अनुसरण नहीं करता है। घरेलू उद्योग "कीमत सूची" की घोषणा करता है और उसके बाद सामग्री की बिक्री घोषित कीमत सूची के आधार पर करता है। आपवादित परिस्थितियों को छोड़कर कंपनी द्वारा की गई सभी बिक्रियां कीमत सूची के अनुसार की गई हैं, जिसके साथ कीमत में संशोधन करने के बारे में विपणन कार्यकारी के प्रचालन स्तर पर कुछ या कुछ भी नहीं विवेकाधिकार हैं।
- घरेलू उद्योग की सूचीगत कीमत का उपयोग घरेलू उद्योग की कीमत के साथ आयातित उत्पाद की कीमत के साथ करने के लिए किया जाना चाहिए। ऐसी किसी स्थिति में जिसमें कंपनी प्रत्येक बार कीमत पर बातचीत करने के बाद ग्राहक-दर-ग्राहक अलग-अलग कीमत पर अलग-अलग ग्राहकों को सामग्री की बिक्री करती है, वहां ऐसा करना संगत और उचित होगा कि अवधि के दौरान बेची गई मात्रा की भारित औसत निर्यात कीमत का निर्धारण किया जाए। तथापि, ऐसी किसी स्थिति में जहां कंपनी अपने उत्पाद की बिक्री पूर्व निर्धारित कीमत पर करती है, सार्वजनिक कीमत सूचियों की घोषणा करती है और जहां ऐसी कीमत सूचियों की घोषणा अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर विचार करने के बाद की जाती है, वहां आयातित एवं घरेलू उत्पाद के बीच कीमत की तुलना ऐसी कीमत सूचियों के आधार पर की जानी चाहिए। घरेलू उद्योग ने यह दोहराया है कि बिक्री कीमतें ग्राहकों के साथ अलग-अलग नहीं रही हैं और इसलिए किसी खास अवधि में बेची गयी मात्रा की भारित औसत बिक्री कीमत का निर्धारण करने की कोई जरूरत नहीं है।
- कीमत का निर्धारण वैज्ञानिक और पारदर्शी ढंग से किया जाता है। कीमत निर्धारण का आधार प्रचलित अंतर्राष्ट्रीय कीमत होता है। प्रचलित अंतर्राष्ट्रीय कीमतों और विभिन्न कारकों पर विचार करते हुए कंपनी अपनी मूलभूत कीमत निर्धारित करती है जिन्हें ऐसे अंतरों के आलोक में देखा जाना चाहिए जो अलग-अलग देशों में विद्यमान हैं (विनिमय दर, सीमाशुल्क आदि के अनुसार)।
- कंपनी ने कुछेक श्रेणी की बिक्री का उल्लेख "माने गए निर्यातों" के रूप में किया है। विरोधी हितबद्ध पार्टियां इस बात से असहमत नहीं हैं कि माने गए निर्यात घरेलू बिक्री का भाग नहीं होना चाहिए। तथापि, महज इस वजह से कि कंपनी ने कुछेक बिक्रियों को ही माने गए निर्यातों के रूप में निर्दिष्ट किया है, ये बिक्रियां माने गए निर्यात नहीं बन जाती हैं।
- माने गए निर्यातों को विदेश व्यापार नीति में परिभाषित किया गया है। मानी गई निर्यात बिक्रियों के अनिवार्य घटक निम्नानुसार हैं :

"मुख्य/उप संविदाकारों द्वारा माल की आपूर्तियों की निम्नलिखित श्रेणियों को एफटीपी के अंतर्गत "माने गए निर्यात" माना जाता है, बशर्ते माल का विनिर्माण भारत में किया गया हो":

- (क) वार्षिक जरूरत/डीएफआईए हेतु अग्रिम प्राधिकार/अग्रिम प्राधिकार पर माल की आपूर्ति ।
- (ख) ईओयू या एसटीपी या ईएचटीपी या बीटीपी को माल की आपूर्ति
- (ग) ईपीसीजी स्कीम के अंतर्गत प्राधिकार पत्र धारण कर्ताओं को पूंजीगत माल की आपूर्ति ।
- (घ) आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा बहु पक्षीय या द्विपक्षीय एजेंसियों/निधियों की प्रक्रियाओं के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा बोली (आईसीबी) के अंतर्गत इन एजेंसियों/निधियों द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं को माल की आपूर्ति जब विधिक करारों में सीमाशुल्क को शामिल किए बिना निविदा के मूल्यांकन का प्रावधान हो ।
- (ङ) आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा आईसीबी के अंतर्गत अधिसूचित बहुपक्षीय या द्विपक्षीय एजेंसियों/निधियों की प्रक्रियाओं के अनुसार आईसीबी के अंतर्गत इन एजेंसियों/निधियों द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं को माल तथा उपकरणों (आद्योपांत संविदाओं की एकल जिम्मेवारी) की आपूर्ति एवं प्रतिष्ठापन, जिनके लिए बोलियां आमंत्रित की गई हों और उनका मूल्यांकन विदेश में विनिर्मित माल की डिलीवरीशुदा शुल्क संदत्त (डीडीपी) कीमत के आधार पर किया गया हो ।
- (च) असंयोजित/वियोजित स्थिति में पूंजीगत माल सहित पूंजीगत माल एवं संयंत्र, मशीनरी, सहायक सामग्री, औजार, सांचों एवं ऐसी वस्तुओं, जिनका उपयोग वाणिज्यिक उत्पादन के चरण तक प्रतिष्ठापन प्रयोजनों में किया जाता है तथा उर्वरक संयंत्रों को एफओआर मूल्य के 10% तक कलपुर्जों की आपूर्ति ।
- (छ) किसी परियोजना या किसी परियोजना के लिए माल की आपूर्ति, जिसके संबंध में वित्त मंत्रालय ने अधिसूचना द्वारा शून्य सीमाशुल्क पर ऐसे माल के आयात की अनुमति दी हो ।
- (ज) उपर्युक्त (च) में असम्मिलित विद्युत परियोजनाओं और तेलशोधन शालाओं को माल की आपूर्ति ।

- (झ) 100% ईओयू (घरेलू फ्रेट कंटेनर-विनिर्माता) द्वारा समुद्री भाड़ा कंटेनरों की आपूर्ति बशर्ते उक्त कंटेनर छः माह की अवधि के भीतर या सीमाशुल्क द्वारा अनुमत आगे की अवधि के भीतर भारत से निर्यात कर दिए गए हों ।
- (ज.) यू एन एजेंसियों द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं को आपूर्ति; और
- (ट) आईसीबी के विपरीत प्रविस्पर्धी बोली के जरिए नाभिकीय विद्युत परियोजनाओं को माल की आपूर्ति ।

- चूंकि भारत सरकार मानी गई निर्यात बिक्री को निर्यात बिक्री मानती है तथा यह और कि क्षति का निर्धारण घरेलू बिक्री के लिए किया जाना चाहिए । इसलिए विरोधी हितबद्ध पार्टियों ने सही ढंग से यह दावा किया है कि मानी गई निर्यात बिक्रियों को घरेलू बिक्री से अलग नहीं रखा जाना चाहिए ।
- घरेलू उद्योग द्वारा की गई घरेलू बिक्रियां मानी गई निर्यात बिक्री के रूप में पात्र नहीं हैं, यद्यपि उनके द्वारा बाजार में माने गए निर्यातों की शब्दावली का उपयोग किया जा रहा है । वस्तुतः उपभोक्ता निर्यात लाभों का दावा सबके द्वारा किए गए निर्यातों के बारे में करते हैं और घरेलू उद्योग महज इस कारण से "माने गए निर्यात" शब्दावली का उपयोग करता है कि इस फाइबर का उपयोग ऐसे उत्पाद में किया गया है, जिसका निर्यात किया गया है । तथापि, समस्त निर्यात लाभ उपभोक्ताओं द्वारा लिए गए हैं न कि घरेलू उद्योग द्वारा । यदि ये मानी गई निर्यात बिक्रियां होतीं, तो घरेलू उद्योग विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत प्रदत्त विभिन्न लाभों का पात्र होता ।
- अतः यह अनुरोध किया जाता है कि ये बिक्रियां मानी गई निर्यात बिक्रियां नहीं हैं, जैसा कि विरोधी हितबद्ध पार्टियों ने समझा है अपितु, ये केवल घरेलू बिक्रियां हैं । अतः इन बिक्रियों को "घरेलू बिक्री" शीर्ष के अंतर्गत उचित ढंग से शामिल किया गया है ।

छ.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

43. प्राधिकारी ने हितबद्ध पार्टियों द्वारा किए गए अनुरोधों को नोट किया है जिनमें घरेलू उद्योग का यह तर्क भी शामिल है कि उन्होंने तथाकथित "माने गए निर्यातों" के लिए विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत कोई लाभ नहीं लिया है । अतः ऐसी बिक्रियों को घरेलू बिक्री माना जाना चाहिए । तथापि, इन दावों और प्रतिदावों की प्रति जांच आगे की जाने वाली जांच और मौके पर सत्यापन की कार्यवाही के दौरान की जाएगी ।

43.1. प्राधिकारी ने हितबद्ध पार्टियों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों को दर्ज किया जाए और क्षति विश्लेषण निम्नानुसार किया है:

43.2 पाटनरोधी नियमों के अनुबंध II में यह अपेक्षित है कि क्षति के निर्धारण में (क) पाटित आयातों की मात्रा और समान उत्पाद के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव

और ; (ख) पाटित आयातों के मात्रात्मक प्रभाव के संबंध में ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातकों के परिणामी प्रभाव, दोनों की तथ्यपरक जांच शामिल होगी । पाटित आयातों की मात्रा के प्रभाव की जांच करते समय उक्त प्राधिकारी इस बात पर विचार करेंगे कि क्या पाटित आयातों में समग्र रूप में या भारत में उत्पादन या खपत की तुलना में पर्याप्त वृद्धि हुई है । जहां तक कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव का संबंध है, निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात पर विचार करेंगे कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में अत्यधिक कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से कीमतों में अन्यथा अत्यधिक गिरावट आई है या कीमत में होने वाली उस वृद्धि में रूकावट आई है, जो अन्यथा पर्याप्त स्तर तक बढ़ गई होती ।"

43.3 जहां तक घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव का संबंध है, पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II के पैरा (iv) निम्नानुसार उल्लेख है :

"संबंधित घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में बिक्री लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय या क्षमता उपयोग में स्वाभाविक और संभावित गिरावट, सहित उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी संगत आर्थिक कारकों और संकेतकों; घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकद प्रवाह पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता को प्रभावित करने वाले कारकों का मूल्यांकन शामिल होगा ।"

43.4 प्राधिकारी ने हितबद्ध पार्टियों द्वारा उपलब्ध कराए गए तथ्यों और दिए गए तर्कों को ध्यान में रखते हुए क्षति मापदंडों की तथ्यपरक जांच की है ।

संचयी निर्धारण

44. चूंकि वर्तमान जांच में शामिल देश एक से अधिक हैं, इसलिए प्राधिकारी ने इस बात की जांच की है कि क्या संचयी निर्धारण हेतु शर्तों की प्रथम दृष्टया पूर्ति होती है या नहीं । प्राधिकारी ने यह पाया है कि :

- i. प्रत्येक संबद्ध देश से पाटन मार्जिन निर्धारित सीमाओं से अधिक है;
- ii. प्रत्येक संबद्ध देश से आयात की मात्रा निर्धारित सीमा से अधिक है;
- iii. आयातों के प्रभाव का संचयी निर्धारण उचित है क्योंकि संबद्ध देशों से हुए निर्यात भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत समान वस्तुओं के साथ सीधे प्रतिस्पर्धा करते हैं । ऐसा इस तथ्य से स्पष्ट हो जाता है कि घरेलू उत्पाद और आयातित उत्पाद निम्नलिखित आधार पर समान वस्तुएं हैं :- प्रत्येक संबद्ध देश से हुए आयात काफी अधिक रहे हैं; भारतीय उत्पादकों द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से आयातित वस्तु में प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा है; सामान्य पार्टियां आयातित सामग्री और घरेलू सामग्री का उपयोग कर रही हैं; भारतीय उत्पादक/ग्राहक घरेलू सामग्री तथा आयातित सामग्री का उपयोग कर रहे हैं ; संबद्ध देशों के निर्यातकों और

आवेदक ने एक ही श्रेणी के ग्राहकों को एक समान अवधि में एक समान उत्पाद की बिक्री की है आदि ।

44.1 उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी यह मानते हैं कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति का संचयी निर्धारण करना उचित होगा ।

मांग एवं बाजार हिस्सा:-

45. देश में उत्पाद की मांग का निर्धारण घरेलू उत्पादकों की घरेलू बिक्री और सभी स्रोतों से हुए आयातों की मात्रा के रूप में किया गया है ।

मी. ट. में

	2005-06	2006-07	2007-08	अप्रैल-जून 08	जुलाई-दिसं. 08 (जांच अवधि)	अप्रैल-जून 08 वार्षिकीकृत	जांच अवधि वार्षिकीकृत
घरेलू उद्योग की बिक्री	223,147	226,178	237,395	49,784	100,925	199,136	201,850
सूचीबद्ध	100	101	106	89	90	89	90
भारत में आयात	198	6,774	6,842	1,890	6,329	7,561	12,658
सूचीबद्ध	100	3,415	3,450	3,812	6,382	3,812	6,382
मांग	223,345	232,952	244,237	51,674	107,254	206,697	214,508
सूचीबद्ध	100	104	109	93	96	93	96
मांग में बाजार हिस्सा							
संबद्ध देश	0.06%	1.34%	2.78%	3.66%	5.90%	3.66%	5.90%
अन्य देश	0.03%	1.57%	0.03%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
घरेलू उद्योग	99.91%	97.09%	97.20%	96.34%	94.10%	96.34%	94.10%

45.1 यह नोट किया जाता है कि विचाराधीन उत्पाद की मांग में वर्ष 2007-08 तक वृद्धि हो रही थी । तथापि, उसमें अप्रैल-जून, 08 की अवधि और जांच अवधि के दौरान गिरावट (आनुपातिक आधार पर) आई है । यह भी नोट किया जाता है कि यद्यपि जांच अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद की मांग में गिरावट देखी गई है, तथापि मात्रा में पर्याप्त वृद्धि (आनुपातिक आधार पर हुई है) । कुछेक हितबद्ध पार्टियों ने यह तर्क दिया है कि भारत में उत्पाद की मांग में गिरावट आई है और इसलिए घरेलू उद्योग को क्षति, यदि कोई हो, आरोपित आयातों के कारण नहीं हुई है । तथापि, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि मांग में गिरावट के प्रभाव के परिणामस्वरूप आयातों में अनुपातिक आधार पर गिरावट आई होगी । तथापि, यह देखा जाता है कि संबद्ध देशों से पाटित कीमतों पर संबद्ध वस्तु के आयातों के कारण प्रत्यक्षतः ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है जिसके अंतर्गत विचाराधीन उत्पाद की मांग में गिरावट आई है और आयातों में पर्याप्त वृद्धि हुई है ।

45.2 आयातों में वृद्धि का यह प्रभाव आयातों के बाजार हिस्से में ही दृष्टिगोचर होता है । जांच अवधि के दौरान संबद्ध देशों से पाटित आयातों का बाजार हिस्सा काफी अधिक रहा है ।

आयात की मात्रा और बाजार हिस्सा

46. संबद्ध वस्तु के आयातों और बाजार हिस्सों का ब्यौरा निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

	2005-06	2006-07	2007-08	अप्रैल-जून 08	जुलाई- दिसं. 08 (जांच अवधि)	अप्रैल-जून 08 वार्षिकीकृत	जांच अवधि वार्षिकीकृत
संबद्ध देशों से आयात	125	3,121	6,779	1,890	6,329	7,561	12,658
अन्य देशों से आयात	73	3,653	62	-	-	-	-
कुल आयातक	198	6,774	6,841	1,890	6,329	7,561	12,658
निम्न के संबंध में पाटित आयात -							
- भारतीय उत्पादन	0.05%	1.26%	2.44%	3.27%	10.05%	3.27%	10.05%
- भारतीय खपत	0.06%	1.34%	2.78%	3.66%	5.90%	3.66%	5.90%
घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा	99.91%	97.09%	97.20%	96.34%	94.10%	96.34%	94.10%

46.1 यह देखा गया है कि:-

- आयातों में समग्र रूप में पर्याप्त वृद्धि प्रदर्शित हुई है ।
- आयातों में भारत में उत्पादन और खपत की तुलना में वृद्धि हुई है ।
- जहां संबद्ध देशों के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है, वहीं घरेलू उद्योग के हिस्से में गिरावट आई है । इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि घरेलू उद्योग पर आयातों का प्रभाव प्रतिकूल रहा है ।

इस तर्क के संबंध में कि बाजार हिस्से में गिरावट विशेष रूप से बृहत आर्थिक समस्याओं को देखते हुए कोई खास नहीं है, प्राधिकारी मानते हैं कि उस मात्रा के संबंध में कोई विधिक निर्धारण नहीं है जहां तक संकेतक इस निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए विकृति दर्शाएं कि घरेलू उद्योग को क्षति हुई है अथवा क्षति नहीं हुई है । विधिक प्रावधानों के अनुसार न तो पाटनरोधी नियमावली और न ही डब्ल्यू टी ओ के पाटनरोधी करार में मांग में बाजार हिस्से के आधार पर कोई निर्धारित न्यूनतम सीमा संबंधी मापदंड है । कुछ प्राधिकारी आयातों के 1% बाजार हिस्से को अधिक हिस्सा मानते हैं । यदि किसी देश विशेष से आयातों का 1% बाजार हिस्सा "काफी अधिक" माना जा सकता है तो बाजार हिस्से में 2.3% की गिरावट को कम नहीं माना जा सकता है ।

तथापि, बृहत आर्थिक समस्याओं (हितबद्ध पक्षकार स्पष्ट रूप से वैश्विक मंदी का हवाला दे रहे हैं) के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऐसे कारकों की मौजूदगी पाटन को उचित नहीं ठहराती है और घरेलू उद्योग को हुई परिणामी क्षति का समाधान करने का निवारण नहीं करती है। ऐसी स्थिति में जहां उत्पाद की घरेलू मांग में गिरावट आई है, वहां आयातों में वृद्धि से क्षति में वृद्धि ही होगी।

आयातों का कीमत प्रभाव

47. निम्नलिखित तालिका से यह देखा जाता है कि कीमत में मामूली ऋणात्मक कटौती हुई है।

रु./किग्रा.	चीन जन.गण.	इंडोनेशिया
सीआईएफ निर्यात कीमत	94.13	95.39
पहुंच कीमत	99.03	100.35
घरेलू उद्योग की निवल बिक्री कीमत	***	***
कीमत कटौती	***	***
कीमत कटौती % रेंज	-1% to 1%	-2% to 2%

तथापि, घरेलू उद्योग ने यह उल्लेख किया है कि वह विचाराधीन उत्पाद के पहुंच मूल्य के अनुसार संबद्ध वस्तु की कीमत तय करता है और यह तुलना निवल बिक्री कीमत में उस कारोबार छूट को शामिल करने के बाद की जानी चाहिए जो वह अपने ग्राहकों को प्रदान करता है, जो कि प्राप्त कारोबार के लिए प्रत्यक्ष प्रासंगिक होता है; और यदि इस कारोबारी छूट को औसत बिक्री कीमत में शामिल किया जाएगा तो कीमत कटौती अत्यधिक सकारात्मक होगी।

47.1 प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के निष्पादन पर पाटित आयातों का कीमत प्रभाव प्रतिकूल रहा है। प्राधिकारी ने उत्पादन लागत तथा घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत के साथ-साथ आयातों की पहुंच कीमत की आगे तुलना की है जो निम्नलिखित तालिका में दर्शायी गयी है:

रु./किग्रा.	2005-06	2006-07	2007-08	अप्रैल-जून 08	जलाई-दिसं. 08 (जांच अवधि)
उत्पादन की लागत	***	***	***	***	***
सूचीबद्ध	100	106	117	150	146
बिक्री कीमत	***	***	***	***	***
सूचीबद्ध	100	116	141	149	135
पहुंच कीमत चीन जन.गण.	138.02	86.59	112.66	110.79	99.03
सूचीबद्ध	100	63	82	80	72
पहुंच कीमत इंडोनेशिया	77.28	87.58	99.47	107.78	100.35
सूचीबद्ध	100	113	129	139	130

संबद्ध देशों से औसत पहुंच कीमत	77.77	87.40	102.80	108.07	100.14
सूचीबद्ध	100.00	112.39	132.19	138.97	128.77

47.2 यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत आधार वर्ष में 100 से बढ़कर जांच अवधि में 135 हो गई है। तथापि, इसकी उत्पादन लागत आधार वर्ष में 100 से बढ़कर जांच अवधि में 146 हो गई है। स्पष्टतः घरेलू उद्योग उत्पादन लागत में वृद्धि के अनुरूप अपनी बिक्री कीमत में बढ़ोत्तरी नहीं कर सका; जिससे यह पता चलता है कि पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमत में अत्यधिक ह्रास हो रहा था।

47.3 प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की कम कीमत पर बिक्री की भी जांच की है और यह नोट किया है कि संबद्ध देशों से पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत से काफी कम रहा है जैसा कि निम्नलिखित तालिका से देखा जा सकता है।

रू./किग्रा.	एनआईपी (ग्रे फाइबर)	पहुंच कीमत	कम कीमत पर बिक्री	कम कीमत पर बिक्री % रेंज
चीन जन.गण.	***	99.03	***	5 से 15
इंडोनेशिया	***	100.35	***	5 से 15
संबद्ध देश	***	100.14	***	5 से 15

47.4 स्पष्टतः घरेलू उद्योग पाटित आयातकों की मौजूदगी के कारण क्षति रहित कीमत से कम कीमत पर संबद्ध वस्तु की बिक्री करने के लिए बाध्य हुआ है। हितबद्ध पक्षकारों ने अन्य बातों के साथ-साथ यह तर्क दिया है कि वर्तमान मामले में कीमत कटौती ऋणात्मक रही है और इसलिए घरेलू उद्योग को क्षति पाटित आयातों के कारण नहीं हुई है। अतः प्राधिकारी ने विधिक और तथ्यात्मक स्थिति की विस्तृत जांच की है। यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग प्रचलित अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के आधार पर अपनी कीमत निर्धारित करता है। वस्तुतः केवल इस तथ्य से यह साबित हो जाता है कि उत्पादन लागत में हुई वृद्धि के अनुरूप की गई बिक्री कीमतों में वृद्धि संबद्ध देशों से पाटित आयातों की मौजूदगी के कारण की गई थी।

47.5 प्राधिकारी यह भी समुक्ति करते हैं कि कीमत कटौती निर्धारित करने का उद्देश्य इस बात का आकलन करना है कि क्या ऐसे पाटित आयातों से घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है। यदि आयात कीमत घटती है तो घरेलू उद्योग को भी अपनी बिक्री कीमतें घटाने के लिए बाध्य होना पड़ सकता है। यदि आयात कीमतें बढ़ती हैं परंतु यह उत्पादन लागत में हुई पूरी वृद्धि तक नहीं बढ़ती हैं तो घरेलू उद्योग को उत्पादन लागत में हुई वृद्धि के अनुरूप अपनी कीमतों में वृद्धि करने में समस्या आएगी। पाटनरोधी नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी के लिए यह निर्धारित करना अपेक्षित है कि आयातों से घरेलू कीमतों में कटौती हो रही है या क्या आयातों का प्रभाव अन्यथा बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों को कम करना अथवा घटाना रहा था। इस प्रकार नियमों में कीमत कटौती, कम कीमत पर बिक्री या कीमत ह्रास को साबित करने का स्पष्ट प्रावधान है।

47.6 इस संबंध में यह नोट करना संगत है कि प्राधिकारी ने कारखाना द्वार स्तर पर निवल बिक्री प्राप्ति पर विचार करके तथा छूट और कमीशन, माल भाड़ा और परिवहन लागत आदि को घटाकर कीमत कटौती का निर्धारण किया था। यद्यपि, घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि बीजक के बाद की छूटों को घटाना उचित नहीं है। किसी भी तरह से सकारात्मक कटौती की गैर मौजूदगी का अर्थ क्षति का अभाव नहीं है।

घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंड

48. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-॥ में यह अपेक्षित है कि क्षति के निर्धारण में ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की तथ्यपरक जांच शामिल होगी। जहां तक ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन उत्पादों के परिणामी प्रभाव का संबंध है, नियमों में आगे यह उपबंध है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में समस्त संगत आर्थिक कारकों और बिक्री में वास्तविक एवं संभावित गिरावट, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्सा, उत्पादकता, निवेश पर आय या क्षमता उपयोग में गिरावट, घरेलू कीमत, पाटन मार्जिन की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक; नकद प्रभाव, माल सूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक एवं संभावित ऋणात्मक प्रभावों सहित उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले संकेतकों की तथ्यपरक और निष्पक्ष जांच शामिल होनी चाहिए। घरेलू उद्योग के निष्पादन की जांच से यह पता चलता है कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है। घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति मापदंडों पर निम्नानुसार चर्चा की गई है :-

बिक्री मात्रा

49. घरेलू उद्योग की बिक्री मात्रा निम्नलिखित तालिका में दी गई है :-

मी.ट. में	2005-06	2006-07	2007-08	अप्रैल-जून 08	जुलाई-दिसं. 08 (जांच अवधि)	अप्रैल-जून 08 वार्षिकीकृत	जांच अवधि वार्षिकीकृत
बिक्री मात्रा	223,147	226,178	237,395	49,784	100,925	199,136	201,850
प्रवृत्ति सूचीबद्ध	100	101	106	89	90	89	90

49.1 यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग की बिक्री में वर्ष 2007-08 तक बिक्री हुई थी और उसके बाद अप्रैल-जून, 08 की अवधि तथा जांच अवधि में गिरावट आई थी। यद्यपि, मांग में गिरावट आई है तथापि, मांग में गिरावट आने के कारण आयातों में आनुपातिक रूप से गिरावट नहीं आई है, अपितु उनमें वास्तविक वृद्धि हुई है।

इस तर्क के संबंध में कि बिक्री मात्राओं में गिरावट उपभोक्ताओं के खरीद कम करने और वस्त्र उत्पादों के निर्यातों में तेजी से गिरावट के कारण आई है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऐसी स्थिति जहां (क) उपभोक्ता घरेलू स्रोत से खरीद को सीमित कर रहे हैं परंतु आयातों के जरिए खरीद बढ़ा रहे हैं; और (ख) आयात कीमतों के कारण घरेलू कीमतों में गिरावट आई है। वस्तुतः यह सिद्ध करती है कि घरेलू उद्योग को पाटित आयातों के कारण क्षति हुई है।

उत्पादन, क्षमता और क्षमता उपयोग

50. उत्पादन, क्षमता एवं क्षमता उपयोग से संबंधित सूचना निम्नलिखित तालिका में दी गई है:

मी.ट. में	2005-06	2006-07	2007-08	अप्रैल-जून 08	जुलाई- दिसं. 08 (जांच अवधि)	अप्रैल-जून 08 वार्षिकीकृत	जांच अवधि वार्षिकीकृत
क्षमता	253,450	266,450	266,450	82,355	166,520	329,420	333,040
सूचीबद्ध	100	105	105	130	131	130	131
उत्पादन	228,981	246,832	277,818	57,829	114,314	231,317	228,628
सूचीबद्ध	100	108	121	101	100	101	100
क्षमता उपयोग	90.35%	92.64%	104.27%	70.22%	68.65%	70.22%	68.65%
सूचीबद्ध	100	103	115	311	152	78	76

50.1 यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग के उत्पादन और क्षमता उपयोग में वर्ष 2007-08 तक सुधार हो रहा था जिसमें अप्रैल-जून, 08 की अवधि और जांच अवधि में गिरावट आई। कुछेक हितबद्ध पार्टियों ने यह आरोप लगाया है कि घरेलू उद्योग ने मार्च, 2008 में अपनी क्षमता में वृद्धि की थी और किसी नई क्षमता द्वारा पुरानी क्षमता के बराबर कार्य निष्पादन नहीं किया जा सकता। प्राधिकारी ने क्षमता के उसी स्तर पर जो विस्तार से पूर्व विद्यमान था, घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन की जांच की है और यह नोट किया है कि क्षमता के एक समान स्तर होने के बाद भी क्षमता उपयोग वर्ष 2007-08 में 104.27% से घटकर जांच अवधि में 85.8% हो गया।

लाभ/हानि, निवेश पर आय और नकद लाभ

51. लाभ/हानि, निवेश पर आय और नकद लाभ से संबंधित सूचना निम्नलिखित तालिका में दी गई है:-

	2005-06	2006-07	2007-08	अप्रैल-जून 08	जुलाई- दिसं. 08 (जांच अवधि)	अप्रैल-जून 08 वार्षिकीकृत	जांच अवधि वार्षिकीकृत
करपूर्व लाभ लाख रुपए	***	***	***	***	***	***	***
सूचीबद्ध	100	168	271	127	73	127	73
करपूर्व लाभ रु. किग्रा	***	***	***	***	***	***	***
सूचीबद्ध	100	166	254	142	81	142	81
पीबीआईटी लाख रुपए	***	***	***	***	***	***	***
सूचीबद्ध	100	163	257	138	96	138	96
पीबीआईटी लाख रुपए	***	***	***	***	***	***	***
सूचीबद्ध	100	161	242	155	107	155	107
नकद लाभ लाख रुपए	***	***	***	***	***	***	***
सूचीबद्ध	100	163	255	131	84	131	84

नकद लाभ रु. किग्रा.	***	***	***	***	***	***	***
सूचीबद्ध	100	161	240	147	93	147	93
निवेश पर आय - जीएफए आधार	***	***	***	***	***	***	***
सूचीबद्ध	100	149	185	100	62	100	62
आरओआई- एनएफए आधार	***	***	***	***	***	***	***
सूचीबद्ध	100	149	171	87	57	87	57

51.1 प्राधिकारी नोट करते हैं कि लाभप्रदता में वर्ष 2007-08 तक सुधार हो रहा था जिसमें तत्पश्चात पर्याप्त गिरावट आई थी। निवेश पर आय एवं नकद लाभ में भी लाभप्रदता के समान प्रवृत्ति देखी गई है। यह नोट किया जाता है कि यद्यपि जांच अवधि के दौरान निवेश पर औसत आय सकारात्मक थी, तथापि क्षति अवधि के दौरान इसमें भारी गिरावट आई। प्राधिकारी ने जांच अवधि के भीतर तिमाही आधार पर घरेलू उद्योग के लाभ एवं आरओआई स्थिति की आगे जांच की थी। आगे यह नोट किया गया है कि जांच अवधि की दूसरी तिमाही में घरेलू उद्योग के निष्पादन में भारी गिरावट आई है जैसा कि निम्नलिखित तालिका से देखा जा सकता है

	जुलाई-सितं. 08	अक्टू-दिसं. 08	जुलाई-दिसं. 08 (जांच अवधि)
आरओआई - जीएफए आधार	***	***	***
सूचीबद्ध	85.09%	39.01%	62.37%
आरओआई - एनएफए आधार	***	***	***
सूचीबद्ध	75.35%	35.06%	56.51%

51.2 कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग के प्रकाशित विवरणों से काफी अधिक जबर्दस्त वित्तीय निष्पादन प्रदर्शित होता है जैसा कि नियोजित पूंजी पर उच्च आय से प्रदर्शित होता है। इस संबंध में यह नोट किया जाता है कि नियोजित पूंजी पर आय 2005-06 की अवधि, जांच अवधि और 2008-09 की अवधि के दौरान क्रमशः 43%, 17% और 23% रही थी। तथापि, प्राधिकारी ने नोट किया है कि नियोजित पूंजी पर इस आय का निर्धारण (क) आवंटन नहीं करने योग्य कार्पोरेट अतिरिक्त व्ययों को समायोजित किए बिना, (ख) फाइबर और लुग्दी के संबंध में किया गया है। तथापि, विद्युत् उत्पाद की लाभप्रदता और नियोजित पूंजी पर आय घरेलू उद्योग की फाइबर और लुग्दी खंड के उप समूह के लिए संगत है। घरेलू उद्योग के बी एस एफ खंड में न केवल संबद्ध वस्तु शामिल है बल्कि लुग्दी सुविधाएं, इंजीनियरिंग प्रभाग, उपभोक्ता उत्पाद प्रभाग आदि भी शामिल है। इस बात पर भी ध्यान दिलाना संगत है कि प्रकाशित वित्तीय विवरण में 2005-06 में 43% की नियोजित पूंजी पर आय से जांच अवधि में 17% की आय तक की भारी गिरावट दर्शायी गई है।

51.3 कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग की लाभप्रदता पर संभवतः ब्याज और मूल्यहास के कारण उच्च लागत के चलते प्रभाव पड़ा होगा। दूसरी ओर घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि उसकी ब्याज और मूल्यहास लागत इस तथ्य के मद्देनजर कम रही है कि क्षमताओं का एक बड़ा हिस्सा काफी समय पहले सृजित/स्थापित किया गया है और इन संयंत्रों का अब पूर्णतः मूल्यहास हो गया है परंतु ये पूर्णतः प्रचालनरत हैं। वस्तुतः घरेलू उद्योग ने यह दावा

किया है कि वह इन कारणों से उच्च कीमतों का हकदार है। तथापि, प्राधिकारी ने यह संगत दृष्टिकोण अपनाया है कि किसी अवधारणात्मक निर्धारण के बजाए घरेलू उद्योग की वास्तविक उत्पादन लागत पर उसकी लाभप्रदता का आकलन करने के लिए विचार किया जाएगा।

मालसूची:

52. घरेलू उद्योग की मालसूची का स्तर निम्नानुसार रहा है:

मी.ट. में	2005-06	2006-07	2007-08	अप्रैल-जून 08	जुलाई-दिसं. 08 (जांच अवधि)
मालसूची	***	***	***	***	***
मालसूची-दैनिक बिक्रियों की संख्या के बराबर	***	***	***	***	***

52.1 यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग की मालसूची में वर्ष 2006-07 में गिरावट आई जिसमें वर्ष 2007-08 में पुनः वृद्धि हुई। अप्रैल-जून, 08 की अवधि एवं जांच अवधि के दौरान वर्ष 2007-08 की अवधि की तुलना में मालसूची में पुनः वृद्धि हुई।

रोजगार, मजदूरी एवं उत्पादकता

53. घरेलू उद्योग के रोजगार, मजदूरी एवं उत्पादकता से संबंधित सूचना निम्नानुसार है:

	2005-06	2006-07	2007-08	अप्रैल-जून 08	जुलाई-दिसं. 08 (जांच अवधि)	जुलाई-दिसं. 08 (जांच अवधि वार्षिकीकृत)
रोजगार	***	***	***	***	***	***
सूचीबद्ध	100	97	96	95	95	95
मजदूरी लाख रु.	***	***	***	***	***	***
सूचीबद्ध	100	117	125	137	123	123
प्रति दिवस उत्पादकता	***	***	***	***	***	***
सूचीबद्ध	100	108	121	101	100	100
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	***	***	***	***	***	***
सूचीबद्ध	100	111	126	107	105	105

53.1 यह नोट किया जाता है कि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के रोजगार के स्तर में गिरावट आई थी। तथापि, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यह गिरावट न केवल जांच अवधि में देखी गई है अपितु यह जांच अवधि से पूर्व भी विद्यमान थी। घरेलू उद्योग की मजदूरी में सामान्य वृद्धि प्रदर्शित होती है। जहां तक प्रति कर्मचारी उत्पादकता का संबंध है, इसमें वर्ष 2007-08 तक वृद्धि हुई और अप्रैल-जून, 08 की अवधि और जांच अवधि के दौरान गिरावट आई।

पाटन मार्जिन:

54. यह देखा गया है कि संबद्ध देशों से हुए निर्यातों के संबंध में पाटन मार्जिन सकारात्मक और निर्धारित न्यूनतम सीमाओं से अधिक है।

वृद्धि

55. प्राधिकारी नोट करते हैं कि बिक्री (आधार वर्ष से 9.54% और वर्ष 2007-08 से 16% की गिरावट) उत्पादन (आधार वर्ष से 0.15% और 2007-08 से 21.48%) और क्षमता उपयोग (आधार वर्ष से लगभग 24% और वर्ष 2007-08 से 39.42% की गिरावट) जैसे मात्रात्मक मापदंडों के रूप में घरेलू उद्योग की वृद्धि ऋणात्मक रही है। कीमत संबंधी मापदंडों में वृद्धि भी ऋणात्मक देखी गई है। जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का कर पूर्व लाभ (आधार वर्ष से 26.69% और वर्ष 2007-08 से 197% की गिरावट) तथा निवेश पर आय (आधार वर्ष से 43.49% और वर्ष 2007-08 से 114.13% की गिरावट) में भी भारी कमी आई है।

वास्तविक क्षति का खतरा

56. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु की अधिशेष क्षमताओं की उपलब्धता के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोधों को नोट किया है। रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना से यह देखा जाता है कि संबद्ध देशों में क्षमताओं में भारी वृद्धि हुई है जबकि क्षमता उपयोग में भारी गिरावट आई है जिससे संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु की अधिशेष क्षमताओं का संकेत मिलता है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति अवधि के दौरान पाटित आयातों की वृद्धि दर अत्यधिक है जिससे अत्यधिक संवर्धित आयात की संभावना का पता चलता है। इंडोनेशिया से सहयोगी निर्यातकों के आंकड़ों से उनकी मालसूची के स्तरों में भारी वृद्धि प्रदर्शित होती है। भारी मात्रा में कम कीमत पर बिक्री और भारी मूल्य ह्रास हुआ है जिससे घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति के खतरे का संकेत मिलता है। यदि जांच अवधि के तुरंत बाद की तिमाही के दौरान संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के पहुंच मूल्य को देखा जाता तो यह मत और भी दृढ़ हो जाएगा। यह नोट किया जाता है कि पहुंच मूल्य में 7.81% तक की गिरावट आई है जैसा कि इंडोनेशिया से आयातों के मामले में निम्नांकित तालिका से देखा जा सकता है। जहां तक जांच अवधि के दौरान चीन जन.गण. से आयातों का संबंध है, यह देखा गया है कि पहुंच मूल्य में 18.03% तक की गिरावट आई है। संचयी रूप से संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के पहुंच मूल्य में जांच अवधि के दौरान 7.97% की गिरावट आई है।

रु./किग्रा.	जुलाई-दिसं.08 (जांच अवधि)	जन-मार्च 09 (जांच अवधि के बाद की तिमाही)
पहुंच मूल्य - ची जन.गण.	99.03	81.17
पहुंच मूल्य - इंडोनेशिया	100.35	92.51
संबद्ध देशों से औसत पहुंच कीमत	100.02	92.05
घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत	***	***

ज. कारणात्मक संबंध**57. घरेलू उद्योग के विचार**

- प्राधिकारी ने सभी अन्य ज्ञात कारकों की पहले ही जांच कर ली है। मांग में गिरावट के कारण क्षति के संबंध में प्राधिकारी द्वारा प्रारंभिक जांच परिणामों में इसकी जांच की गई है। जहां तक वैश्विक मंदी का संबंध है, यह प्रदर्शित नहीं किया गया है कि वैश्विक मंदी के कारण लाभप्रदता में वास्तव में गिरावट आनी चाहिए। जहां तक निविष्टि लागत में वृद्धि का संबंध है, इसे नियमावली के अंतर्गत विशिष्ट रूप से शामिल किया जाता है।

- जहां तक भारतीय रुपए के कमजोर होने का संबंध है, तो यह बात घरेलू उद्योग के विरुद्ध होने के बजाए घरेलू उद्योग के लाभ की ओर जानी चाहिए। यद्यपि, आवेदक केवल आयातित बुड पल्प पर निर्भर करता है और उस पर इसके कारण प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता था क्योंकि आयातित लुग्दी की पहुंच कीमत काफी बढ़ गई थी।
- जहां तक क्षमता विस्तार का संबंध है, यह पूर्ववर्ती निर्णयों का परिणाम होता है। किसी भी तरह से घरेलू उद्योग से केवल पाटन के कारण अपनी विस्तार योजनाओं को समाप्त करने की आशा नहीं की जा सकती है।

58. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

- प्राधिकारी को ऐसे अन्य कारकों की जांच करनी चाहिए जिनसे घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है।
- अपनी वार्षिक रिपोर्ट में घरेलू उद्योग ने बताया है कि उत्पादन और बिक्रियों और लाभों में कमी (1) कम मांग (2) वैश्विक मंदी (3) निविष्टि लागत में तेजी से वृद्धि और भारतीय रुपए के कमजोर पड़ने के कारण हुई है। इस प्रकार कथित पाटन के कारण क्षति होना मिथ्या आरोप है और कोरी कल्पना है।
- कीमतों में कटौतियों का कथित पाटन से कोई लेना देना नहीं है (इस संबंध में वर्ष 2007-08 की वार्षिक रिपोर्ट का हवाला दिया गया है)
- कम लाभप्रदता निविष्टि लागतों में वृद्धि, कम मात्राओं और कम मार्जिनों के कारण है। ब्याज और मूल्यहास की लागत काफी अधिक प्रतीत होती है (वर्ष 2007-08 की वार्षिक रिपोर्ट, कारपोरेट प्रस्तुतिकरण, वित्त वर्ष 09 की दूसरी तिमाही का प्रस्तुतिकरण और वित्त वर्ष 09 की तीसरी तिमाही के प्रस्तुतिकरण का संदर्भ दिया गया है)।
- मंदी की स्थिति के बावजूद घरेलू उद्योग ने अपनी क्षमता का विस्तार किया है।
- बिक्रियों में गिरावट (1) उपभोक्ताओं के खरीद नहीं करने (2) वस्त्र निर्यातों में गिरावट के कारण मांग में कमी आने (3) स्थितिकारी दबाव के साथ वैश्विक मंदी (4) मूल्य श्रृंखला में मालसूची के परिसमापन के कारण आई है।
- क्षमता में विस्तार हुआ है, इस प्रकार क्षमता में वृद्धि /विस्तार की क्षमता के कारण कोई क्षति नहीं हुई है। (वर्ष 2007-08 की वार्षिक रिपोर्ट का हवाला दिया गया है)
- तीसरी तिमाही की रिपोर्ट के अनुसार कम मांग के कारण उत्पादन को घटाया गया था। भिन्न-भिन्न मंचों के समक्ष घरेलू उद्योग द्वारा भिन्न-भिन्न विवरण दिया गया है। डेप्ट 09-एच1 के कार्य निष्पादन में पानी की कमी के कारण 48 दिनों तक एनएजीडीए संयंत्र के बंद रहने के बावजूद उत्पादन में 15% तक की वृद्धि हुई। बिक्रियों में 19% की वृद्धि, नई प्रभागीय आय में 17% तक और पी बी आई डी टी में 35% तक की वृद्धि हुई।
- घरेलू उद्योग गुजरात के विलायत में 80,000 मी.ट. की एक परियोजना में निवेश करने की योजना बना रहा है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

59. प्राधिकारी ने इस बात की जांच की है कि क्या अन्य मापदंडों से घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती थी। इस संबंध में निम्नलिखित मापदंडों का विश्लेषण किया गया है :-

(क) तीसरे देशों से आयात:- प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंडएस से संबद्ध वस्तु के आयात के सौदेवार आंकड़े एकत्र किए हैं। रिकार्ड में उपलब्ध सूचना से प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जांच अवधि के दौरान किसी अन्य देश से संबद्ध वस्तु का कोई आयात नहीं हुआ है।

(ख) मांग में कमी:- प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तु की मांग में 2007-08 तक पर्याप्त सुधार प्रदर्शित हुआ है और तत्पश्चात जांच अवधि में गिरावट देखी गई है तथापि, मांग की तुलना में आयात में पर्याप्त वृद्धि हुई है जो सामान्यतः मांग में गिरावट के कारण नहीं होनी चाहिए थी। यह नोट किया जाता है कि उपलब्ध मांग के भीतर घरेलू उद्योग ने अपना बाजार हिस्सा गंवाया है। स्पष्टतः घरेलू उद्योग को पहले ही घटती हुई मांग की समस्या का सामना करना पड़ रहा था परंतु पाटित आयातों ने स्थिति को और गंभीर बना दिया।

(ग) खपत की प्रवृत्ति : खपत की प्रवृत्ति में किसी खास परिवर्तन को नोट नहीं किया गया है। स्पष्टतः घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किया गया उत्पाद संबद्ध देशों से आयातित सामग्री से सीधे प्रतिस्पर्धा कर रहा है।

(घ) प्रतिस्पर्धा की स्थितियां : रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के अनुसार इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि प्रतिस्पर्धा की स्थितियां अथवा व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाओं के कारण घरेलू उद्योग को कोई क्षति हुई हो।

(ङ) प्रौद्योगिकी में विकास : रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के अनुसार क्षति अवधि के दौरान प्रौद्योगिकी में ऐसा कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देता है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हुई हो।

(च) घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन : घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन को घरेलू बिक्रियों और निर्यात बिक्रियों के लिए पृथक-पृथक किया गया है और घरेलू उद्योग की क्षति का आकलन करते समय घरेलू उद्योग के केवल घरेलू कार्य निष्पादन पर विचार किया गया है।

60. प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन में संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण विकृति आई है। यह बात निम्नलिखित तथ्यों से सिद्ध होती है:-

(i) क्षति अवधि के दौरान संबद्ध देशों से आयातों में भारी वृद्धि हुई है। यह नोट किया जाता है कि यद्यपि घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आई है परंतु संबद्ध देशों से आयातों के हिस्से में वृद्धि हुई है।

(ii) कीमतों पर दबाव रहा है क्योंकि घरेलू उद्योग उत्पादन लागत में हुई वृद्धि के अनुपात में अपनी कीमतों में वृद्धि नहीं कर पाया है। पाटित आयातों द्वारा भारी कीमत ह्रास के कारण घरेलू उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इसके परिणामस्वरूप लाभ और नकद प्रवाह में भारी गिरावट आई है।

(iii) संबद्ध देशों से पहुंच मुख्य के साथ घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत की तुलना से यह पता चलता है कि कम कीमत पर बिक्री का भी मामला बनता है।

60.1 कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि उत्पादन, बिक्री और लाभप्रदता में गिरावट कम मांग, प्रचलित वैश्विक मंदी, निविष्टि लागतों में तेजी से वृद्धि और भारतीय रुपए के कमजोर होने के कारण आई है; प्राधिकारी नोट करते हैं कि वार्षिक रिपोर्ट में इन सार्वजनिक विवरणों से इस निष्कर्ष में कोई बदलाव नहीं आया है कि इस उत्पाद के पाटन से घरेलू उद्योग को क्षति उठानी पड़ी है। सर्वप्रथम हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गलत ढंग से यह मान लिया गया है कि उत्पाद का पाटन घरेलू उद्योग को हुई क्षति का एकमात्र कारण होना चाहिए। यद्यपि, मांग में गिरावट के कारण निश्चित रूप से उत्पादन और बिक्री में गिरावट आई है परंतु संबद्ध वस्तु के पाटन के कारण भी घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति उठानी पड़ी है। लाभप्रदता के संबंध में घरेलू उद्योग आयात कीमतों के आधार पर अपनी कीमतें तय करता है; इसलिए बाजार में कम कीमत पर पाटित आयातों की उपलब्धता के कारण स्पष्ट रूप से घरेलू उद्योग को ऐसी कीमतों की पैदाइश

करने पर बाध्य होना पड़ा है जिनसे निविष्टियों की लागत में हुई वृद्धि की वसूली नहीं हो सकती थी ।

60.2 जहां तक निविष्टि लागतों में तेजी से वृद्धि से संबंधित मुद्दे का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि यदि घरेलू उद्योग उत्पादन लागत में हुई वृद्धि के अनुक्रम में अपनी कीमतों में वृद्धि करने में सक्षम नहीं रहा है तो यह स्पष्ट रूप से कीमत न्यूनीकरण का मामला है जो क्षति का एक महत्वपूर्ण संकेतक होता है । भारतीय रूपए के कमजोर पड़ने के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि इससे आयातों से होने वाली क्षति में कमी आनी चाहिए क्योंकि भारतीय रूपए के कमजोर होने से आयातों के कम आकर्षक होने का प्रभाव पड़ता है ।

क्षति की मात्रा और क्षति मार्जिन

61. जांच अवधि के दौरान क्षति मार्जिनों के निर्धारण के लिए प्राधिकारी द्वारा यथानिर्धारित घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु की क्षति रहित कीमत की तुलना संबद्ध देशों से निर्यातों के पहुंच मूल्य के साथ की गई है । इस प्रकार तुलना द्वारा ज्ञात किये गये क्षति मार्जिन निम्नानुसार हैं :-

रु./किग्रा.

	इंडोनेशिया			चीन जन.गण.
	पी टी इंडो भारत रेयन	पी टी साउथ पेसिफिक विस्कोस	अन्य	
एनआईपी	***	***	***	***
पहुंच मूल्य	***	***	***	***
क्षति मार्जिन	***	***	***	***
क्षति मार्जिन %	***	***	***	***
क्षति मार्जिन रेंज(%)				

अ. निष्कर्ष

62. हितबद्ध पार्टियों द्वारा किए गए अनुरोधों और उनमें उठाए गए मुद्दों की जांच करने और रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों पर विचार करने के उपरान्त प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि

- (क) संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद का भारत को निर्यात इसके सामान्य मूल्य से कम कीमत पर किया गया है;
- (ख) विचाराधीन उत्पाद के संबंध में घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति उठानी पड़ी है । इसके अलावा, वास्तविक क्षति के खतरे का मामला भी बनता है ।
- (ग) वास्तविक क्षति और उसका खतरा संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों के कारण उत्पन्न हुआ है ।

ट. भारतीय उद्योग के हित एवं अन्य मुद्दे

63. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्कों का उद्देश्य सामान्यतः पाटन की अनुचित व्यापार पद्धतियों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली एवं

उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति को बहाल किया जा सके, जो देश के सामान्य हित में है। पाटनरोधी उपाय लागू करने से संबद्ध देशों से आयातों पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगेगा; अतः उपभोक्ताओं के लिए उन उत्पादों की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी।

64. प्राधिकारी यह स्वीकार करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से संबद्ध वस्तुओं के उपयोग से विनिर्मित उत्पादों के कीमत स्तर प्रभावित हो सकते हैं और परिणामतः इन उत्पादों की तुलनात्मक प्रतिस्पर्धात्मकता पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है। तथापि, पाटनरोधी उपायों द्वारा भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा में कमी नहीं आएगी खासकर तब जबकि पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए आवश्यक राशि तक सीमित रखा जाएगा। इसके विपरीत पाटनरोधी उपाय लागू किए जाने से पाटन के व्यवहार द्वारा प्राप्त अनुचित लाभ समाप्त होंगे, घरेलू उद्योग का ह्रास रूकेगा और संबद्ध वस्तु के उपभोक्ताओं के लिए व्यापक विकल्प उपलब्ध रखने में मदद मिलेगी। परवर्ती उद्योग पर इसके प्रभाव को कम करने की दृष्टि से प्राधिकारी ने पाटन और क्षति मार्जिनों में से कम के आधार पर पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश करने को उचित समझा है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी उपायों को लगाए जाने से संबद्ध देशों से होने वाले आयात किसी भी तरह से प्रतिबंधित नहीं होंगे और इसलिए इनसे उपभोक्ताओं को उत्पाद की उपलब्धता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

ठ. सिफारिशें

65 प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की शुरुआत कर उसकी सूचना सभी हितबद्ध पार्टियों को दी गई थी और निर्यातकों, आयातकों एवं अन्य हितबद्ध पार्टियों को पाटन, क्षति एवं कारणात्मक संबंध के पहलुओं के बारे में सकारात्मक सूचना प्रदान करने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था। पाटनरोधी नियमों के अनुसार पाटन, क्षति एवं कारणात्मक संबंध के बारे में प्रारंभिक जांच शुरू करने के बाद तथा सकारात्मक पाटन मार्जिन एवं ऐसे पाटित आयातों द्वारा घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति की अनंतिम रूप से पुष्टि करने के बाद प्राधिकारी का यह मत है कि जांच पूरी होने तक पाटन एवं क्षति को समाप्त करने के लिए अनंतिम शुल्क लगाना अपेक्षित है। अतः प्राधिकारी यह आवश्यक समझते हैं और संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों पर नीचे उल्लिखित प्रपत्र में और तरीके से निम्नानुसार अनंतिम पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश करते हैं।

66. प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए कमतर शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी पाटन मार्जिन और "क्षति" मार्जिन जो भी कम हो, के बराबर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं ताकि घरेलू उद्योग को हुई "क्षति" समाप्त की जा सके। तदनुसार संबद्ध देशों के मूल की या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के सभी आयातों पर निम्नलिखित तालिका के कालम 8 में उल्लिखित राशि के बराबर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की जाती है।

क्र. सं.	शीर्ष / उप शीर्ष	वस्तु विवरण	उद्गम का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	निर्यातक	शुल्क राशि	इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
1	5504.10.00	"बॉस के फाइबर को छोड़कर विस्कोस स्टेपल फाइबर (बीएसएफ)"	इंडोनेशिया	इंडोनेशिया	मै. पी टी साउथ पॅसिफिक विस्कोस	मै. पी टी साउथ पॅसिफिक विस्कोस	0.103	कि. ग्रा.	अम.डॉ.
2	5504.10.00	"बॉस के फाइबर को छोड़कर विस्कोस स्टेपल फाइबर (बीएसएफ)"	इंडोनेशिया	इंडोनेशिया	पी टी इंडो भारत रेयान	पी टी इंडो भारत रेयान	0.164	कि. ग्रा.	अम.डॉ.
3	5504.10.00	"बॉस के फाइबर को छोड़कर	इंडोनेशिया	इंडोनेशिया	उपरोक्त क्र. सं. 1 और 2 पर किए गए उत्पादों से इतर कोई संयोजन		0.512	कि. ग्रा.	अम.डॉ.

		विस्कोस स्टेपल फाइबर (वीएसएफ)							
4.	5504.10.00	"बांस के फाइबर को छोड़कर विस्कोस स्टेपल फाइबर (वीएसएफ)"	इंडोनेशिया	इंडोनेशिया से इतर कोई देश	कोई	कोई	0.512	कि. ग्रा.	अम.डॉ.
5.	5504.10.00	"बांस के फाइबर को छोड़कर विस्कोस स्टेपल फाइबर (वीएसएफ)"	पाटनरोधी शुल्क के अधीन देश से इतर कोई देश	इंडोनेशिया	कोई	कोई	0.512	कि. ग्रा.	अम.डॉ.
6.	5504.10.00	"बांस के फाइबर को छोड़कर विस्कोस स्टेपल फाइबर (वीएसएफ)"	चीन जन.गण.	चीन जन.गण.	कोई	कोई	0.194	कि. ग्रा.	अम.डॉ.
7.	5504.10.00	"बांस के फाइबर को छोड़कर विस्कोस स्टेपल फाइबर (वीएसएफ)"	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. से इतर अन्य कोई देश	कोई	कोई	0.194	कि. ग्रा.	अम.डॉ.
8.	5504.10.00	"बांस के फाइबर को छोड़कर विस्कोस स्टेपल फाइबर (वीएसएफ)"	पाटनरोधी शुल्क के अधीन देश से इतर कोई देश	चीन जन.गण.	कोई	कोई	0.194	कि. ग्रा.	अम.डॉ.

67. इस प्रयोजनार्थ आयातों का पहुंच मूल्य सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत सीमाशुल्क द्वारा यथानिर्धारित आकलनीय मूल्य होगा और उसमें सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3, 3 क, 8 ख, 8 ग, 9 तथा 9 क के अंतर्गत लगाए गए शुल्कों को छोड़कर समस्त सीमाशुल्क शामिल होंगे।

68. इस आदेश के खिलाफ कोई अपील सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अनुसार सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क तथा सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण में दायर की जा सकेगी।

पी. के. चौधरी, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

FINAL FINDINGS

New Delhi, the 17th May, 2010

Subject : Anti-dumping investigation concerning imports of "Viscose Staple Fibre excluding Bamboo fibre" originating in or exported from China PR and Indonesia—Final Findings.

No. 14/6/2009-DGAD- Whereas the Designated authority, having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time, (hereinafter referred to as the AD Rules); recommended imposition of Anti Dumping duty on the imports of 'Viscose Staple Fibre excluding Bamboo fibre' (hereinafter also referred to as the subject goods) originating in or exported from China PR and Indonesia (hereinafter also referred to as the subject countries).

A. Background of the Case

- Having regard to the Act and the AD Rules, the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) received a written application from the Association of Man Made Fibre Industry of India (AMFII) on behalf of the domestic industry, alleging dumping of 'Viscose Staple Fibre excluding Bamboo fibre' originating in or exported from China PR and Indonesia.

3. Preliminary scrutiny of the application revealed certain deficiencies, which were subsequently rectified by the Applicant. The application was, therefore, considered as properly documented. The Authority on the basis of sufficient evidence submitted by the Applicant to justify initiation of the investigation, decided to initiate the investigation against imports of the subject goods from the subject countries. The Authority notified the Embassies of the subject countries in India about the receipt of the application claiming, *inter alia*, allegations of dumping and consequent injury to the domestic industry before proceeding to initiate the investigation in accordance with Rule 5(5) of the AD Rules. The Authority issued a public notice dated 19th March, 2009 published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating Anti-dumping investigation concerning imports of the subject goods originating in or exported from the subject countries, in accordance with the Rule 6(1) of the AD Rules to determine the existence, degree and effect of alleged dumping and to recommend the amount of anti-dumping duty, which, if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.
4. The Authority recommended imposition of provisional Anti-dumping duty on the imports of 'Viscose Staple Fibre excluding Bamboo fibre' originating in or exported from China PR and Indonesia falling under Sub-heading 5504.10.00. The Preliminary findings were notified vide Notification No 14/6/2009-DGAD dated 5th August 2009.

B. PROCEDURE

5. In these proceedings the procedure described herein below has been followed:
 - i. The Embassies of the subject countries in India were informed about the initiation of the investigation, in accordance with Rule 6(2) of the AD Rules.
 - ii. The Designated Authority sent copies of the initiation notification dated 19th March 2009 to the Embassies of the subject countries in India, known exporters from the subject countries, known importers and other interested parties, and the domestic industry, as per the information available with it. Parties to this investigation were requested to file the questionnaires' responses and make their views known in writing within the prescribed time limit. Copies of the letter and questionnaires sent to the exporters were also sent to the Embassies of the subject countries along with a list of known exporters / producers with a request to advise the exporters/ producers from the subject countries to respond to the questionnaires within the prescribed time.
 - iii. Copy of the non-confidential version of the application filed on behalf of the domestic industry was made available to the known exporters and the Embassies of the subject countries in accordance with Rule 6(3) of the AD Rules.
 - iv. Questionnaires were sent to the following known exporters from the subject countries in accordance with Rule 6(4) of the AD Rules to elicit relevant information:

S.N.	Company's Name
	Indonesia
1.	P.T.South Pacific Viscose
2.	PT. Indo Bharat Rayon
	China PR
3.	Hebei Jigao Chemical Fiber Co. Ltd
4.	Kunshan Hengsheng Chemical Fiber Co. Ltd.
5.	Zibo Hualong Chemical Fiber Co., Ltd.
6.	Hubei Chemical Fiber Group Ltd..

7.	Gaomi Silver Hawk Chemical Fibre Co. Ltd
8.	Sateri(Jiangxi)Chemical Fiber Co., Ltd
9.	Fulida Group Holding Co.,Ltd
10.	Manasi Aoyang Technical Co.,Ltd
11.	Yibin Grace Group Co.,Ltd

v. In response to the initiation notification, the following exporters / producers from Indonesia have responded:

- PT Indo Bharat Rayon
- PT South Pacific Viscose

None of the exporters / producers from China PR responded in the instant matter.

vi. Questionnaires were sent to the following known importers and users of the subject goods in India for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the AD Rules:

<ul style="list-style-type: none"> • Pallava Textiles • Cheran Spintex (I) Ltd., • Pallipalayam Spinners, • Shri Cheran Syn. India Ltd. • Keshar Multiyarn Mill Ltd. • Soundararaja Mills Ltd., • Ginni Filaments Ltd. • PKPN Spinning Mills (P) Ltd. • Adani Enterprises Ltd. • Rajapalayam Mills Ltd. • Sutlet Inds. Ltd. • Pallava Textiles • Zenith Spinners, • Cheran Spintex (I) Ltd., • Pee Vee Textiles, • Birla Textiles Mills, • AGT Mills P. Ltd. • Mothi Spinner Ltd, • Orient Syntex, • SMP Textile Mills (P) Ltd. • Sarmangal Synthetics, • Shree Rajasthan Syntex Ltd, • Maharaja Sathayam Ind. Pvt. • Nahar Spinning • Chola Spinning Mills P Ltd, • Sri Karthikeya Spg & Wvg Mills, • KRV Spinning Mills P. Ltd. • Velatal Spinninh Mills P Ltd, • Sree Dinakar Fabrics • Arcot Textile Mill Ltd • Valli Spg Mills • Banswara Syntex Ltd, 	<ul style="list-style-type: none"> • RSWM Ltd. • Reliance Chemotex Ind Ltd, • Rajaguru Spinning Mills, • Deepak Spinners Ltd, • Ankur Ugyog, • Chola Spg Mills • Gimatex Industries Pvt. Ltd., • Sri Bhagirath Textiles Ltd, • Suryalata Spinning Mills • Gillanders Arbuthnot & Co. • Victory Spg. Mills, • Arunkumar Spinning Mills P., • Cheran Spinner Ltd • Shree Bharani Spinning • Sutlet Inds. Ltd. • Rajaguru Spinning Mills, • Pallava Textiles • Sidharth Exports Pvt. Ltd., • Choleeswarar Spinning Mills, • Sree Karpagambal Mills • Sri Hariprasath Textiles • Vardhman Textile Ltd. • Sri Nallathal Spinning Mills • Mothi Spinner Ltd, • Supertex Mills India Pvt. Ltd., • GVS Spinners, • Nru Spinning Mills • Saraf Yarn Pvt.Ltd • Sangam Spinners Ltd. • Chenab Textile Mills , • Spentex Industries Ltd
--	--

In response to the above notification and thereafter, the following importers and users and their Associations have responded:

S.N.	Company's Name
1	Indian Spinners Association – Mumbai
2	Shree Rajasthan Syntex Ltd
3	Suryalata Spinning Mills Ltd, Secunderabad.
4	Spentex Industries Ltd, New Delhi
5	Pee Vee Textiles Ltd
6	Shree Cheran Synthetics India Limited
7	Pallava Textiles Ltd, Tamilnadu
8	RSWM Ltd
9	Pallipalayam Spinners Pvt Limited
10	Northern India Textiles Mills Association
11	The Synthetics and Rayion Textiles Export Promotion Council
12.	Rajasthan Textiles Mills Association
13.	Ginni Filaments Limited
14.	Keshar Multiyarn Mills, Kolkata
15.	Gimatex Industries Pvt.Ltd, Mumbai

- vii. The imports data for the period of investigation and preceding three years was called from Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S).
- viii. The Authority made available non-confidential version of the evidence presented by the interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties.
- ix. Optimum cost of production and cost to make & sell the subject goods in India based on the information furnished by the applicant on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) was worked out so as to ascertain if anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the Domestic Industry.
- x. In accordance with Rule 6(6) of the AD Rules, the Authority also provided opportunity to all interested parties to present their views orally in a public hearing held on 22nd December 2009. The parties, which presented their views in the public hearing, were requested to file written submissions of the views expressed orally. The arguments made in the written submissions/rejoinders received from the interested parties have been considered, wherever found relevant, while arriving at the present findings.
- xi. Some interested parties requested for a second hearing due to change in the Designated Authority. However, the Authority on a careful perusal of the AD Rules considered that holding of a second hearing is not warranted on this ground alone. The party seeking hearing has not raised any contention which warrants presenting the same orally before the Authority. Further, the submissions made by interested

parties have been duly considered by the Authority while arriving at the present findings.

- xii. Verification to the extent deemed necessary was carried out in respect of the information & data submitted by the domestic industry and the co-operating producers/exporters.
- xiii. Investigation was carried out for period starting from 1st July 2008 to 31st Dec 2008 (POI). The examination of trends, in the context of injury analysis, covered the period from 2005-06, 2006-07, 2007-08, April 08-June 08 and POI.
- xiv. In accordance with the Rule 16 of the AD Rules, the essential facts under consideration before the Authority in the instant matter were disclosed to the known interested parties. The comments received on the disclosure statement have been duly considered in the final findings.
- xv. Information provided by interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.
- xvi. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has recorded these findings on the basis of the 'facts available'.
- xvii. *** in this statement represents information furnished by the interested parties on confidential basis and so considered by the Authority under the AD Rules.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND DOMESTIC LIKE ARTICLE:

C.1 Submissions made by the importers and exporters.

6. M/s. Ginni Filament has made the following submissions:

- the basic issue is that they are a non-woven manufacturer, which requires special type of Viscose Staple Fibre and that the submissions made by domestic industry do not contain proper facts. It manufactures non-woven by using hydro entanglement technology. The names of buyers mentioned by the domestic industry are not using the same technology as of theirs and therefore, it is incorrect to state that a number of companies are using domestic fibre for same goods. None of the customers mentioned by domestic industry are the customers of Ginni Filaments Ltd. as contended by domestic industry.

Accordingly, they seek exemption for their industry from levying of antidumping duty in the instant matter.

- Domestic fibre is not at all suitable for their end product, sample consignment tested shows that domestic product does not meet the requirement
- Use of domestic fibre leads to choking of Jet Strips, cartridges, filter etc, which leads to stoppages in production process. Grasim do not use H2O2 for bleaching, which leads to bad smell in the fabric manufactured.
- Grasim does not use dulling agent, hence ash content is low. They need lower oil pickup in fibre, which is not there in domestic fibre.

C.2 Submissions made by the domestic industry.

7. Domestic industry has made the following submissions:

- Referring to M/s. Ginni Filament's submissions, the domestic industry has stated that it is incorrect to state that domestic product is not suitable for their product. A number of companies are using their product and producing same goods. Sales made to such customers is given in the table below:

S.N.	Company's Name	Sales in MT	
		2008-09	2009-10 9 months
1	Ginni Filaments Limited	***	***
2	UNI Products Limited	***	***
3	Supreme Non Woven P Limited	***	***
4	Pacific Harish Industries	***	***
5	Unique Non Woven Co	***	***
6	Tata Mills	***	***
7	Cosmos Non Woven Mills P Ltd	***	***
8	Thakar Felts Pvt Limited	***	***
9	Jiwan Products	***	***
10	Alpha Foam Limited	***	***
11	Ruby Surgical & Allied Products	***	***
12	Total	***	***

- The domestic industry has contended that they have been selling to these customers on regular basis. Even Ginni Filament has been buying from them on regular basis; there is no reason, why Ginni Filament cannot buy from them further.

C.3 Examination by the Authority.

8. The product under consideration is "Viscose Staple Fibre (VSF) excluding Bamboo fibre". Viscose Staple Fibre is described as "Viscose rayon staple fibre not

carded/combed” under the Customs Tariff and is also known as “Rayon Fibre” in some markets. The product under consideration is classified under Custom Headings 5504.10.00. The Customs classification is indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation.

9. Viscose Staple Fibre was the first man-made fibre, and unlike other man-made fibres, is not a synthetic fibre. It is made through wet spinning technology and is a regenerated cellulose fibre made from wood pulp, which is essentially cellulose extracted from a sustainable natural resource i.e. wood, by subjecting it to various chemical and mechanical processes. On account of its cellulosic base, viscose staple fibre properties are similar to those of natural cellulosic fibres than those of thermoplastic, petroleum based synthetic fibres such as nylon or polyester. Further, it has a distinct advantage of engineered specification and uniformity.
10. Viscose Staple Fibre has silk-like aesthetic with superb drape, soft feel and retains rich brilliant colours. Fabrics made from it are moisture absorbent (even more than cotton), breathable, comfortable to wear, and easily dyeable in vivid colours. They do not build up static electricity, and are pill-resistant.
11. Main strength of VSF is its versatility and ability to blend easily with nearly all other textile fibres to impart lusture, softness, absorbency and resulting comfort to the fabric made from such blends. Bamboo fibre, one of the types of Viscose Staple Fibre is excluded from the scope of this investigation. In the initiation notification, Designated Authority has specifically requested the interested parties to make their submissions with regard to exclusion of Bamboo Fibre. None of the interested parties had made any submissions in this regard.
12. With regard to like article, Rule 2(d) of the AD rules provides as under

"like article " means an article which is identical or alike in all respects to the article under investigation for being dumped in India or in the absence of such article, another article which although not alike in all respects, has characteristics closely resembling those of the articles under investigation
13. The applicant has claimed that there is no known difference in the subject goods produced by the domestic industry and the subject goods exported from the subject countries. The subject goods produced by the domestic industry and the subject goods imported from subject countries are comparable in terms of characteristics such as physical and chemical characteristics, manufacturing process and technology, functions and uses, product specifications, distribution and market & tariff classification of the goods.
14. The Authority notes that M/s. Ginni Filament while making its submissions has not substantiated their claim with any evidence to that effect. Whereas, the domestic industry has provided evidence showing sale of this particular type of fibre to (a) Ginni Filament, (b) other consumers in India, who are producing similar goods, (c) a number of global

consumers. The domestic industry has also provided evidence to show that Ginni Filament is in fact discussing procurement of more material from the domestic industry. It is also not established that M/s Grasim Industries does not produce this type of fibre or that it lacks production facilities or capabilities to produce this type of fibre. The available information on record of the Authority does not show that there is any material difference in the domestic like article and imported subject goods. The Authority, therefore, holds that the subject goods produced by the domestic industry is like article to the subject goods imported from subject countries in accordance with the AD rules for the purpose of the present investigation.

D. Scope of the Domestic Industry

D.1 Views of the domestic industry

15. The submissions of the Applicant with respect to its claim of the domestic industry are as under:

- (i) M/s Grasim Industries is the only producer of the product under consideration in India. Therefore, the application has been made by or on behalf of the domestic industry.
- (ii) The application, therefore, satisfies the requirement of standing under the AD Rules. Further, applicant constitutes the domestic industry within the meaning of the AD Rules.
- (iii) The applicant has affiliated companies in China PR and Indonesia producing & selling the product, namely Birla Jingwai Fibres Company Limited, China and PT Indo Bharat Rayon, Indonesia. The relationship between these entities is given in the table below:-

Sr.No	Name of the entity	Common directors
1	Grasim Industries Ltd	***

2	Birla Jingwai Fibres Company Limited, China PR	***
3	PT Indo Bharat Rayon, Indonesia	***

- (iv) Since the applicant itself has stated that these entities are related, the basis on which these companies are related becomes irrelevant. Information establishing relationship is relevant only in those situations where a party disputes existence of such a relationship.

- (v) The affiliated producers are largely selling their products either in the respective domestic markets or exporting to third countries. In general, there are no exports to India.
- (vi) The Chinese affiliated company has not exported the product to India, whereas the Indonesian Company has exported a small quantity to India, which is less than 3% of imports and negligible with reference to Indian production. The exports have been made because some customers of the applicant required imported material under duty exemption schemes. Since the volumes of these imports are quite small, hence the Authority has rightly considered that the applicant should not be considered ineligible under the Rules.
- (vii) It is rightly held by the Authority that the application satisfied the requirements of Rule 2(b) and Rule 5(3) of the AD Rules and therefore, M/s Grasim Industries Ltd. is being treated as 'domestic industry' within the meaning of Rule 2(b) of the AD Rules.
- (viii) An issue that arises for consideration and determination in the present case is in a situation where a producer is related to an exporter in one of the exporting countries, should that producer be considered as eligible domestic industry. In other words, whether the Designated Authority has discretion under the Rule 2(b), and if so, how the discretion is required to be applied. The anti dumping rules were amended in 1999, wherein one of the amendments related to the definition of domestic industry. The Rule (2(b)) prior to this amendment was as follows:

2(b) "domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in which case such producers shall be deemed not to form part of domestic industry:

- (ix) The rule after the amendment is as follows:

2(b) "domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in which case such producers may be deemed not to form part of domestic industry.

- (x) That the rule was amended with a view to provide discretion to the Designated Authority to decide on merits whether a company who is importing the product under consideration or which is related to an exporter or importer should be included or

excluded for the determination of the domestic industry. Rule 2(b) has been amended with the sole objective of providing discretion to the Designated Authority to decide whether to include or exclude a company who has itself imported the alleged ~~dumped~~ product, or who is related to an exporter or importer of the subject ~~goods~~. Such discretion has been exercised in an even manner by the Designated Authority in the instant case.

- (xi) The facts relating to relationship are under full knowledge of the Authority. Factual information on this account is in full public domain. Notwithstanding this, the interested parties have not been able to establish that how the nature of relationship vitiates the present investigation.
- (xii) To support their contentions, the applicant have given references to the followings:
- 'Dumping and Subsidies-The Law and Procedures Governing the Imposition of Anti-dumping and Countervailing Duties in the European Community – by M/s. Clive Stanbrook and Philip Bentley, Kumer Law International, 3rd Edition
 - A Handbook on Anti-dumping Investigations – by Judith Czako, Johann Human and Jorge Miranda, Cambridge University Press, page 234
 - Appendix-F, Antidumping and Countervailing Duty Handbook – Publication 3482, 9th Edition, United States International Trade Commission, page App. F-33
- (xiii) Various decisions of the investigating authorities with regard to imports by applicant itself-from related exporter have been referred to by the applicant, such as:
- a. Council Regulation (EC) No 423/97 of 3 March 1997 amending Regulation (EEC) No 3433/91 in respect of imports originating in Thailand and imposing definitive anti-dumping duties on imports of gas-fuelled, non- refillable pocket flint lighters originating in Thailand, the Philippines and Mexico. Official Journal L 065 , 06/03/1997 P. 0001 – 0016.
 - b. COMMISSION REGULATION (EC) No 2318/95 of 27 September 1995 imposing a provisional anti-dumping duty on imports of certain tube or pipe fittings, of iron or steel, originating in the People' s Republic of China, Croatia and Thailand and terminating the anti-dumping proceeding in respect of imports of these fittings, originating in the Slovak Republic and Taiwan. Official Journal L 234, 03/10/1995 P.0004- 0015
 - c. Council Regulation (EC) No 2022/95 of 16 August 1995 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of ammonium nitrate originating in Russia Official Journal L 198, 23/08/1995 P.0001-0014
 - d. COMMISSION REGULATION (EC) No 823/95 of 10 April 1995 imposing a provisional anti-dumping duty on imports of disodium carbonate originating in the United States of America Official Journal L 083 , 13/04/1995 P. 0000 – 0010

- e. Council Regulation (EC) No 2025/97 of 15 October 1997 imposing a definitive anti-dumping duty on imports into the Community of advertising matches originating in Japan and collecting definitively the provisional duty imposed Official Journal L 284 , 16/10/1997 P. 0057 – 0067
 - f. COMMISSION REGULATION (EC) No 1845/98 of 27 August 1998 imposing a provisional anti-dumping duty on imports of certain large electrolytic aluminium capacitors originating in the United States of America and in Thailand
 - g. Designated Authority's Final Findings Anti-Dumping investigation concerning imports of Nylon Tyre Cord Fabric- (NTCF) from Indonesia, South Korea, Thailand and Taiwan
 - h. Anti-Dumping Investigation concerning imports of Pentaerythritol originating in or exported from China PR and Sweden
 - i. Designated Authority's Final Findings in the matter of Anti-Dumping Investigations concerning imports of 'Carbon Black used in rubber applications' originating in or exported from Australia, China PR, Iran, Malaysia, Russia and Thailand
- (xiv) Various decisions of the investigating authorities with regard to imports by applicant itself-from unrelated exporter have also been referred to, such as:
- a. Commission Decision No 307/2000/ECSC of 10 February 2000 imposing a provisional anti-dumping duty on imports of certain hot-rolled flat products of non-alloy steel originating in the People's Republic of China, India and Romania. Official Journal L 036 , 11/02/2000 P. 0004 – 0019
 - b. Commission Regulation (EC) No 1497/2001 of 20 July 2001 imposing provisional anti-dumping duties on imports of urea originating in Belarus, Bulgaria, Croatia, Estonia, Libya, Lithuania, Romania and the Ukraine, accepting an undertaking offered by the exporting producer in Bulgaria and terminating the proceeding as regards imports of urea originating from Egypt and Poland. Official Journal L 197, 21/07/2001 P. 0004 – 0027.
 - c. Commission Regulation (EEC) No 1418/88 of 17 May 1988 imposing a provisional anti-dumping duty on imports of serial-Impact dot-matrix printers originating in Japan. Official Journal L 130, 26/05/1988 P. 0012 – 0033
 - d. Commission Regulation (EC) No 165/97 of 28 January 1997 imposing a provisional anti-dumping duty on imports of certain footwear with textile uppers originating in the People's Republic of China and Indonesia. Official Journal L 029 , 31/01/1997 P. 0003 – 0018
 - e. Commission Regulation (EC) No 1069/97 of 12 June 1997 imposing a provisional anti-dumping duty on imports of cotton-type bed linen originating in Egypt, India and Pakistan. Official Journal L-156, 13/06/1997 P. 0011–0033
 - f. Commission Regulation (EC) No 1023/97 of 6 June 1997 imposing a provisional anti-dumping duty on certain imports of flat pallets of wood originating in Poland and accepting undertakings offered from certain exporters in connection with those imports. Official Journal L 150 , 07/06/1997 P. 0004 – 0017
 - g. Commission Regulation (EC) No 255/2001 of 7 February 2001 imposing a provisional anti-dumping duty on imports of integrated electronic compact

- fluorescent lamps (CFL-i) originating in the People's Republic of China. Official Journal L 038 , 08/02/2001 P. 0008 – 0021
- h. Commission Regulation (EC) No 1833/98 of 25 August 1998 imposing a provisional anti-dumping duty on imports of bicycles originating in Taiwan. Official Journal L 238 , 26/08/1998 P. 0010 – 0026
 - i. Designated Authority's Final Findings in the matter of Anti-Dumping (Sunset Review) investigations Metronidazole originating in or exported from China PR
 - j. Designated Authority's Final Findings in the matter of Anti-Dumping investigations concerning import of Seamless Tubes from Austria, Czech Republic, Russia, Romania and Ukraine.
- (xv) The decision of other investigating authorities with regard to imports by applicant itself from other than the subject country referred to by the applicant is:
- Council Regulation (EC) No 769/2002 of 7 May 2002 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of coumarin originating in the People's Republic of China. Official Journal L 123, 09/05/2002 P. 0001 – 0009.
- (xvi) The decision of the investigating authorities with regard to imports by affiliated company in India from related exporter referred to by the applicant is:
- Commission Regulation (EC) No 362/1999 of 18 February 1999 imposing a provisional anti-dumping duty on imports of steel ropes and cables originating in the People's Republic of China, India, Mexico, South Africa and the Ukraine and accepting undertakings offered by certain exporters in Hungary and Poland Official Journal L 045 , 19/02/1999 P. 0008 – 0025.
- (xvii) The decision of the investigating authorities with regard to imports by affiliated company in India from unrelated exporter referred to by the applicant is:
- Council Regulation (EC) No 2320/97 of 17 November 1997 imposing definitive anti-dumping duties on imports of certain seamless pipes and tubes of iron or non-alloy steel originating in Hungary, Poland, Russia, the Czech Republic, Romania and the Slovak Republic, repealing Regulation (EEC) No 1189/93 and terminating the proceeding in respect of such imports originating in the Republic of Croatia Official Journal L 322, 25/11/1997 P. 0001-0024.
- (xviii) Various decisions of the investigating authorities with regard to relationship with exporter exported during POI that have been referred to by the applicant are:
- COMMISSION REGULATION (EC) No 1742/2000 of 4 August 2000 imposing a provisional anti-dumping duty on imports of certain polyethylene terephthalate (PET) originating in India, Indonesia, Malaysia, the Republic of Korea, Taiwan and Thailand
 - COUNCIL REGULATION (EC) No 173/2000 of 24 January 2000 terminating the anti-dumping proceedings concerning imports of certain large

- aluminium electrolytic capacitors originating in Japan, the Republic of Korea and Taiwan
- Commission Regulation (EC) No 1472/2000 of 6 July 2000 imposing a provisional anti-dumping duty on imports of Polyester Staple Fibres originating in India and the Republic of Korea Official Journal L 166, 06/07/2000 P. 0001- 0013
 - Final Findings in the matter of Anti-dumping investigation concerning import of Para Cresol originating in or exported from People's Republic of China.
- (xix) Various decisions of the investigating authorities with regard to cases where the domestic industry is related to exporters but no exports has been made during the POI that have been referred to by the applicant are:
- Council Regulation (EC) No 771/98 of 7 April 1998 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of tungsten carbide and fused tungsten carbide originating in the People's Republic of China Official Journal L 111 , 09/04/1998 P. 0001 – 0009
 - Council Regulation (EEC) No 535/87 of 23 February 1987 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of plain paper photocopiers originating in Japan Official Journal L 054, 24/02/1987 P. 0012 – 0035
- (xx) The cases, wherein one of the producer was related to one of the exporter, that have been referred to by the applicant are:
- Gas-Fuelled, non refillable pocket flint lighter originating in Thailand.
 - Certain tubes or pipe fittings of Iron & Steel, originating in China PR, Croatia and Thailand.
 - Polyethylene terephthalate (PET) film from India, Indonesia, Malaysia and Korea RP.
 - Synthetic Staple Fibre of Polyester from Australia, Indonesia and Thailand.

D.2 Views of the importers, consumers, exporters and other interested parties

16. Following submissions have been made by the Indian Spinners Association, Rajasthan Textiles Mills Association and PT South Pacific Viscose – Indonesia with regard to 'standing' of the domestic industry:
- The initiation of investigation in this case is without jurisdiction as the applicant has related companies in the subject countries. Further, since PT Indo Bharat Rayon, Indonesia, a wholly owned company of the applicant has been found to be dumping, the applicant is not eligible to file the present application under the Rules and the jurisprudence on the subject. The injury to the sole domestic producer under such circumstances is, at best, a self-inflicted injury which ought not to be protected by way of anti-dumping duty. Further, the Indian producer and its subsidiary in Indonesia have colluded to ensure that the other competitors are first forced to lower

their prices and then the Indian arm brings an anti-dumping investigation with the sole objective of blocking fair competition in the Indian market. It is submitted that the process of anti-dumping investigations should not be allowed to be so brazenly abused by the sole monopoly producer in India.

- The fact that the related entity of the applicant is seeking determination of individual dumping margin goes against the object and purpose of introduction of deeming fiction in Rule 2(b) which contemplates exclusion of such producers who are related to the exporters, if the Designated Authority deems it fit. Exercise of discretion in favour of Domestic Industry would be an antithesis to the object and purpose of introduction of deeming fiction in Rule 2(b).
- The entire issue of related party transactions goes by the doctrine of "Single Economic Enterprise". In the US Hot Rolled Steel, paragraphs 141-158; Ref. WT/DS-184/AB/R, the Appellate Body has held that "There are many reasons relating to corporate law and strategy, and to fiscal law, which may lead to resources being allocated, in these ways, within a single economic enterprise".
- Under the EC jurisprudence and academic literature, the authorities exclude the domestic producer from the definition of "Domestic Industry" if they find
 - (i) that the related exporter had participated in the dumping practices, or
 - (ii) that the related exporter provoked or contributed to a fall in prices in the market.
- As per the EC jurisprudence related producers which fulfill any of the two conditions above, would have to be excluded from the definition of Domestic Industry. However, in the instant case both the conditions are met as related exporter from Indonesia has significantly higher dumping margin than the other cooperated exporter from Indonesia and a detailed analysis would indicate that the related exporter himself had contributed to the price fall. In view of the above also, there is no question for not to exclude the applicant from the purview of the domestic industry.
- Quantum of imports cannot be a decisive factor for exercising discretion. There are no criteria in Rule 2(b) in this regard.
- The Application proforma does not ask about import volume. It does ask only about relationship.
- Various cases referred to by the applicant deal with the situation, wherein applicant themselves imported the product concern, which is not the situation in the present case.

D.3 Examination by the authority

17. At the time of the initiation of this investigation, Rule 2(b) of the AD Rules read as follows:-

"(b) "domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves

importers thereof in which case such producers may be deemed not to form part of domestic industry".

- 17.1 However, post initiation, this Rule has been amended as follows:

"(b) "domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term 'domestic industry' may be construed as referring to the rest of the producers only"

- 17.2 Thus, Rule 2(b) of the AD Rules provides that domestic producers which are related to the exporters or importers or which are themselves importers of the allegedly dumped articles may be excluded when determining the domestic industry in certain situations.

As the use of the word 'may' in Rule 2(b) suggests, the two types of producers in question, i.e. related producers and producers importing the dumped product, are not automatically excluded from being part of the domestic industry. Rather, it is the consistent practice of the investigating authorities that the exclusion of such producers must be decided on a case-by-case basis, on reasonable and equitable grounds, and by taking into consideration all the legal and economic aspects involved.

- 17.3 The question of excluding or including a domestic producer from the ambit and scope of the domestic industry is of practical importance as the question arises whether or not they are really part of the domestic industry in the sense of Rule 2(b) of the AD Rules. This in turn may have an effect on the standing of the application i.e. whether or not their (the domestic producers that have filed or supported the application) production reaches the necessary level of representativity as stipulated under the AD Rules; as the output of domestic producers, which are excluded from the definition of the domestic industry because of their relationship to exporters or importers; or because of their own dumped imports, will not be taken into consideration while calculating total domestic production and when determining if the applicant along with supporting domestic producers represent a major proportion of such production.

- 17.4 The Authority notes that Rule 2(b) has been amended twice. The Rule 2(b) as enshrined in the AD Rules as on 1.1.1995 provided no discretion to the Designated Authority in such situations where one or more domestic producer has imported the product under consideration or is related to an importer or exporter of the product under consideration. However, WTO Agreement on Anti Dumping and Municipal laws of other investigating authorities vested a discretion to the investigating authorities in such situations, which were to be applied on a case by case basis. Rule 2(b) was amended with effect from 15th July 1999 vide Customs Notification No.44/1999 (N.T.) vesting discretion to the Designated Authority in such situations, which could be applied on case by case basis. Rule 2 (b) has further been amended recently as stated above. The Authority considers that this discretion is consistent with meeting the situations wherein:-

(a) Some domestic producers may not wish to support an anti-dumping application merely because they themselves are importing the product, or they are related to an importer or exporter of the product. Such domestic producers may even wish to force closure of other domestic producers in order to eliminate competition through unfair practice of dumping. One reason for vesting the discretion in the Authority could be to exclude such related entities, who may seek to thwart an attempt by the remaining domestic producers to seek redressal of injury caused to them on account of dumping by filing an anti-dumping application and seeking suitable relief against the unfair trade practice of dumping. If it were not so, the remaining domestic producers may not be able to meet the 'Standing requirement' as stipulated in the law to file an anti-dumping application and seek suitable remedy against the unfair trade practice of dumping. In short, the Authority considers that there was a need to exclude certain entities from the scope of domestic industry in order to enable the Authority to address injurious dumping in the Country.

(b) One or more of the domestic producers might have imported the product under consideration or their related company might have imported or exported the product under consideration for one or more *bona-fide* reasons. Some of these reasons are listed below:

(i) imports made under advance license in order to compete in the international market in the downstream product;

(ii) imports made at the time of temporary suspension of production (due to variety of *bona-fide* reasons, such as fire, strike, natural calamities etc);

(iii) imports made to supplement the product line by importing a particular type which the applicant may not be producing and which might constitute a very small portion of its total business operations;

(iv) imports made for testing, research & development, seed-marketing purposes (imports of the product to test the quality and other parameters when faced with low priced imports);

(v) imports of the part of the product which does not form the core activity in the manufacturing of the product.

Axiomatically, the Authority considers that it would be inappropriate to exclude such *bona-fide* domestic producers from being treated as domestic industry.

17.5 Thus, the Authority is of the view that the modified Rule provides discretion to the Authority in the above mentioned situations. In other words, the AD Rules have been amended to provide discretion to the Authority to include a domestic producer in certain situations or to exclude a domestic producer in certain situations.

17.6 The Authority has relied upon the jurisprudence available on the subject that suggests the circumstances in which a related domestic producer may be included or excluded as follows:-

- (a) one of the important factor in this regard is the balance of business of the domestic producer between manufacturing and importing. If the company predominantly manufactures the product in India, it should be included. However, if the domestic producer closes or reduces its production and instead imports the product or the general emphasis of its business shifts from production to imports, it should be excluded.
- (b) if a domestic producer has shielded itself from the effect of dumping by resorting to imports or exports to a related party, the company must be excluded.
- (c) if a domestic producer has participated in some way in the dumping practices or has otherwise unduly benefitted from it, it must be excluded.
- (d) if inclusion of a domestic producer would distort the injury findings, it must be excluded.
- (e) if a domestic producer does not cooperate with the Authority, the Authority tends to consider such domestic producer as ineligible.

17.7 The Authority also notes that the text book written by M/s. Czako, Human and Miranda; *inter alia*, mentions the criteria applied by the other WTO members in such situations as follows:-

- (a) The percentage of domestic production of the product in question that is accounted for by the related producers.
- (b) Whether imports of the product in question by the related producers allow them to benefit, or serve to shield them, from the effects of dumping.
- (c) Whether exclusion of the related parties would unduly skew the data for the remaining members of the industry.
- (d) The level or long term nature of the commitment shown by the producer to the domestic production, as opposed to importing activities.
- (e) The ratio of import shipments to domestic production for the related producers.

17.8 The Authority considers that the purpose of the discretion to include or exclude certain domestic producers is to enable the Authority to come to an objective and undistorted determination with regard to the effects of dumped import on the domestic industry in India by excluding those domestic producers from the relevant domestic industry which have participated in injurious dumping. The Investigating authorities may exclude a related producer, where the related parties either:

- (a) provoked or contributed to a fall in prices on the market,
- (b) are shielded from their effects, or
- (c) where they benefitted unduly from them.

With regard to the first category, i.e. the participation in dumping practices, the Authority considers that several typical situations may be distinguished. On the one hand, the

exclusion is indeed appropriate where the injury of a domestic producer is self-inflicted because imports from dumped producers reduced the use of domestic producers' own capacity, or resulted in the abandonment of domestic producers' projects designed to increase their own production.

17.9 The Authority further considers that exclusion of a domestic producer is *prima facie* not appropriate, if its participation in the dumping was an act of self-defence. Such a domestic producer should, therefore, be taken into account when defining the relevant domestic industry.

17.10 The Authority considers that domestic producers that import the dumped product or whose related exporter exports the dumped product or whose related importer imports the dumped product do not unduly benefit from dumping practices, if these imports do not represent a significant part of their sales or market size. Indeed, no advantage occurs to such domestic producers because of the competition from other suppliers in the market. The Authority also notes that another distinction drawn by the Investigating authorities of other countries while deciding whether a domestic producer should be excluded is: Is the domestic producer merely supplementing its domestic production with some dumped imports or whether it is primarily an importer with relatively limited production? The Authority considers that in the latter case, such company should be excluded from the scope of domestic industry. Another element which can be considered is whether or not the domestic producer in question is committed to production in the country of imports.

17.11 While disputing the claim of M/s Grasim Industries Ltd to treat it as the domestic industry, the opposing interested parties have contended that M/s Grasim Industries Ltd should be treated as ineligible for consideration as the domestic industry. Reference has also been made to WTO Appellate Body's decision in the matter of US Hot Rolled Steel Case, which is in the context of determination of normal value and deals with the treatment of transactions between related parties.

17.12 After careful examination of the legal provisions and facts of the case, the Authority notes that facts on record do not justify exclusion of M/s Grasim Industries Ltd from considering it as the domestic industry in the instant matter. The opposing parties have argued that the cases referred by the domestic industry are not relevant to the present situations. It is, however, noted that the cases relied upon by the domestic industry are not limited to those situations where the applicant company(s) had imported the product under consideration. The applicant has referred to some decisions wherein one of the domestic producers was related to exporter from subject or non-subject countries and it was found by the investigating authorities that inclusion of such domestic producers within the category of domestic industry was justified.

The contention of the opposing parties that the domestic industry is ordinarily to be excluded is not borne out either from a plain reading of the law or from the jurisprudence on the subject.

17.13 The Authority notes that the relevant provision defining the domestic industry grant discretion to the Authority to either include or exclude a related domestic producer from its consideration as a part of the domestic industry. The Authority notes that in a situation where the applicant is related to a producer in the exporting country, the mere fact of such relationship does not lead to automatic exclusion of such producer from the ambit and scope of the domestic industry. Indeed, discretion has been granted to the Authority in such cases to examine further on case by case basis and consider whether such a related producer should be considered as eligible or ineligible to be considered as a part of the domestic industry. Axiomatically, the impact of relationship on the facts of the case needs to be appreciated for this purpose. For this purpose, the Authority, *inter alia*, considered the followings:-

- (a) Is the behaviour of the related parties distinct and different as compared to unrelated parties;
- (b) Whether there is some evidence to show that such related producer triggered or intensified dumping in the Indian market;
- (c) Is the related domestic producer shielded from effects of dumping or unduly benefited from it;
- (d) Is the related domestic producer seeking to stifle the competition in the Indian market;
- (e) Is there a case of self-inflicted injury?

17.14 The Authority considers that apart from being a related party, it is also pertinent to evaluate the impact of the exports, if any, made by the related party in a given case. Whether such related party had exported the product to India during the period, if so, what is the impact thereof on the claims of injury? If not, whether there is any other ground still justifying its exclusion. In case the related party has also exported the subject goods, then the following also need to be evaluated:

- The volume of exports made by such related party;
- The purpose of such exports made by the related party;
- Whether there is any evidence to show that injury to the domestic industry was attributable to such exports by the related party;
- Whether the general emphasis of the related domestic producer was on the production of the subject goods or whether the general emphasis gradually or steadily shifted to imports;
- Whether the volume of exports by such related parties were such that the related exporter is gradually or steadily substituting the unrelated domestic producers' market;
- Any other factor which might have been brought to the notice of the Authority by the interested parties during the course of the proceedings.

17.15 PT South Pacific Viscose has, *inter alia*, argued that they have been forced by PT Indo Bharat Rayon to resort to dumping, that is, they have resorted to unfair competition in the form of dumping because the other party was dumping. The Authority, however, notes

that reasons for dumping are entirely irrelevant under the law and it is only the factum of dumping that is relevant. Only existence and degree of dumping is relevant in an anti-dumping proceeding and the reasons leading to such dumping are not material. Even if one or more foreign producers (from the same or different countries) have been forced to resort to dumping by one or more other foreign producers, the law does not condone the same. Besides, on facts of the case, this allegation was found to be false, as PT South Pacific Viscose had exported the subject goods much earlier than the shipments exported by PT Indo Bharat Rayon. The volumes of exports made by PT South Pacific Viscose are significantly higher than the volume of exports made by PT Indo Bharat Rayon. PT South Pacific Viscose was found to be selling the product concerned even in its domestic market at a loss and therefore, the allegation that they resorted to dumping because the other party was dumping is not based on the facts.

17.16 The opposing interested parties have further argued that the Authority should not permit the process of anti-dumping to be abused by the "sole monopoly producer" in India. The Authority, however, notes that 'dumping' is an unfair trade practice and must be condemned if it causes injury to an established domestic industry, even though there is only one domestic producer; as the intent of anti-dumping duty is only to redress the injury caused to the domestic industry on account of the unfair trade practice of dumping. Imposition of the duties shall not restrict the rights of foreign producers to sell the subject goods at un-dumped prices in the Indian market.

17.17 The Authority further notes that neither the Indian law nor the WTO Anti-dumping Agreement provides that the Authority should hold a domestic producer as ineligible if it is related to foreign producer in case such related foreign producer participates in the investigation and positive dumping margin is established in respect of its exports. Further, an individual dumping margin is required to be determined in respect of each known exporter and the Act and the AD Rules do not make any distinction between a related and unrelated exporter in this respect. As regards deeming fiction under Rule 2(b), the same unambiguously vests discretion in the Authority in such a case. Such discretion, however, needs to be exercised in an un-biased and objective manner.

17.18 The Authority notes that the opposing interested parties have erred while contending that the criteria based on quantum of exports is not a rational criterion. As the issue at hand is "exports" made by a related exporter, the Authority considers that the quantum of imports is indeed an important factor to decide the exclusion of the related domestic producer. Further, it would, *inter alia*, be one of the factors in assessing whether the injury claimed is a self-inflicted injury or otherwise.

17.19 The Authority notes that in the instant case, M/s Grasim Industries Ltd. has affiliated companies in Indonesia and China PR producing & selling the product concerned, namely Birla Jingwai Fibres Company Limited, China PR and PT Indo Bharat Rayon, Indonesia. PT Indo Bharat Rayon - Indonesia have also filed their detailed response to the questionnaire sent, which has been verified by the Authority and has been dealt

appropriately in the relevant sections of these findings. PT Indo Bharat Rayon is not a subsidiary of M/s Grasim Industries Ltd. It is noted that M/s Grasim Industries Ltd holds only *** % shareholding in PT Indo Bharat Rayon, Indonesia and ***% in Birla Jingwai Fibres Company Limited, China PR. M/s Grasim Industries Ltd. is the sole producer of the subject goods in India and has claimed injury on account of the dumped imports from the subject countries. Despite being a related party, the Authority did not notice any difference in its behaviour, were it not a related party. No evidence was found by the Authority in respect of stifling the competition by M/s Grasim Industries Ltd. or taking any other undue advantage by seeking application of the anti-dumping duty in the instant matter.

- 17.20 Besides, the volume of exports made by PT Indo Bharat Rayon is quite small and sporadic in nature; these imports have been made by the unrelated importers under duty exemption category. M/s Grasim Industries Ltd has not imported the subject goods. The Authority notes in this regard that in a situation where majority of the exports are by other unrelated Indonesian exporter and where only three sales transactions (during the period of investigation) took place between PT Indo Bharat Rayon and Indian importer/consumer, that too for imports of the material under duty exemption scheme, it could not be concluded that the parties colluded to force other competitors out of Indian market. The Authority also notes that there is no evidence whatsoever provided by the interested parties establishing that the two parties have colluded. Further no evidence has been provided to establish that the unrelated Indonesian producer has been forced to lower the prices due to alleged low prices quoted by PT Indo Bharat Rayon. The allegation by PT South Pacific Viscose, *inter alia*, that dumping was provoked and triggered by PT Indo Bharat Rayon – Indonesia was looked into during the verification of the two companies and was found to be unfounded and incorrect. This view is further buttressed by the analysis of imports of the subject goods from Indonesia, as seen in the following table.

	Imports in MT		Total Imports	Share of	Share of
	PT Indo Bharat Rayon Exports	PT South Pacific Viscose Exports	From Indonesia	PT Indo Bharat Rayon	PT South Pacific Viscose
2006	-	***	***	0.00%	100.00%
2007	***	***	***	5.51%	94.49%
2008 Jan-June	-	***	***	0.00%	100.00%
POI	***	***	***	2.29%	97.71%

- 17.21 Further, the Authority examined the share of Indonesia in respect of imports of the product under consideration in India. It was found that whereas imports from Indonesia were only about 38% of total imports into India in 2006-07, the same increased to 74% in 2007-08, 93% in April-June, 2008 and 84% during POI. It is thus evident that share of

Indonesian imports steadily increased in gross imports of the subject goods in India. Further, share of PT South Pacific Viscose was very high in these imports from Indonesia as may be seen from the following table:

	Gross Imports in India	Imports from Indonesia	Share of Indonesia in gross imports	Export by PT South Pacific Viscose	Share of PT South Pacific Viscose in total imports
2006-07	6,774	2,554	37.70%	***	29.02%
2007-08	6,842	5,069	74.09%	***	71.67%
April-June08	1,890	1,757	92.95%	***	92.95%
POI	6,329	5,305	83.82%	***	81.90%

17.22 With regard to the WTO decision referred to by the interested parties, the Authority notes that the issue in that case is not relevant to the present case. The issue in that case was whether the transactions between the affiliated parties could be considered as transactions in the ordinary course of trade for the purpose of determination of normal value. Thus, while the issue in that case arose in the context of normal value and transactions between related parties; the issue under consideration in the present case is whether M/s Grasim Industries Ltd. should be held as ineligible as a domestic industry within the meaning of Rule 2(b) in view of its relationship with its affiliates in the subject countries. It is also relevant to note that even in the context of determination of normal value; all transactions between the related parties may not be treated as reliable or unreliable and thus is to be examined on the merits of each case. Whereas in the instant case, the transactions are not even between such related parties but are between PT Indo Bharat Rayon and unrelated Indian consumers.

17.23 PT South Pacific Viscose has, *inter alia*, argued that the domestic industry and PT Indo Bharat Rayon's objective was to block fair competition in the Indian market. However, given the positive dumping margin that has been established in the instant case, it is evident that the unrelated Indonesian producer did resort to dumping, which has been found to be unprovoked and not due to the three small shipments made by PT Indo Bharat Rayon. Significant volume of the subject goods have been exported by PT South Pacific Viscose at dumped prices. The Authority on investigation has come to the conclusion that dumped imports of the subject goods from the subject countries have caused 'injury' to the domestic industry, as may be seen from the relevant sections of these findings. The Authority further notes that small and sporadic exports have not been a significant factor in such injury. Besides, the focus of M/s Grasim Industries Ltd continues to be production and sale of the subject goods. Thus, there does not appear to be case of self-inflicted injury. The Authority has also taken note of anti-dumping cases, wherein even though the imports were effected by the related domestic producer from its affiliate, then too they have been considered by the investigating authorities as a part of the domestic industry. Thus, the Authority does not find any justifiable reason to exclude M/s Grasim Industries Ltd from the ambit and scope of the domestic industry.

- 17.24 The Authority therefore, reiterates that the Applicant is not required to be excluded from the scope of the domestic industry under Rule 2(b) of the AD Rules. Thus, the application has been filed by Association of Man Made Fibre Industry of India on behalf of the domestic industry. M/s Grasim Industries Ltd. is the sole producer of the Like Article in India and has provided injury and costing information. The claim of the applicant that there is no other producer of the Like Article in India has not been disputed by any interested party. As per the evidence available on record, the production of M/s Grasim Industries Ltd. accounts for a major proportion of the domestic production of the subject goods, as M/s Grasim Industries Ltd. is the sole producer of the subject goods in India.
- 17.25 Thus, the Authority reiterates its view that it is appropriate to consider M/s Grasim Industries Ltd. as the domestic industry under Rule 2(b) of the AD Rules. Accordingly, the Authority has determined that the application satisfies the requirements of Rule 2(b) and Rule 5(3) of the AD Rules.

E. Other issues

E.1 Submissions made by Indian Spinners Association, Rajasthan Textiles Mills Association and P T South Pacific Viscose

18. Following submissions have been made by Indian Spinners Association, Rajasthan Textiles Mills Association and P T South Pacific Viscose:

- They have objected to the data collected by domestic industry from secondary source. They consider that it was bounden responsibility of the Applicant to give official data. Since data given by the Applicant is not official, conclusion reached by the applicant is wrong.
- Product concerned has dedicated customs code; therefore, consideration of secondary source as basis of imports is not justified. DGCI&S data shows much higher volumes compared to secondary source and at higher prices.
- There have been imports from other countries as per DGCI&S; however, the Applicant claims that no imports have been made from other than the subject countries.
- Due to recessionary conditions, the consumption of the fabric has been greatly affected all over the world and it has impacted prices of not only fabrics but also yarn and fibre including viscose staple fibre.
- The Applicant has always operated on full capacity except when there is water shortage at its NAGDA plant. But in 2008-09 because of recession, it has closed down its Kharach Plant and capacity utilization is also affected.
- Average CIF price of imports during the POI is higher than the average CIF price of 2007-08.
- Basic problem with the domestic industry is continuous increase of capacity without taking into account changing of trends.
- The Applicant has vast resources and worldwide contacts, must be on front foot to help spinning industry.

- The Applicant is the sole producer of the product concerned in India. The imposition of anti-dumping duty will create monopolistic situation in favour of Grasim and their group companies, which has large VSF capacities in other countries including Thailand.
- Six month period of investigation is too short for assessment and analysis of dumping and injury to the domestic industry. Trade notice issued by the Designated Authority earlier also clearly mandates that the period of investigation should normally be twelve months. DGAD practice is to determine POI as financial year. While determining POI, factors like financial reporting, availability of data/information, characteristics of product, seasonality, cyclicity etc are not taken into consideration. The selection of 6 months period of investigation is also contrary to guidelines of the Committee on Anti-Dumping Practices.
- Out of six months of POI, world has faced unprecedented financial crises, hence the industry suffered. In fact, the practice of normally taking a year as the period of investigation is precisely to ensure that no anti-dumping investigations are initiated due to short-term fluctuations in prices. Moreover the Authority is fully aware that the shortest permissible POI of six months covers about four months when the entire world was passing through an unprecedented economic and financial crisis in which the fabric and consequently the yarn and the fibre industry suffered considerably. It is an admitted fact that there was a substantial fall in demand in an otherwise growing market and, therefore, the Designated Authority ought not to have taken a period craftily selected by the Domestic Industry even if the same is legally permissible. It may be clarified that the issue here is not about the legality of selecting a six month POI but the propriety and appropriateness of the same.

E.2 Submissions made by the Domestic industry

19. Following are the other submissions made by the applicant:

- Period of investigation – The application contains specific reasons for consideration of six months as the investigation period. It is not even the argument of interested parties that six months investigation period is impermissible. Even the trade notice uses the word “normally” and not “always”. Relevant extracts of decision of CESTAT in the matter of HAS have been enclosed, wherein the Tribunal has clearly held that there is no bar in consideration of six months as the investigation period. As regards reasons for choosing six months period, the application contains the same. The argument to such an extent is factually incorrect.
- The notice of initiation issued by the Designated Authority contains reasons for choosing 6 months as the POI
- Decision to take six-months period as POI has been upheld by the Hon'ble Tribunal in the matter of Virchow Laboratories Ltd. v/s Ministry of Finance.
- Even the WTO Agreement contains no legal provision with regard to choice of POI.

- The application itself contains reasoning of 6 months POI. It is incorrect to state that 6 months POI is a short period. Following are some of the cases, wherein the investigation period was taken as 6 months:

Acrylic Fibre from USA, Thailand and Korea RP	April95-Sep95
Cathode Ray television picture tube	July09-Dec09
Dry Batteries	April00-Sep00
Hydrofluoric Acid	April01-Sep01
Hydroxyl Amine Sulphate	July99-Dec99
Lead Acid Batteries – Bangladesh, Japan, Korea, China PR	Sep02-Feb03
Penicillin G and Potassium 6 APA	Oct08-Mar09
Vinyl Acetate monomer	April01-Sep01
Vitrified Tiles	Sep04-Feb05
	April05-Sep05
	Sep05-Feb06

- The applicant has clearly mentioned that the information has been procured from TIPS. Such being the case, the argument that the source has not been mentioned is without basis. As regards use of DGCI&S data, the same could not have been adopted for the reason that the product under consideration does not have dedicated customs classification. The interested parties appear to have some misunderstanding that the product under consideration has dedicated customs classification. Further, transaction-by-transaction data can be available only after an application is filed before the Designated Authority. As regards comparison of DGCI&S data with the application data, since the product scope itself does not include all types of VSF, any comparison with the DGCI&S data is, at the least, misleading.
- Kharach plant of the company earlier had two production lines. Two more lines were added, which commenced production in March-April 2008 period. These capacity additions were based on the market feedback given by the consumers. In fact, the company had planned capacity expansion only upon feedback received from the customers that the product had good demand. However, because of dumping and adverse market situation, these two lines could not be fully utilized during the investigation period

E.3 Examination by the Authority.

20. The Authority has noted the submissions made by the interested parties regarding period of investigation and is of the view that the period of investigation chosen in the instant matter has been appropriately chosen considering the facts of the case, which also covers the most recent available data on the subject.
21. With regard to the period of investigation, the Authority notes that the opposing interested parties concede that fixation of 6 months period as the period of investigation is not illegal. It has, however, been contended by them that it was inappropriate for a

number of factual positions in the present case. The issue has been carefully examined by the Authority. It is incorrect to state that it is the DGAD's practice to take 12 months period as the POI; the decision to take a particular period as the POI is taken based on the merits of each case. Besides, the decision to take six-month period as POI has also been upheld by the Hon'ble tribunal in the matter of Virchow laboratories ltd. v/s Ministry of Finance.

22. As far as guidelines and practice followed by the Designated Authority or the guideline of the Committee on Anti Dumping Practices is concerned, the Authority notes that (a) in fact, the Designated Authority has adopted 6 months period of investigation in a number of cases, (b) the interested parties agree that consideration of 6 months as the investigation period is not illegal, (c) the stated guidelines cannot be read as mandatory prescription applicable in all situations, irrespective of the facts of a case. Factors such as financial reporting cannot be considered as the same would imply consideration of only one period as the period of investigation viz. April-March. With regard to reasons for considering 6 months as the period of investigation, the Authority notes that the same have been mentioned in the preliminary findings. With regard to the argument that 6 months period of investigation covers 4 months of the recessionary period, the Authority holds that the fact of recession cannot be selectively pleaded in support of export price below normal values; as the fact of recession would equally apply to normal value as well. It is, however, noted that the domestic prices of the subject goods in Indonesia were materially higher than the export price to India. Thus, recession in the global market cannot be stated as a justified reason to be considered in fixing the period of investigation.
23. As regards fall in demand, the Authority notes that the fall in demand would have equally impacted the domestic industry and imports. However, here is a situation where the demand has fallen but volume of imports from the subject countries increased. The Authority considers that 6 months period of investigation was justified in view of significant drop in import prices and significant deterioration in financial situation of the domestic industry.
24. The Authority notes that product under consideration in the present investigation is Viscose staple fibre – except bamboo fibre. The Customs' classification for the product under consideration does not exclude bamboo fibre. Therefore, summary information published by the Applicant cannot be relied upon as it may include imports of product other than product under consideration. The domestic industry has furnished information as provided by TIPS, which was accepted at the time of initiating the investigation.
25. The domestic industry has alleged that significant import volumes have been reported under Customs Sub-heading No. 5504 9090. The Authority requested the O/o DGCI&S for import information for Custom classification Nos. 55041000 and 55049090, which has been received and analysed. Accordingly, the imports volumes of the subject goods have been determined. A comparison of imports claimed by the Applicant as per TIPS data and as per DGCI&S data shows the following:

	TIPS data		DGCI&S data	
	Qty Kg	Rs./Kg	Qty Kg	Rs./Kg
China PR	907252	96.03	1023971	94.13
Indonesia	4533741	98.44	4689364	98.47

26. From the material available on record, it is seen that there are no imports of the subject goods from any other country except from the subject countries during the POI. Further, the volume and price as per DGCI&S and TIPS are broadly comparable.

F. DUMPING MARGIN

F.1 Views of the domestic industry

- As none of the exporters/producers from China PR has responded and filed any submission with regard to their claim of market economy treatment, the normal value may be determined for all exporters/producers from China PR as per Rules applicable for non-market economy country.
- Applicant has referred to para 7 of Annexure I under the AD Rules, which has been inserted by notification no. 44/99 – Cus (NT) dated 15th July, 1999. The Rules clearly provide various methods for determination of normal values in case of a non-market economy country
- Rules have been amended twice so as to provide Chinese producers liberty to establish that they satisfy market economy status, after meeting the detailed criteria laid down under the Rules.
- China PR is a non-market economy. No country has granted market economy status to China PR after following elaborated evaluation procedure. China PR has been treated as non-market economy by European Union and United States in the past three years. Even China PR agreed in the accession treaty that WTO Members could use an NME anti-dumping methodology through December 11, 2016. European Union and United States are members of World Trade Organization. In India also, the Designated Authority has treated China PR as non-market economy in practically all the investigations initiated against China PR after the amendment. Even after the amendment dated 4th Jan., 02, the Designated Authority has treated China PR as a non-market economy.
- European Commission, in the matter of Certain Compressors, Wire Rod, Certain prepared or preserved citrus fruits (namely mandarins, etc.), Certain welded tubes and pipes of iron or non-alloy steel, Citric Acid from China PR, has treated China PR as a non-market economy. USA has treated China PR as a non-market economy in the matter of anti-dumping investigations concerning imports of Barium Carbonate, Small Diameter Graphite Electrodes, Folding Metal Tables and Chairs Tapered Roller Bearings and Parts Thereof, Finished and Unfinished.
- There are 15 mandatory conditions prescribed under the Rules, each one of which an intending exporter has to satisfy in order to claim market economy treatment and the information and evidence relevant and necessary to establish such a claim. Unless the responding Chinese exporters conform to these standards, the Designated Authority is required to determine normal value in accordance with Para 7 of Annexure-I to the Rules.

- Because, none of the Chinese exporter/producer has responded, the normal value in China PR thus should be determined on the basis of (a) price in India, and (b) cost of production in India, duly adjusted, including selling, general and administrative expenses and profit.
- Dumping Margin determined by the Authority in preliminary finding was provisional estimates and based on earlier definition and understanding of the Rules. Once, the normal value is determined separately for each producer and exporter, petitioner estimates that the dumping margin for SPV would be significantly higher than determined in the preliminary finding.
- Difference in dumping margin does not mean that the IBR is setting up the prices in the Indian market. Out of 6329 MT exported in POI, IBR has exported just 121 MT, which also were invoiced in August 2008, September 2008 and December 2008. Such being the case, it is just imagination/ conjecture that SPV was forced to lower the prices because of IBR low prices.

F.2. Views of exporter/importers and other interested parties including Indian Spinners Association, Rajasthan Textiles Mills Association and PT South Pacific Viscose – Indonesia

- Dumping margin of PT Indo Bharat Rayon is 11.26%, whereas the same for PT South Pacific Viscose is just 6.30%. Dumping margin for PT Indo Bharat Rayon is almost twice of South Pacific Viscose.
- PT South Pacific Viscose has no choice but have to follow the pricing of PT Indo Bharat Rayon. PT Indo Bharat Rayon have tried to ensure that PT South Pacific Viscose produces first forced to reduce price and applicant file a case of Anti Dumping Duty.
- Claiming of individual dumping margin by PT Indo Bharat Rayon is against the purpose and object of introduction of Rule 2(b).

F.3. Examination by the Authority

27. The Authority sent questionnaire to the known exporters from China PR, advising them to provide information in the form and manner prescribed. However, no response has been received to the questionnaires from any of the Chinese producer/exporter. Some of the issues mentioned above, have already been addressed by the Authority in the relevant sections of these findings.
28. Para 7 of Annexure I of the AD Rules provides that

“In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in the market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India or where it is not possible, or on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the designated authority in a reasonable

manner, keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question, and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of selection. Accounts shall be taken within time limits, where appropriate, of the investigation made in any similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without any unreasonable delay the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments”

29. The Authority notes that in the past three years China PR has been treated as a non-market economy country in anti-dumping investigations by India and other WTO Members. China PR has been treated as a non-market economy country subject to rebuttal of the presumption by the exporting country or individual exporters in terms of the AD Rules.
30. As per Paragraph 8 of Annexure I of the AD Rules, the presumption of a non-market economy can be rebutted, if the exporter(s) from China PR provide information and sufficient evidence on the basis of the criteria specified in sub paragraph (3) of Paragraph 8 and establish the facts to the contrary. The cooperating exporters/producers of the subject goods from People's Republic of China are required to furnish necessary information / sufficient evidence as mentioned in sub-paragraph (3) of paragraph 8 in response to the Market Economy Treatment questionnaire to enable the Authority to consider the following criteria as to whether:-
 - a) the decisions of concerned firms in China PR regarding prices, costs and inputs, including raw materials, cost of technology and labour, output, sales and investment are made in response to market signals reflecting supply and demand and without significant State interference in this regard, and whether costs of major inputs substantially reflect market values;
 - b) the production costs and financial situation of such firms are subject to significant distortions carried over from the former non-market economy system, in particular in relation to depreciation of assets, other write-offs, barter trade and payment via compensation of debts;
 - c) such firms are subject to bankruptcy and property laws which guarantee legal certainty and stability for the operation of the firms and
 - d) the exchange rate conversions are carried out at the market rate.
31. The Authority notes that consequent upon the initiation notice issued by the Authority; none of the Chinese producers/exporters have submitted any response including the market economy questionnaire response and sought to rebut the non-market economy presumption. In the initiation notification itself, the Authority had indicated that the Applicant has suggested Indonesia as appropriate surrogate country. Interested parties were requested to make submissions in this regard. However, none of the exporter/producer from China PR has responded and made any submissions in this

regard. Therefore, the Authority examined whether Indonesia could be treated as a surrogate market economy for the purpose of determination of Normal value for China PR. For this purpose, the Authority took into account the level of development of Indonesia and that of the subject goods in question. It is, *inter alia*, noted that there are two major producers of the subject goods in Indonesia and incidentally both have co-operated in this investigation. It is further noted that significant domestic sales have been made by these producers in the domestic market of Indonesia. Thus, the Authority considers that it would be appropriate to treat Indonesia as an appropriate surrogate country in the instant matter. Thus, considering Indonesia as an appropriate surrogate country for China PR, the Authority has adopted the weighted average Normal value of Indonesia so determined for China PR, which works out as USD *** per Kg.

F.4 DETERMINATION OF EXPORT PRICE FOR CHINA PR.

32. As none of the producer/exporter from China PR has responded, the Authority has therefore, determined the Export price as per facts available on record. The Authority notes that the Applicant has furnished transaction-wise information as per secondary sources. Subsequently, the Authority procured the imports data from DGCI&S. The Authority has therefore determined export price for all exporters/producers from China PR based on weighted average export prices of the subject goods during the POI from China PR. The Export price has been adjusted for ocean freight, marine insurance, commission, inland freight, port expenses and bank commission, as per information available on record. The Export price so determined works out to USD *** per KG.

F.5 Normal Value in respect of exporters/ producers from Indonesia

33. The Authority sent the questionnaire to known exporters and producers of product under consideration in Indonesia and China PR. Only the following two producers from Indonesia have responded thereto and filed their responses.

- 1 PT Indo Bharat Rayon
- 2 PT South Pacific Viscose

Determination of Normal Value for Co-operating exporters and producers from Indonesia

P T South Pacific Viscose

34. P T South Pacific Viscose from Indonesia has responded and provided information. Certain deficiencies were observed in the response filed and clarifications sought. The company has furnished information relating to domestic sales in Appendix 1 and exports to India in Appendix 2. The perusal of the data shows that the company's weighted average domestic sales price is lower than the weighted average domestic cost of production. The cost of production of the respondent has been compared with the transaction-wise domestic sales and it has been found that ***% as against ***% of the

domestic sales are profitable, due to corrections made in the credit costs. Thus, the Normal value has been determined on the basis of profitable domestic sales. The adjustments on account of commission, bank charges and rebate are being allowed as noted during the spot verification. Thus, the Normal value is worked out as USD *** per KG.

Pt Indo Bharat Rayon

35. P T Indo Bharat Rayon from Indonesia has responded and provided information in the form and manner prescribed. The respondent has furnished information relating to domestic sales in Appendix 1. The respondent has furnished information relating to cost of production in Appendix 5 to 9. The Authority notes that the respondent has made profit on overall basis on its domestic sales. The cost of production of the respondent has been compared with the transaction-wise domestic sales and it has been found that ***% of the domestic sales are profitable. Thus, the Normal value has been determined on the basis of total domestic sales. The adjustments on account of transport charges, internal insurance, rebate and credit costs are being allowed, as noted during the spot verification. Thus, the Normal value is worked out as USD *** per KG

F. 6 Export price

P T South Pacific Viscose

36. The information/data submitted by the respondent and verified by the Authority is being relied upon for the determination of the export price. The respondent has claimed adjustments on account of inland transportation, ocean transportation, overseas insurance, credit costs and bank charges; the same are being accepted, as noted during the spot verification. Thus, the Authority has determined the export price for the exporter as USD *** per Kg.

Pt Indo Bharat Rayon

37. The information/data submitted by the respondent and verified by the Authority is being relied upon for the determination of the export price. The respondent has claimed adjustments on account of international freight, inland transportation, international insurance, internal insurance and other expenses; the same are being accepted, as noted during the spot verification. Thus, the Authority has determined the export price for the exporter as USD *** per Kg.

Determination of Normal Value & Export Price for Non-cooperating Exporters and Producers from Indonesia

38. No other exporter and producer from Indonesia has responded to the Questionnaire. The Authority has determined their Normal value & Export price based on the facts available on record.

F.7. Dumping margin

39. Considering the Normal values and the Export prices as determined above, the dumping margins work out as follows:

USD per Kg

	Normal Value	Export Price	Dumping Margin	Dumping Margin range (%)
Indonesia				
M/s PT South Pacific Viscose	***	***	***	5-10 %
M/s PT Indo Bharat Rayon	***	***	***	5-10 %
All Other exporters/ and producers except the two Companies mentioned above	***	***	***	30-35%
China PR				
All exporters and producers	***	***	***	10-15 %

- 39.1 The Authority notes that dumping margins from China PR and Indonesia are more than the *de-minimis* limits prescribed.

G. Injury**G.1 Submissions of exporter/importers and other interested parties including Indian Spinners Association, Rajasthan Textiles Mills Association and PT South Pacific Viscose—Indonesia**

40. It has been contended by them that:

- The decline in market share of 2.3% is meager. It may be appreciated that this small loss of market share is based on incomplete data. In any case, a drop in market share by about 2% within a short period of six months out of which bulk of the period saw macroeconomic problems, cannot be a ground of injury, let alone material injury. Further, the demand in India has significantly come down by 31813 MT over the injury investigation period whereas the alleged increase in exports is 3977 MT only. However, there are no reasons for the balance gap of 27836 MT of decline in sales of the applicant on account of the contraction in demand.
- As regards the increase in imports inspite of decline in demand, it has been contended that the orders were booked much earlier, which could not have stopped with the decline in demand, hence imports increased.
- Production & Capacity Utilization of Domestic Industry: It is submitted that the analysis is completely flawed as it does not take into account the fact that the applicant had increased its installed capacity by 25.30% during 2008-09. Obviously, it cannot be expected that the new capacity shall also operate at the same level as that of the existing capacity. Further, it appears that the fall in the national and international demand has certainly contributed to the drop in

production and the capacity utilization during the short POI which has not been factored in at all.

- It can be seen that there is no price undercutting from Indonesia and the price undercutting from China is negligible.
- The Return on Capital Employed for the product under consideration for the applicant as per their own published statements for the years 2005-06, POI and 2008-09 is 43%, 17% and 23% respectively. The industry cannot claim injury with such robust financial performance over the years including the POI. Even during the financial year 2008-09, which subsumes the short POI, the admitted ROCE for the product under consideration has been as high as 23%. It would be unfortunate if the Designated Authority decides to pick up a particularly short period for injury analysis when the performance has been exemplary during a reasonable period like a full financial year.
- Incentives are being given on deemed exports; had these sales were considered at normal price, realization would have significantly changed.
- Sales by domestic industry for eventual exports seem to have been included in domestic sales by domestic industry.
- Significant sales are made to affiliated parties; such sales needs to be examined separately and non confidential version of the same may be given.
- There is decline in demand, which have affected the domestic industry; therefore, alleged dumped imports are not responsible for injury to the domestic industry.
- Price Reduction by Domestic Industry: The applicant has stated in the application that "In view of the price reductions offered by the foreign producers, the domestic industry was forced to undertake a number of price revisions". However, it appears that these price reductions offered by the domestic industry has nothing to do with the alleged dumping of the subject goods by the subject countries. It is clear beyond any doubt that the frequent price revisions, if any, were admittedly made for reasons stated above and not because of the alleged dumping of viscose staple fibre as claimed by the petitioner.
- Pricing Policy of the Applicant: It appears that the domestic industry is offering incentives for their supplies against deemed exports in the form of rebates. As per the pricing policy of the Applicant, rebates are given if certain conditions are met with for their supplies against deemed exports. It is thus clear from the scheme that the petitioner is offering incentive schemes in the form of rebates from the basic price of the subject article offered to the customers. The Authority would appreciate that had the subject article been offered to customers for normal domestic sale, the price charged by the petitioner would have been higher. It has been observed that the price charged for the supplies against deemed exports are much below the prices charged for the domestic sales. This may be seen from the price lists of the petitioner. It therefore, appears from the pricing strategy and policy of the domestic industry that certain sales made to customers for eventual exports have also been included under domestic sales for the purposes of injury analysis. Inclusion of known export sales for injury analysis is inconsistent with the anti-dumping rules and regulations. It may be seen that the applicant is fully aware that the subject goods are meant for eventual exports and therefore it

follows a different pricing policy to ensure that the export market is not lost. This has nothing to do with its performance in the domestic market which is the requirement of law. The domestic industry cannot take shelter of injury under alleged dumping when the so-called injury may have been caused due to its own pricing policies. Thus, there is clearly absence of causal link between alleged dumping and injury to the petitioner.

- It is further contended that the domestic industry has suffered injury on account of decline in profitability due to the alleged dumping of the subject goods from the subject countries. A careful analysis of the various annual reports and performance review of the domestic industry shows that the lower profitability of the company is mainly due to increasing input costs, lower volumes and weak margins. Moreover, it may be seen from the submissions made by the domestic industry in pro-forma IVA that the interest and depreciation component of cost appears to be very high which may also be one of the reasons of lower profitability. It is abundantly clear that even if it is assumed that the domestic industry might have suffered some temporary slowdown of their profitability the same cannot be attributed to the alleged dumping of the subject goods.
- The domestic industry, despite the restrained outlook, expended its capacity in March 2008; it is not possible for any industrial unit to achieve same level of capacity at the very beginning of operations.
- The sales volume declined but not because of alleged dumping.
- The domestic industry is continuing with its expansion project despite the alleged dumping of the subject goods and the global recession. Therefore, there is no injury to the domestic industry so far investment and expansion program are concerned.
- There is no evidence given with regard to threat of any material injury.
- The domestic industry follows a pricing policy through which it gives a substantial rebate. The Designated Authority should analyze the pricing policy before accepting any claim of injury to the domestic industry.
- Major imports from Indonesia are against advance license.
- The petitioner is selling significant volumes in the domestic market on deemed exports basis on which significant discounts are being offered by the petitioners. These sales are not domestic sales and should be excluded from the domestic sales for the purpose of the present investigation.
- The company is offering significant discounts in sales in domestic market, which is evident from the price list of petitioners itself. Injury to the domestic industry, if any is on account of its own pricing policy and not due to alleged dumping.
- There is no injury on account of employment as the level remains virtually the same.
- Wages & Productivity: Since no information has been provided for wages per capita, we presume that there is no injury on account of this fact. For productivity, it is submitted that if the production comes down due to other factors and productivity is simplistically defined as production per capita, the downward trend is obvious but this is of no consequence. It is further submitted that this

factor would be relevant in cases where there is significant mobility of labour which is not true in case of India.

- There is no causal link between the alleged dumping and injury to the domestic industry. The injury to the applicant was at best self-inflicted or clearly attributable to factors other than dumping. The domestic industry itself, in its annual report and various performance review reports has accepted the fact that the deterioration in production, sales and profitability is due to lower demand, prevailing global downturn coupled with steep rise in input costs and weakening of Indian Rupee. Thus, the conclusion of material injury to the domestic industry due to the alleged dumping of subject goods is based on mere conjectures.

Submissions of the domestic industry

41. It has been contended by the domestic industry that:

- The margin of dumping from each of the subject countries and volume of imports from each of the subject countries is more than the limits prescribed.
- Cumulative assessment of the effects of imports is appropriate since the exports from the subject countries directly compete with the like goods offered by the domestic industry in the Indian market
- There are common parties/customers who are resorting to the use of imported material from various sources and domestic material. Imported and domestic material is being used interchangeably and there is direct competition between the domestic product & imported product and inter-se imported product
- Market share of imports from each of the subject countries is more than *de-minimis*. Volume of imports from each of the subject countries is significant.
- Domestic producer and exporters from the subject countries sell the like product to the same category of customers and both are competing in the same market. Both are being used by the consumers interchangeably.
- The demand for the product under consideration was increasing till 2007-08. The same has, however, declined (on proportionate basis) in the investigation period. However, whereas the demand for the product under consideration has shown decline in the POI, import volumes have increased by more than 50% (on proportionate basis). A natural impact of decline in demand should have been decline in imports as well on proportionate basis. However, the dumped prices offered by the Foreign Producers led to a situation where the demand for the product under consideration declined, but import volumes increased.
- Imports from subject countries increased significantly in absolute terms.
- Imports from the subject countries increased significantly in relation to total imports of the subject goods in India.
- Imports increased significantly in relation to production in India.
- Imports increased significantly in relation to consumption in India.
- In view of price reductions offered by the Foreign Producers, the domestic industry was forced to undertake a number of price revisions.

- The volume of imports would have been far more than the present and indeed devastating, had the domestic industry not taken preventive prudent action by reducing the prices.
- Given the capacity and demand in the Country, any flooding of imports would have had a very devastating impact on the established domestic industry.
- The domestic industry has no option but to keep aligning its prices to the prices offered by the Foreign Producers in the market. The current increased volume of imports must be seen in the light of these price revision steps taken by the domestic industry.
- It would be seen that the landed value of imports from the subject countries are lower than the net sales realization of the domestic industry thereby establishing that the imports are undercutting the selling price of the domestic industry.
- Cost of production was increasing over the injury period; selling prices increased up to 2007-08, but declined in POI.
- The domestic industry has been forced to reduce the selling prices significantly.
- The sales and consequently production and capacity utilization were improving till 2007-08, the same have declined thereafter in POI
- Profitability and consequently profits on gross domestic sales, return on investment and cash profits were improving till 2007-08, but declined steeply in the period of investigation due to increase in dumped imports from subject countries and offers for sale at further reduced prices.
- Return on capital employed and cash profits show the same trend as that of profits. The return on capital employed is at low levels in a situation where some of the investments of the domestic industry are fairly old and significant assets are largely depreciated by now.
- So significant has been the decline in the profitability that the company had abysmally low level of cash profits in the last quarter of POI.
- The domestic industry has in fact faced financial losses in the production and sale of the product under consideration in the investigation period. In other words, while the captive inputs continued to be profitable even during the alleged recession period, so significant was the dumping that the producers started pricing VSF below the cost of production.
- The market share of the domestic industry declined and that of subject imports increased. Domestic industry lost market share to imports from the subject countries.
- Current level of reduced market share must be seen along with the price reductions affected by the domestic industry. Had the domestic industry maintained its prices at the same level to protect its profitability, it would have suffered significantly higher loss of market.
- Inventory levels of the domestic industry declined till 2007-08 and increased again thereafter. Inventory with the domestic industry increased significantly. In fact, so significant was the increase in inventories that the petitioner had to decide to resort to production cuts.
- The growth of the domestic industry was positive up to 2007-08. Growth has become negative in POI with increased competition from imports. Growth on

account of production, sales, capacity utilization, market share, inventories was positive up to 2007-08 and became negative in POI. In spite of the same, inventories increased very significantly. In value parameters, growth in profits, return on investment and cash flow was positive up to 2007-08 and became negative in POI.

- Further, the domestic industry has collected transaction wise information of imports in post POI (table below). It may be seen that there is further decline in prices from the subject countries

	Jan-Mar 09 USD KG	Apr-Jun 09 USD KG
China PR	1.57	1.57
Indonesia	1.79	1.65

- There is further decline in export price from the subject countries in post POI period. In fact, these are the orders booked at the end of POI and must therefore have been included in the questionnaire responses of the responding exporters.
- Increase in export price between 2007-08 and POI –there was increase in the raw material cost in POI over 2007-08, as would be seen from the table below. This led to increase in the export price.

Rs./kg	2007-08	POI	Change
Raw material	***	***	12.6
Import price			
China PR	107.09	94.13	-12.96
Indonesia	94.55	98.47	3.92

It would be seen that whereas raw material cost in POI increased by 23.48%, export price from China PR declined by 12.10%, which the same increased by just 4.14% in case of Indonesia.

- Requirement of causal link under the Rules – the interested parties seems to have been interpreting the Rules to mean that the sole cause of injury must be dumped imports. This is not, however, the requirement. Under the Rules, one of the principal causes of injury must be dumped imports. The fact that the domestic industry prices its product based on import prices and the fact that the domestic industry has been forced to resort to price revisions downwards, that too more frequently than the normal, itself establishes that dumped imports are causing injury to the domestic industry.

42. Regarding the issue related to deemed exports sales and significant discount offered by the domestic industry on such sales, domestic industry has stated as under:

- The domestic industry follows a well laid down pricing policy. The domestic industry declares and sells the product as per “price list”. The prices are not

negotiated for each sale transaction. The domestic industry does not follow a system of responding to trade enquiries, giving quotations, price negotiations, procurement and execution of order. The domestic industry declares a "price list" and thereafter sells the material on the basis of declared price list. Barring exceptional circumstances, all sales made by the company are as per the price list with little or no discretion to the operating level of marketing executives to modify the prices.

- The domestic industry's price list must be used for comparison of imported product price with the domestic industry price. In a situation where the company sells material to different customers at different prices, negotiating prices each time, which vary from customer to customer, it might be relevant and appropriate to determine weighted average selling price for the quantities sold over the relevant period. However, in a situation where the company sells its product at pre-determined, declared public price lists and where such price lists are declared after considering international prices, the price comparison between the imported and domestic product must be carried out on the basis of such price lists. Domestic industry reiterates that the selling prices do not vary with customers and therefore there is no necessity of determining weighted average selling price of the quantities sold in a particular period.
- The price is fixed in a scientific and transparent manner. The basis of fixation of price is the prevailing international price. Considering prevailing international prices and various factors, which must be accounted for the differences which exists in different countries (such as exchange rate, customs duties etc), the company decides its basic price.
- The company has termed certain category of sales as "deemed exports". They have no disagreement with the opposing interested parties that deemed exports should not form part of domestic sales. However, merely because the company has designated certain sales as deemed exports, these would not become deemed exports.
- Deemed exports have been defined under the Foreign Trade Policy. Essential ingredients of deemed export sales are the following:

"Following categories of supply of goods by main / sub-contractors are regarded as "Deemed Exports" under FTP, provided goods are manufactured in India:

- (a) Supply of goods against Advance Authorization / Advance Authorization for annual requirement / DFIA;
- (b) Supply of goods to EOUs or STPs or EHTPs or BTPs;
- (c) Supply of capital goods to holders of Authorizations under EPCG Scheme;
- (d) Supply of goods to projects financed by multilateral or bilateral agencies / Funds as notified by Department of Economic Affairs (DEA), MOF under International Competitive Bidding (ICB) in

- accordance with procedures of those agencies / Funds, where legal agreements provide for tender evaluation without including customs duty;
- (e) Supply and installation of goods and equipment (single responsibility of turnkey contracts) to projects financed by multilateral or bilateral agencies / Funds as notified by DEA, MoF under ICB, in accordance with procedures of those agencies / Funds, which bids may have been invited and evaluated on the basis of Delivered Duty Paid (DDP) prices for goods manufactured abroad;
 - (f) Supply of capital goods, including in unassembled/ disassembled condition, as well as plants, machinery, accessories, tools, dies and such goods which are used for installation purposes till stage of commercial production, and spares to extent of 10% of FOR value to fertilizer plants;
 - (g) Supply of goods to any project or purpose in respect of which the MoF, by a notification, permits import of such goods at zero customs duty;
 - (h) Supply of goods to power projects and refineries not covered in (f) above;
 - (i) Supply of marine freight containers by 100% EOU (Domestic freight containers-manufacturers) provided said containers are exported out of India within 6 months or such further period as permitted by customs;
 - (j) Supply to projects funded by UN agencies; and
 - (k) Supply of goods to nuclear power projects through competitive bidding as opposed to ICB."
- Since the Govt. of India considers deemed export sales as export sales and further since the injury assessment must be made for domestic sales, the opposing interested parties have rightly claimed that deemed export sales should not be included in the domestic sales.
 - The domestic sales made by the domestic industry do not qualify as deemed export sales, even though it is using the terminology deemed exports in the market place. In fact, the consumer claims export benefits on the exports they make and the domestic industry uses the nomenclature "deemed export" simply for the reason that the fibre has been consumed in a product, which has been exported. However, all export benefits have been taken by the consumers and not by the domestic industry. If these were deemed exports sales, the domestic industry would have been entitled for various benefits granted under Foreign Trade Policy.
 - It is therefore submitted that these sales are not deemed export sales as understood by opposing interested parties but domestic sales only. Therefore, the sales have been rightly included under the head "domestic sales".

G.3. Examination by the Authority

43. The Authority has taken note of submissions made by various interested parties; including the domestic industry's contention that since no benefit has been obtained by them under the foreign trade policy for the so-called "deemed exports", such sales should be treated as domestic sales. These were cross checked during the spot verification and seen that these sales were in fact domestic sales.

43.1 The Authority has taken on board various submissions made by the interested parties and have undertaken the injury analysis as under:

43.2 Annexure II of AD Rules provides for objective examination of both, (a) the volume of dumped imports and the effect of the dumped imports on prices, in domestic market, for the like article; and (b) the consequent impact on domestic producers of such products. While examining the volume effect of the dumped imports, the Authority is required to examine whether there has been a significant increase in dumped imports either in absolute term or relative to production or consumption in India. With regard to price effect of dumped imports, the Authority is required to examine whether there has been significant price undercutting by the dumped imports as compared to price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress the prices to a significant degree, or prevent price increase, which would have otherwise occurred to a significant degree.

43.3 As regards the impact of dumped imports on the domestic industry, para (iv) of Annexure-II of the AD Rules states as follows:

"The examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry concerned, shall include an evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including natural and potential decline in sales, profits, output market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments."

43.4 The Authority has examined the injury parameters objectively taking into account the facts and submissions of the interested parties.

Cumulative assessment

44. Since there are more than one country involved in the present investigation, the Authority has examined whether the conditions for cumulative assessment are satisfied. The Authority observes that:

- i. The margins of dumping from each of the subject countries are more than the *de-minimis* limits prescribed;

- ii. The volume of imports from each of the subject countries is more than the *de-minimis* limits prescribed;
- iii. Cumulative assessment of the effects of imports is appropriate since the exports from the subject countries directly compete with the like article offered by the domestic industry in the Indian market. This is, *inter alia*, evident from the fact that the domestic product and imported product are like Article; imports from each of the subject countries are significant; goods produced by the Indian Producers and imported from the subject countries are in direct competition; common parties are resorting to use of imported material and domestic material; Indian users/customers are using domestic material and imported material interchangeably; the exporters from the subject countries and the domestic industry have sold the subject goods in the same periods to the same set of customers,

- 44.1 In view of the above, the Authority considers it would be appropriate to assess injury to the domestic industry cumulatively from the dumped imports of the subject goods from the subject countries.

Demand and market share:-

45. Demand of the product in the Country has been assessed as the sum of the domestic sales of the domestic producers and imports from all sources.

In MT

	2005-06	2006-07	2007-08	April-June 08	July-Dec 08 (POI)	April-June 08 Annualized	POI Annualized
Sales of Domestic Industry	223,147	226,178	237,395	49,784	100,925	199,136	201,850
Indexed	100	101	106	89	90	89	90
Imports in India	198	6,774	6,842	1,890	6,329	7,561	12,658
Indexed	100	3,415	3,450	3,812	6,382	3,812	6,382
Demand	223,345	232,952	244,237	51,674	107,254	206,697	214,508
Indexed	100	104	109	93	96	93	96
Market Share in Demand							
Subject Countries	0.06%	1.34%	2.78%	3.66%	5.90%	3.66%	5.90%
Other Countries	0.03%	1.57%	0.03%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Domestic Industry	99.91%	97.09%	97.20%	96.34%	94.10%	96.34%	94.10%

- 45.1 It is noted that the demand for the product under consideration was increasing till 2007-08. The same has however declined (on proportionate basis) during April-June 08 period and the period of investigation. It is also noted that whereas demand for the product under consideration has shown decline during the POI; import volumes have increased significantly (on proportionate basis). It has been contended by opposing interested parties that there is a decline in demand of product in India and therefore,

injury to the domestic industry, if any, is not from the alleged imports. The Authority, however, notes that impact of decline in demand should have resulted into decline in imports as well on proportionate basis. However, it is seen that the imports of the subject goods at dumped prices from the subject countries have apparently led to a situation where the demand for the product under consideration has declined and that of imports have increased significantly.

- 45.2 This effect of the increase in imports is visible in the market share of imports as well. The market share of dumped imports from subject countries is significantly higher during the POI.

Import volumes and market share

46. The imports of the subject goods and the market share are given in the following table:

In MT

	2005-06	2006-07	2007-08	April-June 08	July-Dec 08 (POI)	April-June 08 Annualized	POI Annualized
Imports from the Subject Countries	125	3,121	6,779	1,890	6,329	7,561	12,658
Imports from Other Countries	73	3,653	62	-	-	-	-
Total Imports	198	6,774	6,841	1,890	6,329	7,561	12,658
Dumped Imports in relation to -							
- Indian Production	0.05%	1.26%	2.44%	3.27%	10.05%	3.27%	10.05%
- Indian Consumption	0.06%	1.34%	2.78%	3.66%	5.90%	3.66%	5.90%
Market Share of Domestic Industry	99.91%	97.09%	97.20%	96.34%	94.10%	96.34%	94.10%

- 46.1 It is seen that:

- The imports have shown a significant increase in absolute terms.
- The imports have increased in relation to production and consumption in India.
- While the market shares of the subject countries have increased but that of the domestic industry has declined. It is thus evident that the impact of the imports on the domestic industry has been adverse.

With regard to the argument that the decline in market share is insignificant, particularly in view of macro-economic problems, the Authority holds that there is no legal prescription with regard to the extent to which indices would show deterioration to

conclude that the domestic industry has or has not suffered injury. As per the legal provisions, while there is no *de-minimis* criterion on the basis of market share in demand either in the AD Rules or the WTO's AD Agreement, some authorities do consider 1% market share of imports as significant. If 1% of market share of import from a particular country in consumption can be considered as "significant", the decline in market share by 2.3% cannot be considered as insignificant.

With regard to macro-economic problems (the interested parties are apparently referring to the global meltdown), however, the Authority notes that existence of such factors do not justify dumping and stop redressal of consequent injury to the domestic industry. In a situation where domestic demand for the product has fallen, increase in imports only aggravates the injury.

Price effect of imports

47. It is seen from the following table that there is marginal negative price-undercutting.

Rs/Kg.	China PR	Indonesia
CIF Import Price	94.13	95.39
Landed Price	99.03	100.35
Net Selling price of Domestic Industry	***	***
Price Undercutting	***	***
Price Undercutting % range	-1% to 1%	-2% to 2%

However, the Domestic industry has claimed that it fixes the prices of the subject goods in tandem with the landed value of the product under consideration and this comparison should be made after including the turnover discount in the net selling price that it gives to its customers which is evidently contingent upon the turnover achieved; and if this turnover discount is included in the average selling prices, the price undercutting would be significantly positive.

- 47.1 The Authority notes that the price effect of the dumped imports has been adverse as regards the domestic industry. The Authority has further made comparison of the cost of production and the selling price of the domestic industry along with the landed price of imports, which is given in the following table:

Rs /Kg.	2005-06	2006-07	2007-08	April-June 08	July-Dec 08 (POI)
Cost of Production	***	***	***	***	***
Indexed	100	106	117	150	146
Selling Price	***	***	***	***	***
Indexed	100	116	141	149	135
Landed Price China PR	138.02	86.59	112.66	110.79	99.03

Indexed	100	63	82	80	72
Landed Price Indonesia	77.28	87.58	99.47	107.78	100.35
Indexed	100	113	129	139	130
Average Landed Price from the subject countries	77.77	87.40	102.80	108.07	100.14
Indexed	100.00	112.39	132.19	138.97	128.77

- 47.2 It is seen that while selling price of the domestic industry increased from 100 in base year to 135 during the POI. However, its cost of production increased from 100 in the base year to 146 during the POI. Apparently, the domestic industry could not increase its selling price in line with the increase in its cost of production; thereby indicating that the dumped imports are significantly suppressing the prices of the domestic industry.
- 47.3 The Authority has also examined price underselling of the domestic industry and notes that the landed value from subject countries is significantly below the non-injurious price of domestic industry as may be seen from the following table.

In Rs./Kg.	NIP (Grey fibre)	Landed price	Price Underselling	Price Underselling % range
China PR	***	99.03	***	5 to 15
Indonesia	***	100.35	***	5 to 15
Subject Countries	***	100.14	***	5 to 15

- 47.4 Apparently the domestic industry is forced to sell the subject goods below the non-injurious price due to the presence of dumped imports. Interested parties have, inter alia, argued that price undercutting in the instant case is negative, and therefore, injury to the domestic industry has not occurred due to dumped imports. The Authority, therefore, examined the legal and factual position in detail. It is noted that the domestic industry fixes its prices periodically based on prevailing international prices. In fact, this fact itself establishes that the increase in the selling prices was incommensurate with the increase in cost of production because of presence of the dumped imports from the subject countries.
- 47.5 The Authority also observes that the purpose of determining price undercutting is to assess whether such dumped imports are causing injury to the domestic industry. If the import price decline, the domestic industry may also be forced to reduce its selling prices. If the import price increases, but not to the full extent of increase in the cost of production, the domestic industry may be prevented from increasing its prices commensurate with the increase in the cost of production. Under the AD Rules, the Authority is required to determine whether imports are undercutting the domestic prices or whether the effect of imports was to otherwise depress or suppress the prices of domestic industry in the market. Thus, the rules clearly provide for establishing either price undercutting, price suppression or price depression.

- 47.6 It is relevant to note in this regard that the Authority determined price undercutting by considering net sales realization at ex-factory level and after deducting discounts & commissions, freight & transportation cost etc. While the domestic industry has contended that it is not appropriate to deduct post invoice discount. In any case, absence of positive undercutting does not mean lack of injury.

Economic parameters of the domestic industry

48. Annexure II to the AD Rules requires that a determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of these imports on domestic producers of such products. With regard to consequent impact of these imports on domestic producers of such products, the AD Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. The various injury parameters relating to the domestic industry are discussed below:

Sales volumes

49. The sales volumes of domestic industry are given in the following table:

In MT	2005-06	2006-07	2007-08	April-June 08	July-Dec 08 (POI)	April-June 08 - Annualized	POI - Annualized
Sales volume	223,147	226,178	237,395	49,784	100,925	199,136	201,850
Trend indexed	100	101	106	89	90	89	90

- 49.1 It is noted that sales of domestic industry had increased up to 2007-08 and then declined during April-June 08 period and the POI. Though, there has been a decline in demand and sales could have declined on this account but it is also noted that with the decline in demand, the imports have not declined proportionately, but have actually increased.

With regard to the argument that sales volumes have declined due to consumers restricting purchases and sharp fall in exports of textile products, the Authority notes that situation where (a) consumers are restricting purchases from domestic source, but increasing purchases through imports; and (b) domestic prices decline due to import prices in fact establishes that injury to the domestic industry is due to dumped imports.

Production, Capacity and Capacity Utilization

50. Information relating to production, capacity and capacity utilization is given in the following table:

In MT	2005-06	2006-07	2007-08	April-June 08	July-Dec 08 (POI)	April-June 08 Annualized	POI Annualized
Capacity	253,450	266,450	266,450	82,355	166,520	329,420	333,040
Indexed	100	105	105	130	131	130	131
Production	228,981	246,832	277,818	57,829	114,314	231,317	228,628
Indexed	100	108	121	101	100	101	100
Capacity Utilization	90.35%	92.64%	104.27%	70.22%	68.65%	70.22%	68.65%
Indexed	100	103	115	311	152	78	76

- 50.1 It is seen that production and capacity utilization of the domestic industry was improving till 2007-08, which declined during the April-June 08 period and the POI. It has been alleged by some interested parties that domestic industry had increased its capacity in March 2008 and a new capacity cannot perform at same level of old capacity. The Authority has examined performance of domestic industry on same capacity level, which was there before expansion and notes that even with the same capacity levels, the capacity utilization has declined from 104.27 % in 2007-08 to 85.8% in the POI.

Profit/Loss, return on investment and cash profits

51. Information relating to profit/loss, return on investment and cash profits is given in the following table:

	2005-06	2006-07	2007-08	April-June 08	July-Dec 08 (POI)	April-June 08 Annualized	POI Annualized
PBT Rs. Lacs	***	***	***	***	***	***	***
Indexed	100	168	271	127	73	127	73
PBT Rs. KG	***	***	***	***	***	***	***
Indexed	100	166	254	142	81	142	81
PBIT Rs. Lacs	***	***	***	***	***	***	***
Indexed	100	163	257	138	96	138	96
PBIT Rs. Kg	***	***	***	***	***	***	***
Indexed	100	161	242	155	107	155	107
Cash Profit Rs. Lacs	***	***	***	***	***	***	***
Indexed	100	163	255	131	84	131	84

Cash Profit Rs. Kg	***	***	***	***	***	***	***
Indexed	100	161	240	147	93	147	93
ROI - GFA Basis	***	***	***	***	***	***	***
Indexed	100	149	185	100	62	100	62
ROI - NFA Basis	***	***	***	***	***	***	***
Indexed	100	149	171	87	57	87	57

- 51.1 The Authority notes that the profitability was improving till 2007-08, which declined thereafter significantly. The return on investment and the cash profits have followed the same trend as that of profitability. It is noted that though during the POI, the average return on investment was positive, however, it declined significantly over the injury period. The Authority further examined profits and ROI situation of the domestic industry on quarterly basis within the POI. It is further noted that performance of the domestic industry declined significantly in the 2nd quarter of POI, as may be seen from the following table:

	Jul-Sept 08	Oct-Dec 08	July-Dec 08 (POI)
ROI - GFA Basis	***	***	***
Indexed	85.09	39.01	62.37
ROI - NFA Basis	***	***	***
Indexed	75.35	35.06	56.51

- 51.2 Some interested parties have argued that published statements of the domestic industry show significantly robust financial performances, as reflected in high ROCE. It is noted in this regard that the return on capital employed was 43%, 17% and 23% respectively for the period 2005-06, period of investigation and 2008-09. The Authority has, however, noted that this ROCE has been determined (a) without adjusting for unallocable corporate overhead expenses, (b) is in respect of Fibre & Pulp segment. The profitability of the product under consideration and ROCE relevant to the Authority is, however, a sub-set of Fibre & Pulp segment of the domestic industry. VSF segment of the domestic industry includes not only the subject goods but also pulp, utilities, engineering division, consumer product division etc. It is also relevant to point out that in any case, the published financial statement also shown a significant reduction in ROCE from 43% in 2005-06 to 17% in the period of investigation.
- 51.3 Some interested parties have contended that profitability of the domestic industry might have suffered due to high cost on account of interest and depreciation. On the other hand, the domestic industry has contended that its interests & depreciation cost is low in view of the fact that a significant portion of the capacities were created/installed long way back

and these plants are now fully depreciated but fully operational. The domestic industry has in fact, claimed that it is entitled to a higher prices on these accounts. The Authority has, however, taken a consistent position that actual cost of production of the domestic industry shall be considered to assess its profitability rather than any notional determination.

Inventories:

52. Inventory levels of the domestic industry have been as under:

In MT	2005-06	2006-07	2007-08	April-June 08	July-Dec 08 (POI)
Inventory	***	***	***	***	***
Inventory – equal to no. of days sales	***	***	***	***	***

- 52.1 It is noted that inventory of the domestic industry declined in 2006-07, which again increased in 2007-08. The inventory further increased during April-June 08 period and the POI as compared to the 2007-08 period.

Employment, wages and productivity

53. Information relating to employment, wages and productivity of the domestic industry has been as under:

	2005-06	2006-07	2007-08	April-June 08	July-Dec 08 (POI)	July-Dec 08 (POI Annualized)
Employment	***	***	***	***	***	***
Indexed	100	97	96	95	95	95
Wages Rs. Lacs	***	***	***	***	***	***
Indexed	100	117	125	137	123	123
Productivity per day	***	***	***	***	***	***
Indexed	100	108	121	101	100	100
Productivity per Employee	***	***	***	***	***	***
Indexed	100	111	126	107	105	105

- 53.1 It is noted that employment level of the domestic industry declined over the injury period. The Authority, however, notes that this decline is not only seen in the POI, but was there even before the POI. The wages of the domestic industry shows normal increase. As regards productivity per employee, it increased till 2007-08 and showed a decline during April-June 08 period and the POI.

Dumping Margin:

54. It is observed that dumping margin in respect of the exports from the subject countries is positive and more than the *de-minimis* limits prescribed.

Growth

55. The Authority notes that the growth of the domestic industry is negative in terms of volume parameters such as sales (declined by 9.54% from the base year and 16% from 2007-08), production (0.15% from the base year and 21.48% from 2007-08) and capacity utilization (declined by about 24% from the base year and 39.42 % from 2007-08). The growth in price parameters is also seen as negative. Profits before tax (declined by 26.69 % from the base year and 197 % from 2007-08) of the domestic industry and the ROI (declined by 43.49 % from the base year and 114.13 % from 2007-08) too deteriorated significantly during the POI.

Threat of material injury

56. The Authority has taken note of the submissions made by the domestic industry regarding availability of surplus capacities of the subject goods in the subject countries. From the information available on record, it is seen that there is a significant increase in the capacities in the subject countries, whereas the capacity utilization has gone down significantly, indicating the surplus capacities of the subject goods in the subject countries. The Authority notes that the rate of increase of dumped imports over the injury period has been significant, indicating the likelihood of substantially increased importation. The data of the co-operating exporters from Indonesia shows significant increase in their inventory levels. There is a significant price underselling and significant price suppression indicating the threat of material injury to the domestic industry. This view is further buttressed if the landed value of the subject goods from the subject countries during the quarter immediately following the POI is seen. It is noted that the landed value has further fallen by 7.81 % as may be seen from the following table in case of imports from Indonesia. As regards imports from China PR during the period, it is seen that the landed value has fallen by 18.03 %. Cumulatively, the landed value of the subject goods from the subject countries has fallen by 7.97% during the period.

Rs./Kg.	Jul-Dec08 (POI)	Jan-Mar09 (Post POI quarter)
Landed Value –China PR	99.03	81.17
Landed Value -Indonesia	100.35	92.51
Average Landed Value from the subject countries	100.02	92.05

H. Causal Link**57. Views of the Domestic Industry**

- The Authority has already examined all other known factors. Regarding injury due to decline in demand, the same has been examined by the Authority in the preliminary finding. As regards global downturn, it has not been demonstrated that profitability

should indeed decline, because of global downturn. As regards increase in input cost, the same is specially covered under the Rules.

- As regards weakening of INR, the same should have been benefitted the domestic industry rather than going against the domestic industry. While the applicant depends upon the imported wood pulp only and would have got adversely impacted on this account only because of this, landed price of imported pulp have substantially increased.
- As regards capacity expansion, the same are results of earlier decisions. In any case, the domestic industry cannot be expected to terminate its expansion plans only because of dumping.

58. Views of other interested parties

- The Authority should have examined other factors, which might have caused injury to the domestic industry.
- In its annual report, the domestic industry have stated that deterioration in production and sales and profits is due to (1) lower demand, (2) global turndown, (3) steep rise in input cost and weakening of INR. Thus injury due to alleged dumping is a false allegations and conjunctures.
- The price reductions have nothing to do with the alleged dumping. (reference has been made to the Annual report of 2007-08 in this regard)
- Lower profitability is due to increase in input costs, lower volumes and weak margins. Interest and depreciation cost appears to be very high. (reference has been made to the Annual report of 2007-08, corporate presentation, Q2FY09 presentation, Q3FY09 presentation).
- Despite restrained outlook, the domestic industry expended its capacity.
- Decline in sales is due to (1) consumer resisting purchases, (2) decline in textile exports led to decline in demand, (3) Global slowdown with inflationary pressure, (4) liquidation of inventory in value chain.
- Capacity expended, hence no injury on account of ability of increase capacity/expansion. (reference has been made to the Annual report of 2007-08).
- As per Q3 report, the production was curtailed due to lower demand. Different statements have been made by the domestic industry before different forums.
- In Dept 09-H1 performance, the production increased by 15% inspite of NAGDA plant was shut for 48 days due to water shortage, 19% growth in sales, new divisional revenue increased by 17% and PBIDT increased by 35%.
- The domestic industry is planning to invest in a project of 80000 MT in Vilayat in Gujarat.

Examination by the Authority

59. The Authority has examined whether other parameters could have contributed to the injury caused to the domestic industry. Following parameters were analyzed in this regard:

- a) Imports from Third Countries: - The Authority has collected the transaction-wise imports data of the subject goods from DGCI&S. From the information available on record, the Authority notes that there are no imports of the subject goods from any other country during the POI.
- b) Contraction in Demand:- The Authority notes that the demand for the subject goods has shown significant improvement till 2007-08, and then shows decline during the POI. However, as compared to the demand, the imports have increased significantly, which ordinarily should have declined with the decline in demand. It is noted that within the available demand, the domestic industry has lost its market share. Apparently, the domestic industry was already facing the problem of declining demand, but the same was compounded by the dumped imports.
- c) Pattern of consumption:- No significant change in the pattern of consumption has been noticed. Apparently, the product supplied by the domestic industry is directly competing with that of imported material from the subject countries.
- d) Conditions of competition:- As per facts available on record, there is no evidence that conditions of competition or trade restrictive practices have caused injury to the domestic industry.
- e) Developments in technology:- As per facts available on record, there appears to be no change in technology over the injury period which could have caused injury to the domestic industry.
- f) Export performance of the domestic industry: - The performance of the domestic industry has been segregated for domestic sales and exports sales; and only domestic performance of the domestic industry has been considered while assessing the injury to the domestic industry.

60. The Authority notes that the performance of the domestic industry over the injury period has deteriorated due to dumped imports from the subject countries. This is established by the following:

- i. The imports from the subject countries have significantly increased over the injury period. It is noted that while the market share of the domestic industry has declined, that of the imports from the subject countries have increased.
- ii. There is price suppression as the domestic industry has not been able to increase its prices in proportion to the increase in the cost of production. The significant price-suppression caused by the dumped imports has adversely impacted the domestic industry, resulting in significant decline in profits and cash flow.
- iii. A comparison of the landed value of the subject goods with the NIP of the domestic industry shows that there is a case of price underselling as well.

60.1 Some interested parties have contended that production, sales and profitability had deteriorated due to lower demand, prevailing global down trend, steep rise in input costs and weakening of Indian Rupee; the Authority notes that these public statements in the

Annual Report does not alter the conclusion that dumping of the product has contributed to injury to the domestic industry. Firstly, it has been wrongly assumed by the interested parties that dumping of the product should be the sole cause of injury to the domestic industry. Though production and sale undisputedly suffered due to decline in demand but dumping of the subject goods also caused material injury to the domestic industry. With regard to profitability, as the domestic industry fixes its prices on the basis of import prices; therefore, availability of dumped imports at lower prices in the market apparently have forced the domestic industry to offer such prices that did not permit recovery of increase in the input costs.

- 60.2 As regards the issue relating to steep increase in input costs, the Authority notes that if the domestic industry is not able to increase its prices in tandem with the increase in costs of production, then it would be a clear case of price suppression, which is an important injury indicator. As regards weakening of Indian Rupee, the Authority notes that the same should have reduced injury from imports, as the weakening of Indian Rupee should have had an impact of making imports less attractive.

Magnitude of Injury and Injury margin:-

61. In response to the Disclosure statement, the Domestic industry has disputed the determination of the Non-injurious price of the product concerned. The issues raised have been examined and duly dealt with while rectifying the Non-injurious price. The Non-injurious price of the subject goods produced by the domestic industry so determined by the Authority has been compared with the landed value of the exports from the subject countries for determination of the injury margins during the POI. Thus compared, the injury margins are worked out as under:

In Rs/Kg.	Indonesia			China PR
	PT Indo Bharat Rayon	PT South Pacific Viscose	Others	
NIP	***	***	***	***
Landed Value	***	***	***	***
Injury Margin	***	***	***	***
Injury margin%	***	***	***	***
Injury margin Range (%)	5-15	5-15	25-35	5-15

I. Conclusions:

62. After examining the submissions made by the interested parties and issues raised therein; and considering the facts available on record, the Authority concludes that:
- (a) The product under consideration has been exported to India from the subject countries below their associated normal values.

- (b) The domestic industry has suffered material injury in respect of the product under consideration. Besides, there is a case of threat of material injury as well.
- (c) The material injury and threat thereof has been caused by the dumped imports of the subject goods from the subject countries.

J. Indian industry's interest & other issues

- 63. The Authority notes that the purpose of anti-dumping duties, in general, is to eliminate 'injury' caused to the Domestic Industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the Country. Imposition of anti-dumping measures would not restrict imports from the subject countries in any way, and therefore, would not affect the availability of the products to the consumers.
- 64. It is recognized that the imposition of anti-dumping duties might affect the price levels of the products manufactured using the subject goods and consequently might have some influence on relative competitiveness of these products. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the antidumping measures, particularly if the levy of the anti-dumping duty is restricted to an amount necessary to redress the injury to the domestic industry. On the contrary, imposition of anti-dumping measures would remove the unfair advantages gained by dumping practices, would prevent the decline of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of the subject goods. With a view to minimize the impact on the downstream industry, the Authority has considered it appropriate to recommend anti-dumping duty based on the lower of the dumping and injury margins. The Authority notes that the imposition of anti dumping measures would not restrict imports from the subject countries in any way, and therefore, would not affect the availability of the product to the consumers.

K. Recommendations

- 65. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the exporters, importers and other interested parties to provide positive information on the aspects of dumping, injury and causal link. Having initiated and conducted the investigation into dumping, injury and the causal link thereof in terms of the Act and the AD Rules and having established definitively positive dumping margins concerning imports of the subject goods originating in or exported from the subject countries and as well as material injury and threat thereof to the domestic industry caused by such dumped imports; the Authority is of the view that imposition of definitive duty is required to offset the dumping and 'injury' in the instant matter. Therefore, the Authority considers it necessary to recommend imposition of definitive anti-dumping duties concerning imports of the subject goods from the subject countries in the form and manner described hereunder.
- 66. Having regard to the lesser duty rule followed by the Authority, the Authority recommends imposition of definitive anti-dumping duty equal to the lesser of margin of

dumping and margin of injury, so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, the antidumping duty equal to the amount indicated in Col 8 of the table below is recommended to be imposed concerning all imports of the subject goods originating in or exported from the subject countries.

Sl. No	Heading / Subheading	Description of goods	Country of Origin	Country of Exports	Producer	Exporter	Duty Amount	Unit	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
1	5504.10.00	'Viscose Staple Fibre (VSF) excluding Bamboo fibre'	Indonesia	Indonesia	M/s P T South Pacific Viscose	M/s P T South Pacific Viscose	0.103	Kg	US \$
2	5504.10.00	'Viscose Staple Fibre (VSF) excluding Bamboo fibre'	Indonesia	Indonesia	PT. Indo Bharat Rayon	PT. Indo Bharat Rayon	0.164	Kg	US \$
3	5504.10.00	'Viscose Staple Fibre (VSF) excluding Bamboo fibre'	Indonesia	Indonesia	Any combination other than as specified at Sr. No.1 & 2		0.512	Kg	US \$
4.	5504.10.00	'Viscose Staple Fibre (VSF) excluding Bamboo fibre'	Indonesia	Any country other than Indonesia	Any	Any	0.512	Kg	US \$
5.	5504.10.00	'Viscose Staple Fibre (VSF) excluding Bamboo fibre'	Any country other than attracting Anti-dumping duty	Indonesia	Any	Any	0.512	Kg	US \$
6.	5504.10.00	'Viscose Staple Fibre (VSF) excluding	China PR	China PR	Any	Any	0.194	Kg	US \$

		Bamboo fibre'							
7.	5504.10.00	'Viscose Staple Fibre (VSF) excluding Bamboo fibre'	China PR	Any country other than China PR	Any	Any	0.194	Kg	US \$
8..	5504.10.00	'Viscose Staple Fibre (VSF) excluding Bamboo fibre'	Any country other than attracting Anti-dumping duty	China PR	Any	Any	0.194	Kg	US \$

67. Landed value of imports for the purpose shall be the assessable value as determined by the Customs under the Customs Act, 1962 and all duties of customs except duties under Sections 3, 3A, 8B, 8C, 9 and 9A of the Customs Tariff Act, 1975.
68. An appeal against this order shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act.

P. K. CHAUDHERY, Designated Authority